हर खबर पर पैनी नजर

नई सोच एक्सप्रेस

(बिहार और झारखंड से प्रकाशित हिन्दी दैनिक)

आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभात..

www.naisochlive.com | पटना, बुधवार, 26 अगस्त 2026, वर्ष- 09, अंक- 182, पृष्ठ-12, मूल्य - 3:00 | naisochexpress@gmail.com

यूपीआई के एक दशक पूरे

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अनुभव साझा करने का किया आग्रह

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले एकीकृत भुगतान अंतरफलक (यूपीआई) के एक दशक पूरे होने पर इसकी परिवर्तनकारी यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि यूपीआई ने देश में तेज, सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक डिजिटल लेन-देन को नई गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपने यूपीआई उपयोग के अनुभव साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से यह भी बताने को कहा कि यूपीआई ने उनके दैनिक जीवन को किस प्रकार सरल, सुविधाजनक और सहज बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दशक पहले शुरू हुआ एकीकृत भुगतान अंतरफलक भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुआ है। इसने डिजिटल लेन-देन को सरल, तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हुए देश में भुगतान के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव किया है। पिछले दस वर्षों में यूपीआई की पहुंच देश के कोने-कोने तक हुई है। इसके चलते डिजिटल भुगतान आम नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। छोटे दुकानदारों से लेकर उपभोक्ताओं और कारोबारियों तक, बड़ी संख्या में लोग रोजमर्रा के लेन-देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की व्यापक पहुंच और इसके लगातार विस्तार को भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की इस उल्लेखनीय और गौरवपूर्ण यात्रा पर हर भारतीय गर्व कर सकता है। उन्होंने कहा कि यूपीआई ने भुगतान की प्रक्रिया को न केवल आसान बनाया है, बल्कि डिजिटल लेन-देन को अधिक सहज और सुविधाजनक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने सामाजिक माध्यम 'एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से नागरिकों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आग्रह किया।

उन्होंने लोगों से यह बताने को कहा कि यूपीआई ने उनके जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया और रोजमर्रा के भुगतान को उनके लिए कितना आसान बनाया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि एक दशक पहले शुरू हुआ यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि इसने देश में डिजिटल लेन-देन को सरल, तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाकर भुगतान के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव ला दिया है।

पीएम मोदी की नई बीजेपी टीम को नसीहत जीत पर मत इतराओ, जनता से जुड़े रहो

- नितिन नवीन के नेतृत्व वाली नई राष्ट्रीय टीम से पहली मुलाकात
- जमीनी स्तर पर जनता और कार्यकर्ताओं से जुड़े रहने पर जोर

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन को मजबूत करने और जनता से लगातार जुड़े रहने पर विशेष जोर दिया। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने नई टीम को चुनावी सफलताओं से संतुष्ट होकर नहीं बैठने की नसीहत दी और कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को जमीनी स्तर पर लोगों की नब्ज समझते हुए लगातार सक्रिय रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व वाली नई राष्ट्रीय टीम के सदस्यों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 65 नए पदाधिकारियों में शामिल सदस्यों से उनके राजनीतिक और संगठनात्मक सफर को लेकर भी चर्चा की। बैठक में पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारी और विभिन्न राज्यों की इकाइयों के प्रमुख भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने पदाधिकारियों से कहा कि संगठन की मजबूती का आधार जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद है। उन्होंने विशेष रूप से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और आम लोगों की समस्याओं व अपेक्षाओं को समझने पर जोर दिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी नई टीम के सदस्यों से बातचीत करते हुए जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संबंध मजबूत करने की अपील की। खासतौर पर उन राज्यों में संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया, जहां बीजेपी सत्ता में है। नितिन नवीन के नेतृत्व वाली बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा 17 अगस्त को की गई थी।

डीआरडीओ की मिसाइल टेक्नोलॉजी भारतीय रक्षा उद्योगों को होगी ट्रांसफर, सरकार की मंजूरी

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से भारतीय कंपनियों को एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम बनाने में बढ़ावा मिलेगा

एजेंसी। नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को स्वदेश में ही उत्पादन के लिए हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ाने की दिशा में इस फैसले से भारतीय कंपनियों को रेगुलेटरी नियमों का पालन करने वाले एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम बनाने में बढ़ावा मिलेगा। घरेलू क्षमताओं को मजबूत करके सरकार न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि देश के डिफेंस सेक्टर को भी बेहतर बना रही है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले से मिसाइल प्रणाली के विकास को औद्योगिक उत्पादन में सफलतापूर्वक परिवर्तित करना संभव होगा। इससे उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और विनिर्माण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग जगत की क्षमताओं का लाभ उठाया जा सकेगा। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि करना, रक्षा क्षेत्र के औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करना और आपूर्ति श्रृंखला में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों की भागीदारी के अवसर उत्पन्न करना है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता में वृद्धि करना, आयात पर निर्भरता घटाना तथा गुणवत्ता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए घरेलू स्तर पर सुधार या बदलाव को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के विकास में सहयोग करना है। डीआरडीओ उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढालने और रक्षा प्रणाली में शामिल करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रौद्योगिकी का यह हस्तांतरण घरेलू उद्योगों को निर्धारित योग्यताओं, प्रमाणन और विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार स्वदेशी उत्पादन में सक्षम बनाकर रक्षा क्षेत्र के अनुकूल परिवेश में उनकी अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस कदम का मकसद रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में भारतीय उद्योग की भूमिका को बढ़ाना और देश के अंदर औद्योगिक पैमाने पर मिसाइल उत्पादन को तेजी से बदलना है। इस पहल के तहत घरेलू कंपनियां डीआरडीओ के मानकों पर मिसाइल सिस्टम बना पाएंगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रौद्योगिकी स्थानांतरण से देश में ज्यादा विनिर्माण क्षमता बनाने और घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और दूसरे प्रौद्योगिकी भागीदारों के लिए मिसाइल सिस्टम सप्लाई चेन में हिस्सा लेने के ज्यादा मौके बनने की भी उम्मीद है। यह पहल रक्षा में आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के बड़े प्रयास का हिस्सा है। डीआरडीओ के बनाए मिसाइल सिस्टम का घरेलू उत्पादन शुरू करके इस कदम का मकसद आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू वैल्यू एडिशन का हिस्सा बढ़ाना और भारत की स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत करना है।

संक्षिप्त समाचार

सुप्रीम कोर्ट के समाधान में 1712 मामलों का हुआ समाधान

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय का समाधान कार्यक्रम, जो एक विशेष लोक अदालत और मध्यस्थता पहल है, बेहद सफल रहा है। 21 से 23 अगस्त तक चले इस तीन दिवसीय आयोजन में कुल 1,712 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। पक्षकारों की आपसी सहमति और समझौते के परिणामस्वरूप समाप्त हुए इन मामलों में 240.94 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जो इस कार्यक्रम की व्यापक सफलता को दर्शाती है। इस समाधान कार्यक्रम की शुरुआत इसी साल 21 अप्रैल को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे विवादों को न्यायालय की लंबी और जटिल प्रक्रिया के बजाय मध्यस्थता और आपसी सहमति से सुलझाना था। इस विशेष लोक अदालत में मामलों को लाने से पहले, पक्षकारों और उनके वकीलों के साथ गहन बातचीत के माध्यम से समझौते की कोशिशें की गई थीं, ताकि त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में कुल 3,285 मामले सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से पहले दिन 402, दूसरे दिन 350, और तीसरे दिन 912 मामलों का समाधान किया गया। इस प्रकार, लोक अदालत के माध्यम से कुल 1,664 मामले सुलझे, जबकि 48 मामलों का निपटारा मध्यस्थता के जरिए हुआ, जिससे कुल 1,712 विवादों का समाधान संभव हो सका। लोक अदालत की पीठों की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों ने की।

ऊना में श्रद्धालुओं से भरा ट्रक खाई में गिरा, 40 से अधिक घायल; तीन पीजीआई चंडीगढ़ रेफर

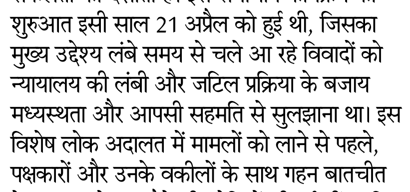

ऊना। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह के समीप मंगलवार सुबह श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक में सवार 40 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक में करीब 50 श्रद्धालु सवार थे। सभी श्रद्धालु हरियाणा के करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, श्रद्धालु दो दिन पहले पीर निगाह मंदिर में दर्शन करने और भंडारा आयोजित करने के लिए पहुंचे थे। मंगलवार सुबह वे पीर निगाह से माता नैना देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए थे। मंदिर से करीब दो किलोमीटर दूर पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक के खाई में गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और खाई में गिरे श्रद्धालुओं को बाहर निकालने का काम शुरू किया। हादसे की सूचना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को दी गई, जिसके बाद राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गए। घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उनका उपचार शुरू किया।

स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति वाली याचिका खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से यह साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक या कानूनी सामग्री पेश नहीं की गई कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। मामला प्रयागराज के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से जुड़ा है। छात्रा ने हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के बाद उसी स्कूल में कक्षा 11 में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। उसने अपनी मां के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्कूल प्रबंधन को निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति देने का निर्देश जारी करने की मांग की थी। याचिका में छात्रा की ओर से तर्क दिया गया था कि हिजाब पहनना इस्लामी रीति-रिवाजों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भी दावा किया गया कि वह कक्षा 6 से ही स्कूल में हिजाब पहनती आ रही है। हालांकि, अदालत ने इस दावे और प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के बाद याचिका को स्वीकार नहीं किया। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने छात्रा से संबंधित विभिन्न कक्षाओं की तस्वीरों का अवलोकन किया। कोर्ट ने पाया कि स्कूल में याचिकाकर्ता के अलावा कोई अन्य छात्रा हिजाब नहीं पहनती है, जिसमें उसी धार्मिक समुदाय से जुड़ी छात्राएं भी शामिल हैं।

नौसेना दूसरे स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल 'निपुण' को कमीशन करने के लिए तैयार

एजेंसी। नई दिल्ली

गहरे समुद्र में गोताखोरी और पानी के नीचे सहायता क्षमताओं में अहम बढ़ोतरी होगी

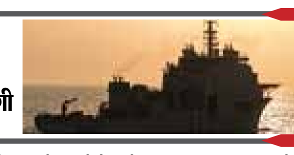

भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल (डीएसवी) निपुण को अपने समुद्री बेड़े में शामिल करेगी। इसके शामिल होने से नौसेना की गहरे समुद्र में गोताखोरी और पानी के नीचे सहायता क्षमताओं में अहम बढ़ोतरी होगी। यह जहाज निर्माण से लेकर ऑपरेशनल सर्विस तक के सफर में नए अध्याय की शुरुआत होगी। विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में डिजाइन और निर्मित 'निपुण' डिफेंस शिपबिल्डिंग में भारत की आत्मनिर्भरता की कोशिश में मील का पत्थर है। आउटफिटिंग और ट्रायल के एक बड़े प्रोग्राम के पूरा होने के बाद यह वेसल 30 जुलाई, 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। यह खासतौर पर बनाया गया प्लेटफॉर्म है, जिसे डाइविंग और पानी के अंदर के कई तरह के ऑपरेशन में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जहाज आधुनिक डाइविंग सिस्टम और पानी के अंदर दखल देने की क्षमताओं से लैस है, जिससे समुद्र में मुश्किल हालात में काम करने वाले गोताखोरों को लगातार मदद मिलेगी। यह सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने की नौसेना की क्षमता को भी बढ़ाएगा। जहाज में नेविगेशन, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट और सटीक स्टेशन कीपिंग के लिए मॉडर्न सिस्टम हैं। साथ ही डाइविंग, पानी के अंदर दखल और मेडिकल सपोर्ट के लिए खास सुविधाएं भी हैं। ये क्षमताएं निपुण को सतह के नीचे मुश्किल ऑपरेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करने में मदद करती हैं। 'निपुण' की कमीशनिंग से नौसेना की भारत के समुद्री इलाकों में खास डाइविंग और पानी के अंदर मिशन करने की क्षमता और मजबूत होगी। इस देश में बने प्लेटफॉर्म का शामिल होना देश के शिपबिल्डिंग इकोसिस्टम की बढ़ती क्षमता को भी दिखाता है, ताकि नौसेना की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांस और खास जहाज बनाए जा सकें। नौसेना के कैप्टन विवेक मधवाल ने बताया कि जहाज पर लगा क्रेस्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल के तौर पर जहाज की मुख्य भूमिका और गहरे समुद्र में डाइविंग से जुड़ी हिम्मत, धीरज और प्रोफेशनल काबिलियत को दिखाता है।

डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में दो आरोपित गिरफ्तार, 5 दिनों की हिरासत

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोवा के चर्चित डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि साइबर ठगी से हासिल रकम को पहले बैंक खातों के जरिए नकदी में बदला जाता था और इसके बाद अधिकृत मनी चेंजर कंपनियों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जाता था। इस नेटवर्क से जुड़े साइबर खातों के तार 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दर्ज 163 एफआईआर और 330 पीड़ित शिकायतों से जुड़े पाए गए हैं। ईडी के पणजी जोनल कार्यालय ने फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सैयद को 23 अगस्त को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया। दोनों को 24 अगस्त को गोवा की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 29 अगस्त तक पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच उत्तरी गोवा साइबर क्राइम पुलिस थाने में दर्ज उस एफआईआर के आधार पर शुरू हुई, जिसमें गोवा की एक महिला को कथित तौर पर 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर ठगी का शिकार बनाया गया था। उसे यह विश्वास दिलाया गया कि वह किसी जांच के घेरे में है।

सरायकेला में दिसंबर में होगी इंटरनेशनल ग्रैंडमास्टर शतरंज चैंपियनशिप

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में सरायकेला-खरसावां जिला शतरंज संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को जिले में दिसंबर 2026 में प्रस्तावित चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी–इंटरनेशनल ग्रैंडमास्टर शतरंज चैंपियनशिप के आयोजन की जानकारी दी। भारतीय शतरंज संघ (AICF) और झारखंड शतरंज संघ (SKDCA) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता स्मृति शेष पद्मश्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती को समर्पित होगी। प्रतिनिधिमंडल में SKDCA के अध्यक्ष मनोज कुमार, उपाध्यक्ष लक्ष्मण टुडू, शैलेंद्र कुमार एवं अभिषेक दास शामिल थे।

दिल्ली, असम समेत देश के अधिकांश क्षेत्रों में अगले चार-पांच दिनों तक बारिश की संभावना

एजेंसी। नई दिल्ली

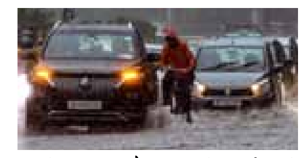

दिल्ली-एनसीआर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश समेत दश के अधिकांश क्षेत्रों में अगले चार-पांच दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने का भी पूर्वानुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 27-29 अगस्त के दौरान, असम एवं मेघालय में 26-27 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 25-27 अगस्त के दौरान, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 25-29 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 29-30 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। कोंकण और गोवा में 25-31 अगस्त के दौरान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 25 अगस्त को काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 26-31 अगस्त के दौरान; गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र एवं कच्छ में 25-31 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा में 25 अगस्त को कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में 25-26 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और तेलंगाना में 25-31 अगस्त के दौरान, केरल, माहे और लक्षद्वीप में 29-31 अगस्त के दौरान, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 26-31 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 25 से 26 अगस्त के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 25 से 29 अगस्त के दौरान, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

चीनी की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने बदले नियम

एजेंसी। नई दिल्ली

जमाखोरी पर अंकुश लगाने दो महीने के अंदर रिफाइनिंग और बिक्री की अनिवार्य

त्योहारी सीजन से पहले ही चीनी की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है और कच्ची चीनी के आयात से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने कच्ची चीनी के आयात नियमों में संशोधन किया, इसके तहत चीनी की जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने दो महीने के अंदर रिफाइनिंग और बिक्री अनिवार्य की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमतों में उछाल के बीच सरकार ने आयात की शर्तों में संशोधन किया और टैरिफ रेट्स कोटा के तहत देश में लाई गई कच्ची चीनी को दो महीने के अंदर सफेद/रिफाइंड चीनी में परिवर्तित करके घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले के नियमों को देखें, तो आयातित कच्ची चीनी को उचित समय सीमा के अंदर और पर्याप्त समय पूर्व संसाधित करना जरूरी था, जिससे इसे 31 अक्टूबर, 2026 तक घरेलू बाजार में बेचा जा सके। अब संशोधित नियमों के तहत प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए दो महीने की डेडलाइन तय की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी आयात से जुड़े नियमों में बदलाव की अधिसूचना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसका उद्देश्य आयातित कच्ची चीनी के भंडारण यानी जमाखोरी को रोकना है। इसके साथ ही यह तय करना है कि आयात से उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द राहत मिल सके। सरकार के इस कदम से चीनी की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल की उम्मीद बढ़ी है। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन चीनी के आयात की अनुमति दे दी है और कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम निर्माताओं और इससे जुड़े व्यापारियों और थोक उपभोक्ताओं पर स्टॉक लिमिट सेट कर दिया है। देश के तमाम राज्यों की ओर से केंद्र से चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन लेने का आग्रह किया गया था।

सरकार जातिगत जनगणना को ठंडे बस्ते में डाल रही : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से जातिगत जनगणना कराई जा रही है, वह केवल व्हाइट वॉश है और कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी। जयराम रमेश ने जातिगत जनगणना की मौजूदा प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि बिहार और तेलंगाना में अपनाए गए सर्वेक्षण मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। जयराम रमेश ने आज यहां कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि 20 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जातिगत जनगणना के संबंध में 21 पन्नों का संयुक्त पत्र लिखा है। यह कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को लिखा गया तीसरा पत्र है। इससे पहले 16 अप्रैल 2023 और 5 मई 2025 को भी खरगे ने पत्र लिखे थे लेकिन अब तक किसी का जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार मांग कर रही है कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से चर्चा की जाए और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर जनगणना कराई जाए।

'सप्तधारा' विकसित भारत का रोडमैप, सात क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है देश: संबित पात्रा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कभी यूपीआई का मजाक उड़ाया था लेकिन आज उसके आंकड़े पूरी दुनिया के सामने हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शायद इन उपलब्धियों को समझ नहीं पाएंगे। संबित पात्रा ने कहा, "आज यूपीआई ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 साल पहले जब यूपीआई की परिकल्पना रखी थी, तब कांग्रेस नेताओं ने उसका उपहास उड़ाया था लेकिन आज वही प्रणाली डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी सफलता बन गई है। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश के सामने 'सप्तधारा' का विजन रखा था। यह विकसित भारत के निर्माण का रोडमैप है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल व सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री बी पी मंडल की जयंती पर किया नमन

पटना। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्व बीपी मंडल की जयंती के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में देशरत्न मार्ग एवं सर्कुलर पथ, पटना के चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया तथा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, कई मंत्री तथा अन्य गणमान्य लोगों ने भी स्व. बीपी मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती-पूजन किया गया तथा भजन एवं गीत प्रस्तुत किये गये।

निशांत कुमार बिहार में स्वास्थ्य क्रांति के अग्रदूत : नवल शर्मा

पटना। निशांत कुमार केवल एक स्वास्थ्य मंत्री नहीं, बल्कि सही मायने में बिहार में स्वास्थ्य क्रांति के अग्रदूत बनकर उभरे हैं। एक ऐसी क्रांति जहाँ व्यवस्था, संवेदनशीलता और जवाबदेही एक साथ आगे बढ़ रही है। पिछले कुछ महीनों में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक नई दिशा पकड़ी है, और इस परिवर्तन के केंद्र में निशांत कुमार का निर्णायक नेतृत्व है। सरकारी अस्पतालों में जवाबदेही, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, ब्लड एवं डिजिटल मॉनिटरिंग से पारदर्शिता और स्वास्थ्य प्रशासन को परिणामोन्मुख बनाना ये कुछ ऐसे कदम हैं जो आनेवाले समय में बिहार के पूरे स्वास्थ्य महकमे की तस्वीर बदल देंगे। गंभीर रोगियों के उपचार हेतु आर्थिक सहायता की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करना गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है। वहीं, टीबी उन्मूलन अभियान में रिकॉर्ड स्तर पर मरीजों की पहचान कर यह सिद्ध किया गया है कि बिहार सरकार केवल इलाज उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि समय रहते जीवन बचाने की प्रभावी व्यवस्था भी विकसित कर रही है।

किलकारी,बाढ़,रघुनाथ बालिका,रविन्द्र बालिका विद्यालय सेमीफाइनल में

पटना। किलकारी बिहार बाल भवन,पटना के तत्वावधान में बिहार बॉल बैडमिंटन संघ के तकनीकी सहयोग से किलकारी बिहार बाल भवन के बॉल बैडमिंटन कोर्ट पर खेली जा रही 17वीं ध्यानचंद स्मृति बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में मेजबान किलकारी, बाढ़,रघुनाथ बालिका विद्यालय कंकड़बाग, रविन्द्र बालिका विद्यालय राजेन्द्र नगर की टीमें सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित किया है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज खेले गये बालिका वर्ग के महत्वपूर्ण लीग मैच में मेजबान किलकारी ने एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी को 35-10,35-12 से,बाढ़ ने बापू स्मारक बालिका विद्यालय को 35-16,35-20 से,बाढ़ ने रविन्द्र बालिका विद्यालय को 35-26,35-25 से,किलकारी ने रघुनाथ बालिका विद्यालय को 35-25,35-15 से,रविन्द्र बालिका विद्यालय ने बापू स्मारक बालिका विद्यालय को 35-20,35-25 से,रघुनाथ बालिका विद्यालय ने एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी को 35-10,35-12 से हराया। किलकारी की ओर से नयना कुमारी, प्रीती कुमारी, खुशी कुमारी, बाढ़ की ओर से स्नेहा कुमारी, तनवी कुमारी, रघुनाथ बालिका विद्यालय की ओर से दिव्या कुमारी, राजनंदनी, रविन्द्र बालिका विद्यालय की ओर से पूनम कुमारी, देवांशी कुमारी, समीक्षा कुमारी ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। किलकारी के प्रशिक्षक राहुल कुमार के अनुसार बालिका वर्ग का पहला सेमीफाइनल मुकाबला मेजबान किलकारी व रविन्द्र बालिका विद्यालय के बीच खेला जाएगा जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बाढ़ व रघुनाथ बालिका विद्यालय के बीच खेला जायेगा।

विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु विद्यार्थी सहयोग शिविर आयोजित

पटना। विद्यार्थियों की शिकायतों एवं समस्याओं के प्रभावी एवं त्वरित समाधान के उद्देश्य से आज टी.पी.एस. कॉलेज, पटना के दिनकर सभागार में विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया तथा अपनी विभिन्न समस्याओं एवं सुझावों को महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखा।कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ. तपन कुमार शांडिल्य ने विद्यार्थी सहयोग शिविर की विशेषताओं एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से विद्यार्थियों से जुड़ी बिजली की समुचित व्यवस्था, परीक्षा परिणाम समय पर जारी होने, प्रयोगशालाओं की उचित व्यवस्था तथा कक्षाओं के सुचारु रूप से संचालन सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण एवं आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना महाविद्यालय की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. हंस कुमार सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यार्थी सहयोग शिविर विद्यार्थियों और महाविद्यालय प्रशासन के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं को सीधे समझकर उनके समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। शिविर में छात्र-छात्राओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं एवं सुझावों को रखा। महाविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रभावी समाधान के साथ-साथ महाविद्यालय में बेहतर, व्यवस्थित एवं छात्रहितैषी शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना रहा।

अतिथि शिक्षकों के सेवा समायोजन की दिशा में बड़ी पहल, मुख्यमंत्री के आश्वासन से खुशी की लहर

पटना। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों (सहायक प्राध्यापकों) के सेवा समायोजन को लेकर बड़ी पहल सामने आई है। 22 दिनों से धरना स्थल पर आमरण अनशन कर रहे अतिथि शिक्षकों के मामले में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के स्तर पर सकारात्मक पहल के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर है।दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के विधायक एवं जदयू जिलाध्यक्ष राजेश मंडल उर्फ ईश्वर मंडल ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अतिथि शिक्षकों को 65 वर्ष तक सेवा सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक आश्वासन दिया है। विधायक ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लगातार मुलाकात कर अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग रखी थी।विधायक ईश्वर मंडल ने कहा कि वर्ष 2019 में नियुक्त अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अध्यापन कार्य के अतिरिक्त अन्य रोजगार नहीं करना का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश का पालन करते हुए शिक्षक वर्षों से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।उन्होंने कहा कि राज्य में सहायक प्राध्यापकों की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ऐसे में यदि उससे पहले अतिथि शिक्षकों के सेवा समायोजन पर निर्णय नहीं लिया गया, तो हजारों शिक्षकों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे शिक्षकों की है, जो वर्तमान में निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं और नई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह सकते हैं।श्री मंडल ने बताया कि बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति की ओर से भी अतिथि शिक्षकों के सेवा समायोजन की अनुशंसा की जा चुकी है। उन्होंने सरकार और राजभवन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए समिति की अनुशंसा के आलोक में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया।

'विद्यार्थी सहयोग शिविर' से समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

नई सोच एक्सप्रेस

» हर माह के चौथे मंगलवार को बिहार के शिक्षण संस्थानों में आयोजित होगा 'विद्यार्थी सहयोग शिविर'

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बिदुपुर में 'सात निश्चय-3' के अंतर्गत 'सबका सम्मान, जीवन आसान' अभियान के तहत 'विद्यार्थी सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य बिहार के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों का प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के प्रशासनिक-सह-शैक्षणिक भवन के फैकल्टी रूम में स्थापित सूचना-सहायता काउंटर का अवलोकन किया और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं जानकारियों के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझावों को सुना। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की जो भी समस्याएं हैं, उनका निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली में इंटरनेट कनेक्टिविटी और निर्बाध बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों के पठन-पाठन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जब तक सभी विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की स्थायी व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक अस्थायी तौर पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिहार एक अनोखा राज्य है, जहां मात्र 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, ताकि उन्हें पढ़ाई में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। विद्यार्थियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस के आसपास प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए इस प्रकार स्थल का चयन किया जाए, जिससे विद्यार्थियों के साथ-साथ बाहरी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान एवं अंबेडकर छात्रावासों में जन औषधि केंद्र खोले जा सकें, यह सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। 'विद्यार्थी सहयोग शिविर के माध्यम से छात्र-छात्राओं को अपनी समस्याएं सीधे संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े और उनकी समस्याओं का निर्धारित समय-सीमा में समाधान हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आने वाली शिकायतों का समय-सीमा के अंतर्गत अधिकतम 30 दिनों के भीतर अंतिम निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी निगरानी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में 'विद्यार्थी सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में शैक्षणिक व्यवस्था, परीक्षा, छात्रावास, पेयजल, शौचालय, कैंटीन सहित विद्यार्थियों से जुड़ी अन्य समस्याओं एवं सुविधाओं के संबंध में शिकायतों और सुझावों की सुनवाई की जाएगी। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत एवं सुझाव दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी ऑनलाइन अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।

राष्ट्रीय सूचना एवं जनसंपर्क सचिव सम्मेलन में बिहार की भागीदारी

नई सोच एक्सप्रेस

» सूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाने और केंद्र-राज्य समन्वय बढ़ाने पर हुआ मंथन

पटना। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव नवीन कुमार ने मंगलवार को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सूचना एवं जनसंपर्क सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री चंचल कुमार सहित केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सूचना एवं जनसंचार व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने, बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप नई व्यवस्थाओं को अपनाने तथा परस्पर समन्वय को सुदृढ़ करना रहा। सम्मेलन के दौरान सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र से जुड़े विभिन्न नीतिगत एवं व्यावहारिक विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) और राज्यों,केंद्रशासित प्रदेशों के सूचना एवं जनसंपर्क विभागों के बीच साझेदारी को मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई। इसके साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) की प्रशिक्षण सुविधाओं के उपयोग पर भी विचार किया गया। सम्मेलन में WAVES 2027 की रूपरेखा, WAVES Bazaar के माध्यम से बाजार तक पहुंच को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण अवसंरचना के विस्तार तथा राज्य-विशिष्ट कार्यक्रमों और जनसंपर्क को प्रभावी बनाने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। फिल्म शूटिंग एवं लाइव इवेंट की अनुमति के लिए India Cine Hub के सिंगल विंडो पोर्टल को अपनाने तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त Press and Registration of Periodicals (PRP) Act, 2023 के अंतर्गत Press Sewa Portal के माध्यम से डिजिटल व्यवस्था की ओर संक्रमण, ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में कम लागत वाले सिनेमा को प्रोत्साहन, सिनेमा हॉल में सुगम्यता मानकों के क्रियान्वयन तथा WaveX State Ecosystem को प्रभावी बनाने जैसे विषय भी सम्मेलन के एजेंडे में शामिल रहे। बिहार की ओर से सम्मेलन में भागीदारी राज्य की सूचना एवं जनसंपर्क व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो रही नई तकनीकों, डिजिटल माध्यमों और संस्थागत व्यवस्थाओं से और अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण रही। सम्मेलन ने केंद्र और राज्यों के बीच अनुभवों एवं कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान के साथ बेहतर समन्वय और क्षमता निर्माण के लिए साझा मंच प्रदान किया।

PMFME योजना में सर्वाधिक स्वीकृतियों के लिए बिहार को मिला 'बेस्ट स्टेट' का सम्मान

नई सोच एक्सप्रेस

» सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने में बिहार की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सम्मान

पटना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार सूक्ष्म, लघु एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। इसी क्रम में, नई दिल्ली में आयोजित पीएमएफएमई कॉन्क्लेव में बिहार को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के तहत सर्वाधिक संख्या में स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के लिए 'बेस्ट स्टेट' के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान बिहार में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने, उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा छोटे उद्यमियों को संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य के उल्लेखनीय प्रदर्शन को मान्यता प्रदान करता है। प्रतिष्ठित सम्मान माननीय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान द्वारा श्री अमन समीर, निदेशक, एमएसएमई एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग विभाग, बिहार सरकार को प्रदान किया गया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने कहा, "PMFME योजना का उद्देश्य देशभर के छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए उन्हें आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। बिहार द्वारा सर्वाधिक स्वीकृतियाँ प्राप्त कर 'बेस्ट स्टेट' का सम्मान हासिल करना राज्य में उद्यमिता और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं को दर्शाता है। यह उपलब्धि बिहार के उद्यमियों के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी।" माननीय उद्योग मंत्री, बिहार सरकार, सुश्री श्रेयसी सिंह ने बिहार की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "PMFME योजना के तहत बिहार को मिला 'बेस्ट स्टेट' का सम्मान राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम कर रहे उद्यमियों की क्षमता और मेहनत का प्रमाण है। सरकार का निरंतर प्रयास है कि छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। यह सम्मान बिहार में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमिता को और गति देने के लिए प्रेरित करेगा।" प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) का उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण और उन्नयन को बढ़ावा देना है। योजना के माध्यम से उद्यमियों को तकनीकी उन्नयन, आधारभूत संरचना, ब्रांडिंग, क्षमता निर्माण तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। बिहार को मिला यह 'बेस्ट स्टेट' सम्मान राज्य में सूक्ष्म उद्यमिता, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उपलब्धि राज्य के छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमियों को आगे बढ़ने और नए उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

बिहार की एक करोड़ महिलाओं को अगले तीन वर्षों में सीधे रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य : मुख्यमंत्री

नई सोच एक्सप्रेस

» प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सभी वर्ग की छात्राओं को 30 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में रक्षाबंधन के पूर्व आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को रोजगार और स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए तीन दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में बिहार की एक करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 25, 26 और 27 अगस्त तक चलनेवाले इस विशेष अभियान में स्वास्थ्य विभाग, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की समृद्धि का रास्ता महिलाओं के सशक्तीकरण से होकर जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले एक करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जाए। जीविका से जुड़ी करीब 1.81 करोड़ महिलाओं और 13 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एनीमिया मुक्त बिहार अभियान भी शुरू किया गया है। अभियान के तहत बिहार में बच्चों, महिलाओं और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं की एनीमिया की जांच की जाएगी तथा जरूरत के अनुसार उनका उपचार और दवा उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी संख्या में महिलाएं एनीमिया से प्रभावित हैं और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया जच्चा-बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। मुख्यमंत्री ने 'अनीमिया मुक्त बिहार' विशेष अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 25 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान के माध्यम से राज्य में एनीमिया की रोकथाम, जांच, उपचार एवं जागरूकता को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। अभियान के तहत लगभग 1 करोड़ 20 लाख 82 हजार 500 लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी उन्मूलन अभियान के तहत भी बड़ी संख्या में लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। अब स्वास्थ्य सेवाओं को जिला स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। जिलों में 36 तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लोगों को हर छोटी-बड़ी स्वास्थ्य सुविधा के लिए पटना आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सभी वर्ग की छात्राओं को 30 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं को पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। आज राज्य में करीब 59-60 प्रतिशत महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर आ रही हैं। यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में बिहार की बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मिथिला हस्तकला को-ऑपरेटिव सोसाइटी की घोषणा एवं नवनियुक्त अध्यक्ष / सदस्यों को प्रमाण-पत्र वितरित किया। पद्मश्री दुलारी देवी (अध्यक्ष), पद्मश्री शांति देवी (सह अध्यक्ष) और पद्मश्री शिवम पासवान (सह अध्यक्ष) को पंजीकरण प्रमाण पत्र सौंपा गया। श्रीमती रानी झा सदस्य बनाई गईं। रक्षाबंधन के अवसर पर जीविका दीदी, सुधा सखी और दुग्ध उत्पादक महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

पौधा संरक्षण उपादान वितरण योजना से किसानों को मिलेगा लाभ, फसलों की सुरक्षा के साथ बढ़ेगी उत्पादकता

नई सोच एक्सप्रेस

» 75 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप एवं फ्रूट फ्लाई ट्रैप

पटना। माननीय कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि किसानों को फसलों को हानिकारक कीटों से बचाने तथा रासायनिक कीटनाशकों के अनियंत्रित उपयोग को कम करने के उद्देश्य से पौधा संरक्षण उपादान वितरण योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत किसानों को आधुनिक, प्रभावी एवं पर्यावरण अनुकूल कीट प्रबंधन तकनीकें अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। माननीय कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में क्लस्टर आधारित व्यवस्था के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप एवं फ्रूट फ्लाई ट्रैप उपलब्ध कराए जाएंगे। इनका उपयोग बैंगन, धान, मक्का, टमाटर, विभिन्न सब्जियों तथा अमरूद सहित अन्य फसलों में हानिकारक कीटों के प्रभावी प्रबंधन के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न फसलों के लिए फेरोमोन ट्रैप पर अनुदान चना फली छेदक, बैंगन तना एवं फल छेदक तथा धान तना छेदक के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप पर 96 रुपये प्रति सेट अथवा अधिकतम 480 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा। मक्का में फॉल आर्मीवर्म के नियंत्रण के लिए 162 रुपये प्रति सेट अथवा अधिकतम 810 रुपये प्रति एकड़ तथा सब्जी फसलों में डायमंड बैक मॉथ के नियंत्रण के लिए 171 रुपये प्रति सेट अथवा अधिकतम 855 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान का प्रावधान किया गया है। **रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता होगी कम:** माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि पौधा संरक्षण उपादान वितरण योजना समेकित कीट प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप एवं फ्रूट फ्लाई ट्रैप के उपयोग से कीटों का प्रभावी नियंत्रण करते हुए रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग में कमी लाई जा सकेगी। इससे किसानों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि फसल की सुरक्षा, उत्पादन लागत में कमी और उत्पादकता में वृद्धि सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। आधुनिक पौधा संरक्षण तकनीकों को खेतों तक पहुंचाकर किसानों को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि की ओर प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का लक्ष्य है कि इन आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल पौधा संरक्षण तकनीकों का अधिकाधिक किसानों तक विस्तार कर सुरक्षित खेती, स्वस्थ फसल और बेहतर कृषि आय की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए।

पूर्व मुख्यमंत्री स्व0 बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के जन्म दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई

नई सोच एक्सप्रेस

पटना। पूर्व मुख्यमंत्री स्व॰ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पटना के देशरत्न मार्ग एवं सर्कुलर पथ चौराहा स्थित आदमकद प्रतिमा के समीप जन्म दिवस के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सहकारिता मंत्री श्री राम कृपाल यादव, विधायक श्री श्याम रजक, विधान पार्षद श्री संजय कुमार सिंह उर्फ गांधीजी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, पूर्व मुख्यमंत्री स्व॰ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जी के पौत्र डॉ॰ मनीष मंडल एवं उनके परिजन सहित अनेक सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व मुख्यमंत्री स्व॰ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती-पूजन, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र गान, बिहार गीत एवं देश भक्ति गीतों का गायन भी किया गया।

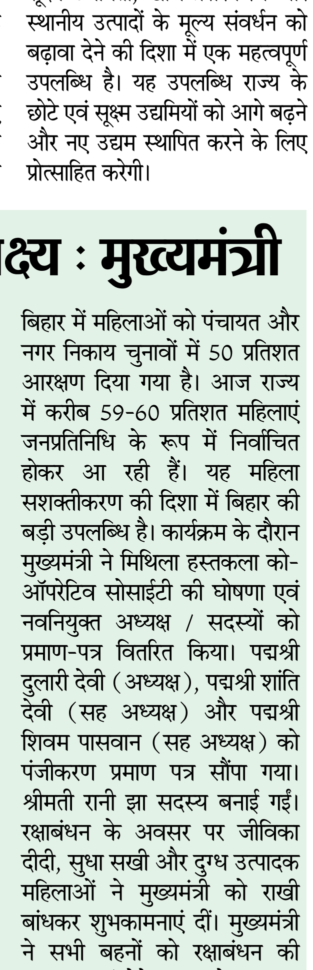

हर खबर पर पैनी नजर
नई सोच एक्सप्रेस
(बिहार और झारखंड से प्रकाशित हिन्दी दैनिक)

संक्षिप्त समाचार

सैमसंग टीवी प्लस इंडिया ने 200 चैनलों तक किया विस्तार

पटना। सैमसंग टीवी प्लस इंडिया ने अपनी सामग्री पेशकश को 200 स्ट्रीमिंग टीवी चैनलों तक विस्तारित किया है, जिससे भारत में लाखों दर्शकों को मनोरंजन के अधिक विकल्प मिलेंगे। इस विस्तार के तहत सैमसंग टीवी प्लस ने एनएच स्टूडियोज़ के साथ साझेदारी कर दो नए चैनल - आशीर्वाद टीवी और थलाइवर हिट्स लॉन्च किए हैं। ये चैनल देशभर के दर्शकों तक कालजयी पौराणिक कहानियाँ और प्रतिष्ठित भारतीय सिनेमा पहुँचाएंगे। कुणाल मेहता, जनरल मैनेजर, हेड ऑफ बिज़नेस डेवलपमेंट, सैमसंग टीवी प्लस इंडिया ने कहा कि भारत के कनेक्टेड टीवी इकोसिस्टम में बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करते हुए सैमसंग टीवी प्लस इंडिया को बीसीएस रत्न अवॉर्ड्स में सीटीवी प्लेटफ़ॉर्म ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाज़ा गया है। वर्षों के दौरान सैमसंग टीवी प्लस ने अपने सामग्री इकोसिस्टम का लगातार विस्तार किया है। भारत में 50 से अधिक चैनलों से बढ़कर आज 200 चैनलों तक पहुँच गया है। यह उपलब्धि दर्शकों के लिए विभिन्न श्रेणियों में विविध मनोरंजन विकल्प उपलब्ध कराने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने की एडीभी 160 और रेबेल 300 की कीमतों की घोषणा

पटना। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने नई होंडा एडीभी 160 और रेबेल 300 की कीमतों की घोषणा की, जो जुलाई 2026 में पेश किए जाने वाले 10-प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का पहला फेज़ है। एचएमएसआई के हाल ही में पेश किए गए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के पहले प्रोडक्ट के तौर पर एडीभी 160 और रेबेल 300 भारत में होंडा की मल्टी-पाथवे प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को दिखाते हैं। होंडा एडीभी 160 की कीमत 170000 (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) रखी गई है और यह होंडा रेडविंग और बिगविंग डीलरशिप पर मिलेगी। जबकि होंडा रेबेल 300 के स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत 222000 (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) और ई -क्लच वेरिएंट की कीमत 262000 (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) रखी गई है। यह खास तौर पर होंडा बिगविंग डीलरशिप पर मिलेगा। एचएमएसआई की मल्टी-पाथवे मोबिलिटी स्ट्रैटेजी के तहत पेश किया गया पहला फ्लेक्स-फ्यूल स्कूटर होने के नाते, एडीभी 160 भारत का पहला स्कूटर है जो ई 85 तक के फ्यूल ब्लेंड के साथ कम्पैटिबल है और इसमें होंडा की प्रूवन फ्लेक्सटेक टेक्नोलॉजी है।

SNAP 2026 के लिए आवेदन शुरू, तीन बार परीक्षा देने का मौका

पटना। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड यूनिवर्सिटी) ने एमबीए प्रवेश के लिए सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट (SNAP) 2026 के आवेदन शुरू कर दिए हैं। आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू हुई है, जबकि 25 नवंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। SNAP 2026 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा तीन चरणों में होगी। पहला टेस्ट 13 दिसंबर, दूसरा 19 दिसंबर और तीसरा 26 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को तीनों परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा और प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर माना जाएगा। परिणाम 12 जनवरी 2027 को जारी किया जाएगा। परीक्षा देश के 79 शहरों में होगी। प्रत्येक प्रयास के लिए आवेदन शुल्क 2,550 रुपये और प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त 1,000 रुपये शुल्क निर्धारित है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 25 प्रतिशत नकारात्मक अंकन होगा। प्रवेश प्रक्रिया में SNAP स्कोर, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरैक्शन के आधार पर कुल 100 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत और एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। SNAP के माध्यम से सिम्बायोसिस के विभिन्न संस्थानों में एमबीए के लिए प्रवेश का अवसर मिलेगा।

बोल्ट ने Ace 5G और Evo के साथ स्मार्टफोन बाजार में की एंट्री

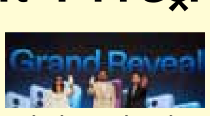

पटना। फायर-बोल्ट के होमग्रोन स्मार्टफोन ब्रांड बोल्ट ने अपने पहले स्मार्टफोन Ace 5G और Evo लॉन्च किए हैं। कंपनी के अनुसार दोनों फोन आधुनिक भारतीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए दमदार परफॉर्मेंस, एआई फीचर्स, बड़ी डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ के साथ पेश किए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन में 6.79 इंच की 120Hz डिस्प्ले, 6000mAh बैटरी और गूगल जेमिनी आधारित एआई फीचर्स दिए गए हैं। इनमें सर्कल टू सर्च, गूगल लेंस और एआई नाइट मोड जैसे फीचर्स मिलेंगे। फोन एंड्रॉइड 16 पर काम करेंगे और 8MP एआई सेल्फी कैमरा से लैस हैं। Ace 5G की शुरुआती कीमत 13,999 रुपये और Evo की 10,999 रुपये रखी गई है। डे-1 ऑफर के तहत इनकी शुरुआती कीमत क्रमशः 12,999 और 9,999 रुपये होगी। दोनों स्मार्टफोन 1 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

टीवीएस आईक्यूब के 10 लाख ग्राहक पूरे, मिलियनआर स्पेशल एडिशन लॉन्च

पटना। टीवीएस मोटर कंपनी ने टीवीएस आईक्यूब के 10 लाख ग्राहकों का आंकड़ा पार करने के अवसर पर आईक्यूब मिलियनआर स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। कंपनी के अनुसार यह उपलब्धि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति ग्राहकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। 3.5 किलोवॉट वेरिएंट पर आधारित इस विशेष संस्करण की आईडीसी रेंज 145 किलोमीटर है। इसमें ऑरोरा ग्रीन ड्यूल-टोन रंग, प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री और मिलियनआर बैजिंग दी गई है। स्कूटर में फ्रंट यूटिलिटी स्टोरेज बढ़ाए जाने से कुल स्टोरेज क्षमता 35.5 लीटर हो गई है। साथ ही 118 से अधिक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी फीचर्स उपलब्ध हैं। टीवीएस आईक्यूब मिलियनआर स्पेशल एडिशन की प्रभावी एक्स-शोरूम कीमत 1,40,138 रुपये (कर्नाटक) रखी गई है। वहीं आईक्यूब रेंज की शुरुआती कीमत 1,11,310 रुपये है। बैटरी-एज-ए-सर्विस की कीमत 59,999 रुपये से शुरू होती है। कंपनी ने कहा कि आईक्यूब ने इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में उसकी स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एयरटेल ने लॉन्च किया भारत का पहला स्वायत्त टेल्को ग्रेड क्लाउड

पटना। एयरटेल ने एक्सटेलिफ़ाय (Xtelify) के माध्यम से एयरटेल क्लाउड लॉन्च कर भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा संप्रभुता के क्षेत्र में नई पहल की है। कंपनी के अनुसार यह भारत का पहला स्वायत्त (सॉवरेन) टेल्को ग्रेड क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय जरूरतों के अनुरूप विकसित किया गया है। एयरटेल क्लाउड में डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंट्रोल प्लेन ऑपरेशन भारत में ही होस्ट और नियंत्रित किए जाते हैं। प्लेटफॉर्म 99.99 प्रतिशत अपटाइम, जियो-रिडंडेंसी, डिजास्टर रिकवरी, इम्यूटेबल बैकअप और लगातार डेटा रेप्लिकेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कंपनी के अनुसार प्लेटफॉर्म प्रति मिनट 1.4 अरब तक ट्रांजैक्शन संभालने की क्षमता के लिए वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया गया है। इसमें आईएएएस, पीएएएस और जनरेटिव एआई आधारित सेवाएं उपलब्ध हैं। इससे सरकारी एवं निजी संस्थानों को मिशन-क्रिटिकल वर्कलोड और संवेदनशील डेटा को सुरक्षित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।

आदित्य बिड़ला कैपिटल ने गोल्ड लोन कारोबार में रखा कदम, पटना में खोली समर्पित शाखा

नई सोच एक्सप्रेस

पटना। आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) के एनबीएफसी कारोबार ने गोल्ड लोन क्षेत्र में प्रवेश करते हुए पटना में अपनी समर्पित शाखा शुरू की है। कंपनी के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से स्वर्ण आधारित ऋण उपलब्ध कराना है। कंपनी ने बिहार को संगठित गोल्ड लोन कारोबार के लिए संभावनाओं वाला बाजार बताया है। बढ़ते वित्तीय समावेशन, संगठित गोल्ड लोन प्रदाताओं की अपेक्षाकृत कम पहुंच और सुरक्षित औपचारिक ऋण की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी राज्य में चरणबद्ध तरीके से विस्तार करेगी। बिहार की राजधानी पटना को इस विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बाजार माना गया है। एबीसीएल की गोल्ड लोन सेवा में शाखा आधारित सेवा के साथ डिजिटल माध्यम से जुड़ने की सुविधा भी होगी। कंपनी के मुताबिक, पारदर्शी मूल्य निर्धारण, गिरवी रखे आभूषणों की सुरक्षित देखरेख और सरल ऋण प्रक्रिया के जरिए शहरी एवं अर्ध-शहरी ग्राहकों की जरूरतें पूरी की जाएंगी। आदित्य बिड़ला कैपिटल के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी-एनबीएफसी राकेश सिंह ने कहा कि गोल्ड लोन कारोबार की शुरुआत कंपनी के ग्राहक-केंद्रित वित्तीय सेवा विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध विस्तार के जरिए मजबूत गवर्नेंस, परिचालन उत्कृष्टता और ओम्नीचैनल अनुभव के साथ विश्वसनीय एवं सुविधाजनक सुरक्षित ऋण समाधान अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। कंपनी के अनुसार, एबीसीएल और उसकी सहायक कंपनियों व संयुक्त उपक्रमों का देशभर में 1,759 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है। 30 जून 2026 तक कंपनी का समेकित ऋण कारोबार 2.19 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। वित्त वर्ष 2026 में एनबीएफसी का एयूएम 27 प्रतिशत बढ़कर 1,59,916 करोड़ रुपये और ऋण वितरण 25 प्रतिशत बढ़कर 84,204 करोड़ रुपये रहा। वहीं वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में एयूएम 28 प्रतिशत बढ़कर 1,67,456 करोड़ रुपये और ऋण वितरण 34 प्रतिशत बढ़कर 21,201 करोड़ रुपये हो गया।

इंटर स्कूल वालीबॉल चैंपियनशिप में ज्ञान निकेतन स्कूल बना विजेता

नई सोच एक्सप्रेस

दानापुर। आदर्श विकास विद्यालय महम्मदपुर ,खगौल में इन्टर स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 अंडर-14 का आयोजन किया गया। जिसमें ज्ञान निकेतन स्कूल पटना ने बाजी मारी वहीं रनरअप आदर्श विकास विद्यालय रहा । इस टूर्नामेंट में संत करेंस सेकेंडरी हाई स्कूल खगौल, पटना सेंट्रल स्कूल ,ज्ञान निकेतन स्कूल पटना, आदर्श विकास विद्यालय खगौल ने भाग लिया। इस वॉलीबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता में पहला मैच आदर्श विकास विद्यालय और संत करेंस सेकेंडरी हाई स्कूल के बीच खेला गया। जिसमें लगातार तीन सेटों में आदर्श विकास विद्यालय ने जीत हासिल किया । दूसरा मैच ज्ञान निकेतन और पटना सेंट्रल स्कूल के बीच खेला गया। जिसमें ज्ञान निकेतन ने जीत हासिल की। फाइनल मुकाबले में ज्ञान निकेतन और आदर्श विकास विद्यालय के बीच खेला गया । जिसमें पहले सेट में 25/18 ज्ञान निकेतन जीत हासिल की वही दूसरा सेट में आदर्श विकास विद्यालय ने 25/ 15 से जीता ,जब कि अंतिम और रोमांचक मुकाबले में ज्ञान निकेतन स्कूल ने 25/18 से जीत हासिल कर इस टूर्नामेंट में विजेता रहे । टूर्नामेंट में बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड आदर्श विकास विद्यालय के छात्र आदित्य राज दिया गया। वही विजेता टीम को वरिष्ठ पत्रकार व यूथ होस्टलस एशोसियेशन ऑफ़ इंडिया बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर मधुकर और वाइस प्राचार्य अंजू प्रसाद ने संयुक्त रूप से खेल का उद्घाटन और खिलाड़ियोंके बीच

» आदर्श विकास विद्यालय बना रनर

पुरस्कारों का वितरण किया है । इस टूर्नामिंटमेंट में आदित्य राज, दिव्यांशु कुमार, रितेश कुमार ,अंकित राज ,आयुष राज ,आरुष कुमार, अर्जुन कुमार, करण कुमार साहिल कुमार , ओमकार , किशु, सिद्धार्थ , आनंद कुमार , सत्यम राज, जिज्ञासु सुमन, कृष्ण सम्राट, विशेष सिंह, अनुभव कुमार ,अभिराज, गुलाम वारिस आदि ने हिस्सा लिया। वहीं इस आयोजन में स्कूल के खेल-कूद के शिक्षक उत्तम कुमार और सभी शिक्षक आदि उपस्थित रहे ।

सचिव द्वारा मेगा परियोजनाओं की समीक्षा, प्रोजेक्ट्स को समयसीमा पर पूर्ण करने के निर्देश

नई सोच एक्सप्रेस

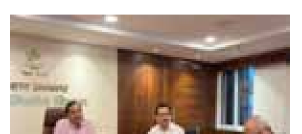

पटना। भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आज विश्वेश्वरैया भवन स्थित कार्यालय कक्ष में संरचना उपभाग के सभी प्रमंडलों (विद्युत सहित) की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेगा परियोजना यथा- बिहार विधान सभा में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण, बिहार लोक भवन परिसर में निर्माणाधीन परियोजना, संयुक्त कार्यालय भवन का निर्माण, जीविका मुख्यालय भवन, एसडीआरएफ, बिहटा के शेष कार्यों एवं बिहार अभियंत्रण विश्विद्यालय सहित अन्य सभी परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्तापूर्ण निर्माण एवं समयबद्धता के साथ क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। उक्त बैठक में विभाग के अपर सचिव, अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहें बिहार लोक भवन, पटना परिसर में निर्माणाधीन राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय एवं अतिथि गृह का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। अतिथि गृह (G+1) का निर्माण अग्रिम चरण में है, जिसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। वहीं, राजेन्द्र भवन (B+G+1) एवं राज्यपाल सचिवालय (B+G+2) का कार्य भी किया जा रहा है। बिहार विधान सभा, पटना परिसर में 1.74 एकड़ के भूखंड पर डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। प्लिंथ से प्रथम तल तक कॉलम की शटरिंग एवं आरसीसी ढलाई तथा ग्राउंड फ्लोर छत का शटरिंग कार्य प्रगति पर है। डिजिटल संग्रहालय का भवन भू-तल समेत एक मंजिला होगा। डिजिटल संग्रहालय में बिहार विधानसभा के गठन से लेकर अब तक के बिहार के सभी माननीय मुख्यमंत्रियों, माननीय विधान सभा अध्यक्ष, विधान परिषद के माननीय सभापति और माननीय विधायकों के बारे में डिजिटल रूप में जानकारी होगी। साथ ही, पिछले 100 वर्षों के विधान मंडल के गौरवशाली इतिहास को भी डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाएगा । पटना में लगभग 5 एकड़ भूखंड पर बिहार अभियंत्रण विश्विद्यालय का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। परिसर में कुछ आवश्यक कार्यों का पूरा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्य भवन जी+4 संरचना में विकसित किया गया है, जिसमें आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर से लेकर चतुर्थ तल तक छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के काम करने में सहजता को प्रमुखता दी गई है। nपटना के पूर्वी गार्डेनर रोड पर निर्माणाधीन संयुक्त कार्यालय भवन का कार्य भी अग्रिम चरण में है। प्लास्टर एवं पुट्टी का कार्य प्रगति पर है। सचिव ने शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया। संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण से कार्यालयी कार्यों में सहुलियत होगी। बैठक में करीब 0.92 एकड़ भूखंड पर बनने वाले जीविका मुख्यालय भवन के निर्माण की समीक्षा की गई। जीविका मुख्यालय भवन G+7 होगा। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बाँका परिसर में अतिरिक्त भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें प्रशासनिक भवन,बालक एवं बालिका छात्रावास, गेस्ट हाउस आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ, बिहटा के बचे हुए शेष कार्यों को भी तेजी से पूर्ण करने का निदेश दिया गया। सचिव ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समयसीमा पर कार्य नहीं होने पर एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करें। सचिव के द्वारा परियोजनाओं के निर्माण में आ रहे अवरोधों को शीघ्र दूर करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को सभी योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। गुणवत्तापूर्ण निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमित रूप से स्थल निरीक्षण का भी निदेश दिया गया। सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समयसीमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं का धरना, छह माह से बकाया मानदेय भुगतान की मांग

नई सोच एक्सप्रेस

पटना। प्रखंड सह अंचल कार्यालय फुलवारीशरीफ परिसर में मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया. इस दौरान सेविका-सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए करीब छह माह से लंबित मानदेय सहित अन्य बकाया राशि का जल्द भुगतान करने की मांग की. धरना का नेतृत्व आंगनबाड़ी संघ की प्रखंड अध्यक्ष वंदना देवी ने किया. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को पिछले करीब छह महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. मानदेय का नियमित भुगतान नहीं होने से सेविका-सहायिकाओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. संघ की प्रमुख मांगों में सेविका-सहायिका की पोशाक राशि, अन्नप्राशन, गोदभराई, प्रोत्साहन राशि, मोबाइल रिचार्ज सहित अन्य बकाया राशि का भुगतान तथा न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रेच्युटी लागू करना शामिल है.प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर संघ आगे भी आंदोलन को तेज करेगा.

रक्षाबंधन पर निगम की 1075 बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा

नई सोच एक्सप्रेस

पटना। रक्षाबंधन पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) ने महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की विशेष व्यवस्था की है। निगम का यह कदम बहनों को बिना किसी आर्थिक बोझ के अपने भाइयों तक पहुंचने और राखी का त्योहार मनाने में मदद करेगा। निगम की करीब 1075 बसों में 27 अगस्त (गुरुवार) को सुबह 6 बजे से 28 अगस्त (शुक्रवार) रात 10 बजे तक महिलाएं बिना टिकट के सफर कर सकेंगी। यह सुविधा राज्यभर में निगम की ओर से संचालित सभी एसी, नॉन-एसी, डीलक्स, पीएम ई-बसों और पीपीपी सहित सभी श्रेणियों की बसों में उपलब्ध रहेगी। इसके संबंध में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो सके। निगम के अनुसार वर्तमान में एक हजार से अधिक बसें संचालित हैं, जिनमें पीपीपी मोड पर चलने वाली बसें भी शामिल हैं। इनसे रोजाना एक लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या करीब आधी रहती है। विदित हो कि महिलाओं की सुरक्षा और आरामदायक सफर को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार इनके लिए खास पिंक बसों का संचालन कर रही है। इस बस सेवा को महिलाओं ने खुले दिल से स्वीकार किया है। परिवहन सचिव राजकुमार ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर निशुल्क यात्रा की यह व्यवस्था हर वर्ष की भांति इस बार भी महिलाओं को दी जा रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को भाइयों को राखी बांधने के लिए बिना किसी आर्थिक बाधा के सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन सुनिश्चित कराना है। साथ ही इस दिन ऑफिस, कोचिंग, बाजार या अन्य कामों के लिए तथा अंतरजिला व अंतरराज्यीय मार्गों पर जाने वाली बसों में भी महिलाएं बिना टिकट के यात्रा कर सकेंगी।

एससी आयोग के अध्यक्ष ने नाबालिग से हुए दुष्कर्म के स्थल का निरीक्षण

नई सोच एक्सप्रेस

पटना। अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, मृणाल पासवान के निदेर्शानुसार आज सारण (छपरा) जिले के तरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरलीपुर गाँव पहुँचकर दलित नाबालिग बच्ची से संबंधित दुष्कर्म के मामले में स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी प्राप्त की गई तथा संबंधित पदाधिकारियों से मामले की वर्तमान स्थिति एवं अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली गई। स्थल निरीक्षण के दौरान सीमांत मृणाल उर्फ प्रिंस पासवान भी साथ मौजूद रहे।अध्यक्ष के निदेर्शानुसार मामले में आवश्यक एवं उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा एवं न्याय सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास जारी है।

मेमोरी चिप की बढ़ती कीमत से महंगे हो सकते हैं सैमसंग के नए फोल्डेबल फोन

नई सोच एक्सप्रेस

पटना। मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों का असर अब प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार पर भी पड़ सकता है। देश के प्रमुख रिटेलर्स के मुताबिक सैमसंग के नए फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी जेड फोल्ड8 अल्ट्रा, गैलेक्सी जेड फोल्ड8 और गैलेक्सी जेड फ्लिप8 की कीमतों में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। इन डिवाइस की मौजूदा कीमतें करीब 1.25 लाख से 2.60 लाख रुपये के बीच हैं। सैमसंग के इन नए फोल्डेबल फोन को कंपनी ने बेहतर डिजाइन, डिस्प्ले, हिंज, मजबूती, परफॉर्मेंस और विशेष रूप से विकसित गैलेक्सी एआई फीचर्स के साथ पेश किया है। गैलेक्सी जेड फोल्ड8 अल्ट्रा खुलने पर महज 4.1 मिमी मोटा है, जबकि गैलेक्सी जेड फोल्ड8 का वजन करीब 201 ग्राम है। सैमसंग इंडिया के अनुसार, इन तीनों फोल्डेबल स्मार्टफोन को भारत में रिकॉर्ड प्री-ऑर्डर मिले हैं। लॉन्च के शुरुआती 72 घंटों में करीब 2.71 लाख प्री-ऑर्डर दर्ज किए गए। हालांकि, मेमोरी चिप की बढ़ती मांग और कीमतों के कारण रिटेलर्स को आने वाले समय में इन फोन की कीमत बढ़ने की आशंका है। कंपनी ने ग्राहकों पर बढ़ती लागत का असर कम करने के लिए लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन करने की बात कही है। साथ ही भारत में इन स्मार्टफोन की खरीद पर लंबी अवधि की जीरो-कॉस्ट ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। जानकारों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर मेमोरी चिप की आपूर्ति और कीमतों को लेकर बने दबाव का असर भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर भी पड़ सकता है। इससे मौजूदा स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ नए मॉडल भी अपेक्षाकृत महंगे हो सकते हैं। रिटेलर्स का कहना है कि मेमोरी चिप की आपूर्ति का संकट आगे और गहरा सकता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए त्योहारी सीजन के डिस्काउंट का इंतजार करने के बजाय मौजूदा कीमतों पर ही स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीदना अधिक फायदे का सौदा हो सकता है।

जनहित और विकास से जुड़ी योजनाओं को समय पर पूरा करें जिलाधिकारी: मुख्य सचिव

नई सोच एक्सप्रेस

» मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों संग विभिन्न विभागों की योजनाओं पर समीक्षा बैठक की

पटना। राज्य के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने मंगलवार को विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में राज्य के सभी जिलाधिकारी और संबंधित विभागों के वरीय अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान कृषि, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, ऊर्जा सहित अन्य विभागों की योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जांच की गई। मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों को कहा कि विकास कार्यों और भूमि हस्तांतरण मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनहित और विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी विभागों से आपसी समन्वय बनाकर साप्ताहिक और मासिक स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा करने भी कहा। किसान रजिस्ट्री की स्थिति पर चर्चा करते हुए बताया गया कि राज्य में कुल 86.36 लाख किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक 53.54 लाख किसानों का रजिस्ट्री पूरा हो चुका है, जो लगभग 62 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति है। वैशाली और शेखपुरा जिलों ने इसमें शीर्ष प्रदर्शन किया है। मुख्य सचिव ने सारण और जमुई जैसे धीमी गति वाले जिलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्काल विशेष अभियान चलाकर पंजीकरण प्रक्रिया को तेज किया जाए। साथ ही राज्य स्तर पर सत्यापन के लिए लंबित आवेदनों को भी जल्द निपटाने को कहा। **सोलर इंस्टॉलेशन के लिए 1 लाख 22 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त:** ऊर्जा विभाग की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा में मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि राज्य में अब तक 1,22,656 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सोलर इंस्टॉलेशन का कार्य जारी है। पटना जिला इंस्टॉलेशन और 7,294 लाख रुपये की सब्सिडी के साथ सबसे आगे है। कुल 35,741 ऋण आवेदनों में से 58.8 प्रतिशत लोन स्वीकृत हो चुके हैं। मुख्य सचिव ने बैंकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर रिजेक्शन रेट कम करने और रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया। आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण को लेकर श्री अमृत ने जमीन की अनुपलब्धता और भूमि विवादों को तुरंत सुलझाने पर बल दिया। उन्होंने मनरेगा (वीबी-जी राम जी) और 15वें वित्त आयोग के संसाधनों के प्रभावी अभिसरण के माध्यम से भवन निर्माण को समय सीमा के भीतर पूरा कराने का निर्देश दिया। राज्य में 2.59 करोड़ लोगों की हुई टी.बी. स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा में पाया गया कि राज्य में कुल 2.59 करोड़ लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। यह 52 दिनों के लक्ष्य का 213 प्रतिशत है। सारण जिले ने 400 प्रतिशत और सहरसा ने 386 प्रतिशत स्क्रीनिंग कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर 'टीबी मुक्त भारत समिति' को सक्रिय रखने तथा निक्षय पोर्टल पर सभी परिणामों की समय पर एंट्री सुनिश्चित करने की हिदायत दी। उन्होंने फ्रंटलाइन स्क्रीनिंग बढ़ाने, शत-प्रतिशत अपफ्रंट न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (नैट) कराने और निक्षय पोषण योजना के तहत भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए। अब तक 93,275 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत भुगतान किया जा चुका है। **वेजफेड एवं नए कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण:** सहकारिता विभाग की समीक्षा में मुख्य सचिव ने प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचनाओं, कोल्ड स्टोरेज और तरकारी आउटलेट्स के लिए लंबित तीन भूमि प्राप्तियों तथा प्याज भंडारण के लिए लंबित नौ भूमि प्राप्तियों को तुरंत स्थानांतरित करने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया। **211 नए डिग्री कॉलेजों के लिए भूमि आवंटन:** उच्च शिक्षा क्षेत्र में 7 निश्चय-3 के अंतर्गत 211 नए डिग्री कॉलेजों के स्थायी परिसरों के निर्माण पर भी चर्चा हुई। अब तक 68 कॉलेजों के लिए भूमि विवरणी प्राप्त हो चुकी है, जबकि 143 कॉलेजों के लिए यह लंबित है। मुख्य सचिव ने पूर्वी चंपारण, सीवान और पटना के जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम पांच एकड़, शहरी क्षेत्रों के लिए 2.5 एकड़ और पटना शहरी क्षेत्र के लिए दो एकड़ भूमि का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए। प्रखंड मुख्यालयों के नजदीक सरकारी या गैरमजरूआ आम भूमि को जल्द आवंटित करने को कहा गया।

संक्षिप्त समाचार

तेज रफ्तार पिकअप की ठोकर से साइकिल सवार अधेड़ की मौत

मोतीहारी। सुगौली थाना क्षेत्र के छपवा-तुरकौलिया पथ में भरगावा फार्म के समीप मंगलवार को तेज रफ्तार पिकअप की ठोकर से साइकिल सवार 61 वर्षीय जवाहर शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दक्षिण सुगांव पंचायत के वार्ड संख्या-5 स्थित सुगांव बढ़ई टोला के निवासी बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार जवाहर शर्मा साइकिल से खेत देखने जा रहे थे। इसी दौरान छगराहा-वृता टोला की ओर से तुरकौलिया सड़क पर पहुंचने के दौरान तुरकौलिया की ओर से तेज गति से आ रही पिकअप ने उन्हें ठोकर मार दी। हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक पिकअप छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष अवनीश सिंह को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। इधर, मुखिया प्रभाकर मिश्र, अशोक झा, तप्पू झा, मंगनी मिश्र, प्रदीप मिश्र सहित कई लोगों ने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। पुलिस दुर्घटना में शामिल पिकअप को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश में जुटी है।

बंगरा गुमटी पर पत्थरबाजी रोकने को लेकर जीआरपी-आरपीएफ ने चलाया जागरूकता अभियान

मोतीहारी। सुगौली रेलवे पुलिस (जीआरपी) और आरपीएफ के सहयोग से मंगलवार को सुगौली एवं सेमरा के बीच बंगरा गुमटी पर पत्थरबाजी की घटनाओं की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों को रेलवे परिचालन की सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए पत्थरबाजी जैसी घटनाओं से दूर रहने की अपील की गई। पुलिस पदाधिकारियों ने लोगों को समझाया कि ट्रेनों पर पत्थर फेंकना गंभीर अपराध है। इससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और रेल परिचालन भी प्रभावित हो सकता है। लोगों से कानून को अपने हाथ में नहीं लेने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। अभियान के दौरान जीआरपी थानाध्यक्ष, एसआई संतोष साहनी, आरपीएफ के हवलदार जागेश्वर राम, जीआरपी सिपाही रीना कुमारी, नीतू कुमारी, शशि सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

महावीरी झंडा जुलूस को लेकर शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्ण आयोजन पर जोर

मोतीहारी। रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में सुगौली नगर में निकलने वाले महावीरी झंडा जुलूस को लेकर मंगलवार को सुगौली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं समाज के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। बैठक में महावीरी अखाड़ा जुलूस को निर्धारित समय एवं शांतिपूर्ण तरीके से निकालने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासन ने सभी अखाड़ा समितियों एवं आयोजकों से निर्धारित मार्ग, समय और नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं, जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रखने तथा किसी भी तरह की अफवाह या विवाद की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना देने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि पर्व-त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक हैं। सभी लोगों के सहयोग से महावीरी झंडा जुलूस शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाएगा।

गया में छात्राओं के लिए नई पहल, 1100 पर शिकायत और पोर्टल से मिलेगा समाधान

गया। गौतम बुद्ध महिला कॉलेज के सावित्री महाजन सभागार में मंगलवार को जिला प्रशासन गया के सहयोग से छात्राओं के लिए 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' आयोजित किया गया। शिविर में छात्राओं को बिहार सरकार की नई पहल 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब छात्राओं की शैक्षणिक और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन शिकायत के माध्यम से कराया जा सकेगा।कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्रधानाचार्य डॉ सहदेब बाउरी ने की। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर (डीपीओ) पूनम कुमारी ने छात्राओं को पोर्टल के उद्देश्य और उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगस्त 2026 से शुरू किए गए इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के शैक्षणिक संस्थानों एवं छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिकायतों समस्याओं और सुझावों का त्वरित एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की योजना है।उन्होंने छात्राओं से कहा कि अब अपनी समस्या के समाधान के लिए सड़क पर प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी। छात्राएं अपनी शिकायत सीधे पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकती हैं।कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्यारे मांझी ने किया। उन्होंने छात्राओं को पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की चरणबद्ध प्रक्रिया समझाई। प्रभारी प्रधानाचार्य डॉ. सहदेब बाउरी ने बताया कि पोर्टल के अलावा टॉल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से भी शिकायत और सुझाव दर्ज कराए जा सकते हैं।कॉलेज की मीडिया प्रभारी डॉ. कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी ने बताया कि पोर्टल पर दर्ज छात्र छात्राओं की शिकायतों का निवारण 30 दिनों के भीतर किए जाने की व्यवस्था है। यह शिविर प्रत्येक महीने के चौथे मंगलवार को कॉलेज सहित सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित किया जाएगा।छात्राएं पोर्टल के जरिए शैक्षणिक समस्याओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र, पेयजल, शौचालय, भोजन और सुरक्षा जैसी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगी।शिविर में डॉ. शगुफ्ता अंसारी, डॉ. कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी, डॉ. जया चौधरी, डॉ. पूजा राय, डॉ. पूजा, डॉ. प्रियंका कुमारी, डॉ. फरहीन वजीरी, प्रीति शेखर, डॉ. विजेता लाल, डॉ. शबाना परवीन हुसैन, डॉ. फातिमा, डॉ. आशुतोष कुमार पांडेय सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद रहीं।

गिद्धौर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए दिनभर जुटे रहे श्रद्धालु

नई सोच एक्सप्रेस

जमुई। सावन माह की अंतिम सोमवारी के अवसर पर गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक पंच मंदिर एवं बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में भगवान शिव को जलार्पण करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर दिनभर 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयकारों से गूंजता रहा। अंतिम सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। अहले सुबह से ही ग्रामीण श्रद्धालु मंदिरों की ओर पहुंचने लगे। महिला, पुरुष, युवा एवं बच्चे कतारबद्ध होकर भगवान शिव के दर्शन-पूजन के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और भगवान भोलेनाथ से परिवार की सुख-शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। विशेष रूप से महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने सावन सोमवारी का व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना की। मान्यता के अनुसार सावन की सोमवारी पर सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा और जलार्पण करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी धार्मिक आस्था के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं एवं कन्याओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा-अर्चना की। प्रखंड मुख्यालय के पंच मंदिर और बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के अलावा गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र की सभी आठ पंचायतों में स्थित शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में सुबह से लेकर दिनभर पूजा-अर्चना और जलार्पण का सिलसिला चलता रहा। सावन की अंतिम सोमवारी के अवसर पर पूरे गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र का वातावरण शिवमय बना रहा। मंदिरों में गूंजते जयकारों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल बना दिया।

» महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने व्रत रखकर किया जलार्पण

दादी प्रकाशमणि की 19वीं पुण्यस्मृति पर रक्तदान शिविर का आयोजन

नई सोच एक्सप्रेस

छपरा। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 19वीं पुण्यस्मृति के अवसर पर मंगलवार को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय, भगवान बाजार, छपरा में राष्ट्रीय स्तर के रक्तदान अभियान के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान कर मानवता की सेवा का संदेश दिया। डॉ. किरण ओझा ने कहा कि रक्तदान दुर्घटना पीड़ितों, गंभीर रोगियों, प्रसूता माताओं, ऑपरेशन कराने वाले मरीजों सहित अन्य जरूरतमंदों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय पर रक्त उपलब्ध होने से कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है। बीके अनामिका दीदी ने बताया कि दादी प्रकाशमणि की पुण्यस्मृति में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य लोगों को नियमित रक्तदान के प्रति जागरूक करना तथा रक्तदान को जनसेवा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि दादी प्रकाशमणि निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी की साक्षात प्रतिमूर्ति थीं। उन्होंने विश्व के 110 देशों में परमात्मा का संदेश पहुंचाया। शिविर में रक्तदान करने वाले लोगों को प्रोत्साहन स्वरूप रक्तदाता कार्ड एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। बीके अरविंद भाई ने कहा कि एक व्यक्ति का रक्तदान किसी जरूरतमंद के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है। उन्होंने लोगों से नियमित रक्तदान करने तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। इस अवसर पर बीके प्रियांशु बहन, बीके प्रिया बहन, बीके पिंकी बहन, बीके शेखर भाई, बीके सचिन भाई, बीके महादेव भाई सहित अन्य भाई-बहनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

आर्य समाज रोड, समस्तीपुर में ई-मेडिक्स स्मार्ट फार्मेसी की नई शाखा का शुभारंभ

नई सोच एक्सप्रेस

समस्तीपुर। समस्तीपुर के प्रमुख क्षेत्र आर्य समाज रोड में ई-मेडिक्स स्मार्ट फार्मेसी की नई शाखा का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. तरुण कुमार (माननीय एमएलसी, समस्तीपुर) ने फीता काटकर स्टोर का उद्घाटन किया। उन्होंने ई-मेडिक्स की इस पहल को स्थानीय स्तर पर बेहतर दवा सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर फ्रेंचाइज़ी ओनर श्रीमती स्नेहा कुमारी गुप्ता एवं श्री अभिषेक कुमार ने कहा कि ई-मेडिक्स स्मार्ट फार्मेसी के माध्यम से समस्तीपुर के लोगों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा देने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर अख्तरुल इस्लाम शाहीन (माननीय पूर्व विधायक, समस्तीपुर) एवं श्रीमती अनिता राम (माननीय मेयर, नगर निगम, समस्तीपुर) उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में राजेश कुमार, भुवनेश्वर राम (पूर्व प्राचार्य, के.ई. इंटर कॉलेज), अमित कुमार मुन्ना (नगर अध्यक्ष, जदयू, समस्तीपुर) एवं प्रदीप साह शिवे (प्रवक्ता, ओबीसी बीजेपी बिहार) ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अतिथियों ने ई-मेडिक्स की संगठित फार्मेसी व्यवस्था और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर दवा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास की सराहना की। ई-मेडिक्स की ओर से वकार सिद्दीकी (जनरल मैनेजर) एवं अमनदीप भारद्वाज (ऑपरेशंस मैनेजर) मौजूद रहे। इस अवसर पर जीएम वकार सिद्दीकी ने कहा, "समस्तीपुर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और आर्य समाज रोड में यह नई शुरुआत लोगों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। ई-मेडिक्स का उद्देश्य सिर्फ स्टोर खोलना नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। हम चाहते हैं कि लोगों को विश्वसनीय दवाओं के लिए दूर न जाना पड़े और उन्हें अपने ही शहर में आधुनिक एवं व्यवस्थित फार्मेसी सेवा मिले।" नई शाखा में ग्राहकों को ब्रांडेड एवं प्रमाणित दवाइयाँ, आकर्षक छूट, होम डिलीवरी, स्मार्ट बिलिंग तथा व्यवस्थित फार्मेसी सेवाओं का लाभ मिलेगा। ई-मेडिक्स स्मार्ट फार्मेसी की यह नई पहल आर्य समाज रोड और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधाजनक एवं भरोसेमंद दवा सेवा का नया विकल्प बनेगी। ई-मेडिक्स स्मार्ट फार्मेसी – 'हर दवा, पूरा भरोसा'

क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटीटिक्स पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग, छात्रों ने कुलपति को सौंपा आवेदन

नई सोच एक्सप्रेस

पूर्णिया। पूर्णिया विश्वविद्यालय में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटीटिक्स पाठ्यक्रम को लेकर छात्रों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने कुलपति को लिखित आवेदन देकर पाठ्यक्रम को पुनः सुचारू रूप से शुरू करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि यह रोजगारपरक पाठ्यक्रम उनके करियर और भविष्य से सीधे जुड़ा है। छात्रों के अनुसार क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटीटिक्स स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जिसकी अस्पतालों, क्लीनिकों, स्वास्थ्य संस्थानों और फिटनेस सेक्टर में मांग बढ़ रही है। छात्रों ने कहा कि उन्होंने पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर समय, मेहनत और आर्थिक संसाधन लगाए हैं। ऐसे में इसे बंद करना या अनिश्चित स्थिति में रखना उनके भविष्य को प्रभावित करेगा। छात्र नेता पीयूष पुजारा ने कहा कि रोजगारपरक पाठ्यक्रम को बंद करना छात्रों के हित में नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों की समस्याओं और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे तत्काल पुनः शुरू करना चाहिए। छात्रों ने उम्मीद जताई कि विश्वविद्यालय प्रशासन मामले में जल्द सकारात्मक निर्णय लेगा।

एनीमिया पर वारः गया में 4.80 लाख लाभुकों को मिलेगी आयरन-फॉलिक एसिड की खुराक

नई सोच एक्सप्रेस

गया। कुपोषण और एनीमिया यानी खून की कमी के खिलाफ गया जिले में 25 अगस्त से 30 नवंबर तक विशेष 'एनीमिया मुक्त बिहार अभियान' चलाया जाएगा। केंद्र सरकार के 'एनीमिया मुक्त भारत' अभियान के तहत शुरू किए गए इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से किया। अभियान के तहत बच्चों किशोर किशोरियों गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को आयरन फॉलिक एसिड की दवा उपलब्ध कराकर एनीमिया से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा।अभियान की शुरुआत के मौके पर जेपीएन सदर अस्पताल के सभागार में जांच शिविर लगाया गया। यहां एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं के रक्त की जांच की गयी और उन्हें आयरन फॉलिक एसिड की दवाएं दी गयीं।जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम नीलेश कुमार ने बताया कि जिले में 4 लाख 80 हजार लाभुकों को आयरन-फॉलिक एसिड की दवा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों के माध्यम से लक्षित वर्ग तक मुफ्त दवा और सिरप पहुंचाया जाएगा।स्वास्थ्य विभाग पंचायती राज संस्थाओं, जीविका दीदियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अभियान को गति देगा। आशा और एएनएम कार्यकर्ता घर-घर जाकर एनीमिया के लक्षण उससे होने वाले नुकसान और बचाव के उपायों की जानकारी देंगी।अधिकारियों ने बताया कि बच्चों में कुपोषण और एनीमिया का एक कारण पेट में कीड़े होना भी है। इसलिए अभियान के दौरान बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों और विटामिन-सी से भरपूर फलों के सेवन के महत्व की जानकारी देकर खान-पान में बदलाव के लिए प्रेरित किया जाएगा।वही सिविल सर्जन डॉ. राजाराम प्रसाद ने अभिभावकों और परिजनों से अपील की कि वे बच्चों और अन्य पात्र लाभुकों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा रही आयरन-फॉलिक एसिड की दवा का नियमित सेवन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य जिले में एनीमिया की दर को तेजी से कम करना है और इसके लिए शत-प्रतिशत लाभुकों तक पहुंच बनाना जरूरी है।

भैंस चोरी के आरोप में नया मोड़ः हम के नेता पहुंचे नौरंगा, आईजी ने दिए डीएनए टेस्ट के निर्देश

नई सोच एक्सप्रेस

गयाजी। अतरी थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में भैंस चोरी से जुड़े मामले को लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुन्दर शरण ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने प्रकाश मांझी और उनके परिजनों के साथ ग्रामीणों से बातचीत कर मामले से जुड़े तथ्यों को समझा।इसके बाद श्याम सुन्दर शरण पीड़ित परिवार और ग्रामीणों को साथ लेकर आईजी विकास वैभव से मिले और मामले की निष्पक्ष व त्वरित जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार से जुड़े मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जांच के जरिए सच्चाई सामने आनी चाहिए।मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी ने गया ग्रामीण एसपी दिव्यांजलि जायसवाल को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही भैंस के वास्तविक स्वामित्व की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने और जांच के आधार पर भैंस को उसके असली मालिक को सौंपने का भी निर्देश दिया है।श्याम सुन्दर शरण ने कहा कि न्याय हर व्यक्ति का अधिकार है। उनका उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच के जरिए वास्तविक तथ्य सामने लाना और सही मालिक को उसका हक दिलाना है।इस दौरान हम पार्टी के अनुमंडल प्रभारी श्रवण मांझी, बथानी प्रखंड अध्यक्ष अरुण मांझी, राहुल कुमार, कुंदन कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।

अलीगंज प्रखंड में स्थापित महाविद्यालय का पहला लाभ स्थानीय छात्र-छात्राओं को मिले, शिविर में उठी प्रमुख मांग

नई सोच एक्सप्रेस

जमुई। बिहार सरकार की सात निश्चय-2 योजना के तहत 'सबका सम्मान, जीवन आसान' के लक्ष्य को लेकर राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को आयोजित होने वाले विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन मंगलवार को राजकीय डिग्री महाविद्यालय, इस्लामनगर, अलीगंज में किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं ने अपनी समस्याओं, शिकायतों और अपेक्षाओं से महाविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया। शिविर में प्रमुख रूप से यह मांग सामने आई कि अलीगंज प्रखंड में स्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालय का प्रथम लाभ स्थानीय छात्र-छात्राओं को मिलना चाहिए। विद्यार्थियों का कहना था कि जिस उद्देश्य से प्रखंड में महाविद्यालय की स्थापना की गई है, उसका वास्तविक लाभ सबसे पहले इसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिलना आवश्यक है, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में ही उच्च शिक्षा का बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। प्राचार्य डॉ. गौरी शंकर पासवान ने कहा कि विद्यार्थी सहयोग शिविर विश्वास, संवाद और समाधान का मंच है। उन्होंने कहा कि समस्या आपकी है और समाधान की जिम्मेदारी हमारी है। छोटी हो या बड़ी, प्रत्येक विद्यार्थी की समस्या का समाधान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सहयोग की भावना से ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सह अलीगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अग्रेय राज ने कहा कि यह शिविर विद्यार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल है। छात्र अपनी समस्याओं को खुलकर रखें, उनके समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनना संवेदनशीलता है और उनके समाधान का प्रयास करना जिम्मेदारी। बर्सर डॉ. गिरधारी लाल लोधी ने कहा कि छात्र हित सर्वोपरि है और हर विद्यार्थी की बात महत्वपूर्ण है। इतिहास विभाग की सहायक प्राध्यापक अंजलि सार्थक एवं समाजशास्त्र के सहायक प्राध्यापक डॉ. राकेश कुमार ने स्थानीय विद्यार्थियों की मांग को प्रमुखता से रखा। सहायक प्राध्यापक श्रेय शेखर एवं अभिषेक कुमार ने कहा कि विद्यार्थी सहयोग शिविर विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मौके पर प्रो. कामेश्वर कुमार, प्रो. प्रिया कुमारी, अकाउंटेंट सह प्रधान सहायक सुशील कुमार, रूपेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

आगामी मिलाद-उन-नबी को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई

नई सोच एक्सप्रेस

जहानाबाद (हसनैन दीवाना)। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आगामी मिलाद-उन-नबी पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था, शांति एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर द्वारा की गई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों, विभिन्न समुदायों के धर्मगुरुओं, स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों एवं संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में संपन्न कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित सदस्यों से निर्धारित रूट चार्ट, समय-सारणी एवं प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा आयोजन के दौरान आपसी समन्वय बनाए रखने की अपील की गई। प्रशासन द्वारा विशेष रूप से अपील की गई कि आमजन किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा भ्रामक सूचना, विशेषकर सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट संदेशों पर ध्यान न दें। किसी संदिग्ध अथवा आपत्तिजनक सूचना की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन को सूचित करें। बैठक में शांति समिति के सदस्यों एवं धर्मगुरुओं से भी अपने-अपने स्तर से लोगों को शांति, भाईचारा, सामाजिक सद्भाव एवं प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुपालन के प्रति जागरूक करने का अनुरोध किया गया। जिला प्रशासन ने सभी जिलेवासियों से अपील की है कि मिलाद-उन-नबी के पवित्र अवसर को आपसी सद्भाव, भाईचारे एवं सामाजिक एकता की भावना के साथ हर्षोल्लास एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं तथा जिले की सौहार्दपूर्ण परंपरा को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

संक्षिप्त समाचार

कोटक बिजलैब्स सीजन-3 में 100 से अधिक स्टार्टअप्स को मिलेगा सहयोग

पटना। कोटक महिंद्रा बैंक ने प्रारंभिक राजस्व चरण के स्टार्टअप्स के लिए अपनी सीएसआर पहल कोटक बिजलैब्स एक्सेलेरेटर प्रोग्राम सीजन-3 शुरू करने की घोषणा की है। अगस्त 2026 से अक्टूबर 2027 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत देशभर के 100 से अधिक स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, उद्योग जगत से जुड़ने के अवसर और शुरुआती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सीजन-3 में आईआईएम कलकत्ता इनोवेशन पार्क, सीआईआईई इनिशिएटिव्स, आईआईएमबी/एनएसआरसीईएल, टी-हब और आईआईटी दिल्ली का एफआईटीटी सहित पांच इनक्यूबेशन पार्टनर शामिल हैं। कार्यक्रम में एग्रीटेक, क्लाइमेट टेक, फिनटेक, हेल्थटेक, एडटेक, स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डीप-टेक स्टार्टअप्स पर भी जोर रहेगा। कोटक के अनुसार कार्यक्रम को अब तक 4,500 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं और 125 से अधिक स्टार्टअप्स को सहयोग दिया गया है। 100 से अधिक स्टार्टअप्स को अनुदान भी प्रदान किया जा चुका है। सीजन-3 के लिए डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के आवेदन खुले हैं।

रेलकर्मियों ने महाप्रबंधक से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से कराया अवगत

पटना। मुख्यालय, हाजीपुर में 07 रेलकर्मी,उनके आश्रितों ने पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह से मुलाकात की तथा अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया । महाप्रबंधक ने संबंधित विभागों को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में केस निष्पादन के निर्देश दिए। रेलकर्मियों एवं उनके आश्रितों की विभागीय समस्याओं के निष्पादन के उद्देश्य से महाप्रबंधक से मुलाकात हेतु प्रत्येक मंगलवार का दिन निर्धारित किया गया है। इसके लिए रेलकर्मी अपना नाम पूर्व में कार्मिक विभाग में पंजीकृत करवाकर मंगलवार को महाप्रबंधक से मुलाकात कर अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकते हैं ।

प्रेम यूथ फाउंडेशन के शांति दूत नेपाल में सम्मानित

पटना। भारत-नेपाल की मित्रता और विश्व शांति का संदेश के संकल्प के साथ प्रेम यूथ फाउंडेशन के दर्जनों शांतिदूत काठमांडू नेपाल में सम्मानित । फाउंडेशन के प्रोग्राम ऑफिसर सुधांशु राज ने कहा कि शांति के बिना विकास संभव नही है । उन्होंने बताया कि सात दिवसीय शांति शिविर में दुनिया मे शांति स्थापित करने को लेकर विमर्श किया गया । आज पूरी दुनिया मे अशांति और भय का माहौल है तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ा है । जहाँ एक ओर रूस और यूक्रेन , अमेरिका और ईरान आमने सामने है इजराइल और हमास में भय का माहौल है । दुनिया बारूद के ढेर पर बैठा है । जे एन जी और जेड अल्फा तुरंत सब कुछ पा लेना चाहता है तत्कालिक लाभ के लिए कुछ भी करने को तैयार है । अराजक तत्वों के हाथों के कठपुतली बन रहा है । उन्होंने युवाओं से आह्वान किया की जात पात एवं धर्म के भावना से ऊपर उठकर अमन चैन एवं विश्व शांति के लिए प्रयत्न करें । उन्होंने बताया कि हर गाँव मे पीस क्लब खोला जा रहा है । शांति दूत एक सप्ताह तक नेपाल में घूमघूम कर लोगो को शांति का संदेश देगे । आज पूरी दुनिया मे अशांति का वातावरण बन रहा है यह सिर्फ एक घटना नही मानवता की चेतना का परिदृश्य है । शांति दूत महात्मा गांधी एवं विनोवा जी के आदर्शों पर चलकर शांति अभियान चलाया जा रहा है ।

इंटर स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में ज्ञान निकेतन विजेता

खगौल। मोहम्मदपुर स्थित आदर्श विकास विद्यालय में इंटर स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप-2026 अंडर-14 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में चार विद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले में ज्ञान निकेतन स्कूल, पटना ने आदर्श विकास विद्यालय, खगौल को 25-18, 15-25 और 25-18 से हराकर खिताब अपने नाम किया। आदर्श विकास विद्यालय की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में आदर्श विकास विद्यालय ने संत करेंस सेकेंडरी हाई स्कूल, खगौल को हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में ज्ञान निकेतन ने पटना सेंट्रल स्कूल को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। आदर्श विकास विद्यालय के आदित्य राज को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। विजेता टीम को शील्ड, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर विद्यालय की वाइस प्राचार्य एवं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर मधुकर ने सम्मानित किया। विद्यालय के खेल शिक्षक उत्तम कुमार ने आयोजन की सफलता पर विद्यालय परिवार, शिक्षकों और खिलाड़ियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय खेल दिवस-2026 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक

नई सोच एक्सप्रेस

पटना। राष्ट्रीय खेल दिवस-2026 के आयोजन की तैयारियों एवं युवा-केंद्रित विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर आज खेल विभाग, बिहार सरकार में माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार की माननीय खेल मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह एवं खेल विभाग के सचिव श्री दीपक आनंद सहित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय खेल दिवस के माध्यम से देशभर के युवाओं को खेल, सकारात्मक सोच, चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता एवं राष्ट्र निर्माण से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान करने तथा उन्हें खेल एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने की कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में Viksit Bharat Young Leaders Dialogue (VBYLD)-2026 में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने, राज्य स्तर पर कार्यक्रम की व्यापक पहुंच बनाने तथा जिला एवं राज्य स्तर के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों का स्वामित्व लेकर प्रभावी क्रियान्वयन करने पर बल दिया गया। इसके तहत युवाओं को जोड़ने के लिए My Bharat Registration को भी व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने की बात कही गई। Viksit Bharat Challenge के तहत बिहार को Ganga Growth Belt क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश एवं बिहार के साथ जनसांख्यिकीय लाभांश, मानव पूंजी विकास एवं युवा विकास से जुड़े विषयों पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। क्विज, निबंध, जिला चैंपियनशिप, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय संवाद के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा एवं विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। बैठक में Khelo India Samvaad को भी महत्वपूर्ण पहल के रूप में शामिल किया गया। इसके तहत प्रख्यात खिलाड़ियों एवं युवा आइकन के साथ युवाओं का संवाद कराया जाएगा, जिसमें खिलाड़ी अपने अनुभव साझा करेंगे तथा युवाओं से खेल, युवा विकास एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़े विचार एवं सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। इन संवादों से प्राप्त महत्वपूर्ण विचारों को संकलित कर आगे की कार्ययोजना में शामिल करने पर भी चर्चा हुई।कार्यक्रमों में युवा स्वयंसेवकों की अधिकतम भागीदारी, जिला एवं राज्य स्तर के युवा पदाधिकारियों की सक्रिय भूमिका तथा स्थानीय स्तर पर युवाओं से निरंतर संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके साथ ही युवाओं को नशा मुक्ति, स्वस्थ जीवनशैली एवं सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने के लिए विशेष गतिविधियां संचालित करने तथा राष्ट्रीय खेल दिवस के संदेश को व्यापक स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। क्विज एवं अन्य युवा-केंद्रित गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की कार्ययोजना पर भी विचार-विमर्श हुआ।बैठक में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की मिनट-टू-मिनट रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन, Khelo India Samvaad, युवा संवाद, नशा मुक्ति की शपथ एवं राष्ट्रीय गान सहित विभिन्न कार्यक्रमों को निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप आयोजित करने की योजना है। राष्ट्रीय खेल दिवस-2026 के माध्यम से युवाओं को खेल भावना, अनुशासन, नेतृत्व, सकारात्मक सोच, स्वस्थ जीवनशैली और विकसित भारत के निर्माण से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार में भी इन कार्यक्रमों में अधिकाधिक युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

सूफी महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण

नई सोच एक्सप्रेस

जहानाबाद (हसनैन दीवाना)। सूफी महोत्सव के सफल आयोजन एवं आवश्यक तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया ने काको स्थित कार्यक्रम स्थल, काको पनिहास तथा बीबी कमाल दरगाह का निरीक्षण किया गया। काको दरगाह समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि इस वर्ष सूफी महोत्सव के अवसर पर 24 सितम्बर को आमजन द्वारा चादरपोशी की जाएगी, जबकि 25 सितम्बर को जिला प्रशासन की ओर से चादरपोशी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम मध्य विद्यालय, काको के खेल मैदान, प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला नजारत उप समाहर्ता को आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित निविदा प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर एजेंसी का चयन एवं कार्य आवंटन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को आपसी समन्वय से आवश्यक रंग-रोगन एवं अन्य कार्य कराने को कहा गया। कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, काको को निर्देशित किया गया। वहीं कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी को अस्थायी शौचालय एवं पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा कार्यपालक अभियंता, विद्युत को समुचित प्रकाश व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। महोत्सव में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए जीविका दीदियों के माध्यम से रसोई,फूड स्टॉल की व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया गया। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने काको पनिहास का निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब की उड़ाही एवं साफ-सफाई कराने के साथ इसके सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन तैयार कर डीपीओ, नमामि गंगे को शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, काको को दिया ताकि विभागीय स्तर पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी ने बीबी कमाल दरगाह का भी निरीक्षण किया। दरगाह समिति के सदस्यों ने बताया कि सूफी महोत्सव के दौरान दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं के आवासन, शौचालय, पेयजल, साफ-सफाई एवं नियमित कचरा उठाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दरगाह परिसर में आवश्यक रंग-रोगन एवं मरम्मति कार्य भी आपसी समन्वय से कराने को कहा गया। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं समन्वित रूप से पूर्ण करने का निर्देश देते हुए कहा कि सूफी महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं एवं दर्शकों की सुविधा, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए।निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पियूष, प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा-सह-निदेशक डीआरडीए डॉ.रोहित कुमार मिश्रा, जिला नजारत उप समाहर्ता-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी चन्द्रकिशोर सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी चाँदनी कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत काको, प्रखंड विकास पदाधिकारी काको, अंचल अधिकारी काको, डीपीओ नमामि गंगे, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण/पीएचईडी/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन सहित अन्य पदाधिकारी एवं दरगाह समिति के सदस्य उपस्थित थे।

2009 से चल रहे रिश्ते में विवाद, शादी से इनकार पर युवती ने दर्ज कराई प्राथमिकी

नई सोच एक्सप्रेस

गया जी। वजीरगंज थाना क्षेत्र के भलुआही गांव की युवती की शिकायत पर पुलिस ने शादी का भरोसा देकर संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। युवती ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि वर्ष 2009 से आरोपी के साथ उसका संपर्क था। इस दौरान आरोपी ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए लेकिन बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। युवती ने अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र आरोपी के पास होने का भी आरोप लगाया है। शिकायत में बातचीत की रिकॉर्डिंग और चैटिंग को भी साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध होने की बात कही गई है।बताया जाता है कि मामले को लेकर गांव में पंचायत के माध्यम से विवाद सुलझाने का प्रयास किया गया लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद युवती ने वजीरगंज थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नवाचारी शिक्षा पद्धति के लिए पटना के दो शिक्षक भोजपुर में सम्मानित

नई सोच एक्सप्रेस

पटना। नवाचारी एवं प्रभावी शिक्षा पद्धति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पटना के दो शिक्षकों को भोजपुर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में प्राथमिक विद्यालय पसही की शिक्षिका एवं टीबीटी पटना प्रमंडल की अध्यक्ष बबीता कुमारी तथा प्राथमिक विद्यालय भूसेनचक के शिक्षक एवं टीबीटी पटना प्रमंडल के मीडिया प्रभारी शैलेश कुमार शामिल हैं। टीबीटी ग्रुप एवं टीबीटी भोजपुर जिला टीम की ओर से दोनों शिक्षकों को मोमेंटो, अंगवस्त्र एवं बुके प्रदान कर सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गतिविधि आधारित शिक्षण, रचनात्मक शिक्षण विधियों तथा आधुनिक तकनीकों के प्रभावी प्रयोग के लिए उनके योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने कहा कि विद्यालयी शिक्षा को रोचक, सरल और प्रभावी बनाने में नवाचारी शिक्षण पद्धति की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे शिक्षकों का सम्मान अन्य शिक्षकों को भी नई तकनीकों और रचनात्मक गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। सम्मान प्राप्त करने के बाद बबीता कुमारी एवं शैलेश कुमार ने टीबीटी टीम और भोजपुर जिला टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है और वे भविष्य में भी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए निरंतर नवाचार करते रहेंगे।

विलक्षण व्यक्तित्व की धनी थीं दादी प्रकाशमणि

नई सोच एक्सप्रेस

फतुहा। एक महान हस्ती! सेवा, सादगी, करुणा और नेतृत्व की ऐसी मिसाल, जिसे राजनीति भी अपना ले तो समाज बदल सकता है।दादी प्रकाशमणि केवल एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं थीं, बल्कि वे मानवता, प्रेम, अनुशासन, सेवा और कुशल नेतृत्व की ऐसी जीवंत मिसाल थीं, जिन्होंने अपने आचरण से हजारों-लाखों लोगों को प्रभावित किया। उनका जीवन यह संदेश देता था कि नेतृत्व पद, प्रतिष्ठा या अधिकार से नहीं, बल्कि व्यवहार, त्याग, विश्वास और सेवा से पैदा होता है। आज जब राजनीति में नेतृत्व को अक्सर सत्ता, सुरक्षा, सुविधाओं, पद और प्रचार से जोड़कर देखा जाता है, तब दादी प्रकाशमणि का जीवन एक बड़ा सवाल खड़ा करता है—क्या सार्वजनिक जीवन में आने वाला व्यक्ति पहले सेवक है या शासक? दादी जी का मानना था कि अपने आसपास लोगों की भीड़ खड़ी कर लेना नेतृत्व नहीं है। वास्तविक नेतृत्व वह है जिसमें लोग स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और विश्वास से भरा हुआ महसूस करें। यही कारण था कि उनके साथ रहने वाले लोग केवल अनुयायी नहीं थे, बल्कि स्वयं को परिवार का सदस्य समझते थे।

नेतृत्व का अर्थ—सबको साथ लेकर चलनाःदादी प्रकाशमणि की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे किसी को छोटा-बड़ा समझकर व्यवहार नहीं करती थीं। उनकी दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक संभावना थी। वे लोगों को आदेश देने के बजाय उन्हें विश्वास, प्रेरणा और जिम्मेदारी देती थीं।

आज की राजनीति के लिए यह सबसे बड़ा सबक है। राजनीतिक दलों में कार्यकर्ता अक्सर चुनाव के समय याद आते हैं और चुनाव समाप्त होते ही उनकी भूमिका सीमित हो जाती है। इसके विपरीत दादी जी ने संगठन को परिवार की तरह चलाने की संस्कृति विकसित की। उनका नेतृत्व यह सिखाता है कि कार्यकर्ता केवल नारा लगाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि संगठन की आत्मा होता है। जिस नेतृत्व में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं, वह नेतृत्व लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकता। 'मैं' नहीं, 'हम' की राजनीति दादी प्रकाशमणि की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था—अहंकार से ऊपर उठकर सामूहिकता। आज सार्वजनिक जीवन में 'मैंने किया', 'मेरे कारण हुआ', 'मेरी उपलब्धि' जैसे शब्द तेजी से बढ़ रहे हैं। राजनीति में व्यक्तिगत प्रचार इतना बढ़ गया है कि कई बार जनसेवा पीछे और प्रचार आगे दिखाई देता है। दादी जी का जीवन इसके बिल्कुल विपरीत संदेश देता है। उनका व्यक्तित्व बताता है कि नेता की वास्तविक ताकत उसके पीछे खड़े लोगों की संख्या नहीं, बल्कि उसके प्रति लोगों का विश्वास और आत्मीयता है।

राजनीति में सादगी की जरूरतःदादी प्रकाशमणि का जीवन सादगी का प्रतीक था। उन्होंने दिखाया कि प्रभाव पैदा करने के लिए बड़े-बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। एक साफ विचार, मधुर वाणी, ईमानदार व्यवहार और सेवा की भावना भी समाज में गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। आज यदि जनप्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ता उनके जीवन से प्रेरणा लें तो राजनीति का चरित्र बदल सकता है। जनता के बीच रहने वाला नेता जनता की समस्याओं को बेहतर समझ सकता है। सरकारी सुविधा जितनी अधिक, जनता से दूरी उतनी अधिक—यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। जनप्रतिनिधि का वास्तविक सम्मान उसके वाहन, आवास या सुरक्षा से नहीं, बल्कि उसके क्षेत्र की जनता के बीच उसकी उपलब्धता से होना चाहिए।

संवाद की शक्ति को समझना होगाःदादी जी की एक बड़ी विशेषता थी—वे सुनती थीं। सामने वाला अपनी बात कह सके, उसकी पीड़ा समझी जाए और फिर उचित मार्गदर्शन दिया जाए—यह नेतृत्व की बुनियादी शर्त है।

प्रबुद्ध साहित्यकारों ने किया प्रो. वीणा अमृत के काव्य संग्रह 'मेरे हिस्से का आसमान' का लोकार्पण

नई सोच एक्सप्रेस

पटना। दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर और वी.के. कॉलेज डुमरांव की प्राचार्य वीणा अमृत के कविता संग्रह 'मेरे हिस्से का आसमान' का लोकार्पण राजधानी पटना के 'बापू टावर सभागार' में हुआ। इस 'काव्य संग्रह' का लोकार्पण लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों आलोक धन्वा, अरुण कमल, गीताश्री, पूनम सिंह, संतोष दीक्षित और बापू टावर के निदेशक विनय कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस काव्य संग्रह के विमर्श में मुख्यवक्ता के रूप में प्रसिद्ध लेखिका भावना शेखर ने कहा कि प्रतिरोध के बावजूद इस संग्रह की कविताओं में प्रेम कायम है। विमर्श में निवेदिता झा, कुमार वरुण और चंद्रविन्द ने भी भाग लिया। पुस्तक 'मेरे हिस्से का आसमान की लेखिका वीणा अमृत ने कहा, "जिंदगी के उतार चढ़ाव, चुनौतियां, कुछ खोना, कुछ पाना, कभी टूटना, बिखरना, संबंधों का मंथन सब कुछ इस 'संग्रह' में घुल गया है और एक पुस्तक बन गयी है 'मेरे हिस्से का आसमान'" पुस्तक का विश्लेषण करते हुए प्रख्यात कथा लेखिका और कवयित्री गीताश्री ने कहा कि इस संग्रहालय की कविताएं सुख दुख की अविरल धारा से भरी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि स्त्री का दुख और उसका आंतरिक संसार पुरुषों से अलग होता है और उन्हीं अनुभूतियों की झलक इस संग्रह में मिलती हैं। नामवर कवि अरुण कमल ने कहा कि कविता के क्षेत्र में स्त्रियां पहले बहुत कम थीं, लेकिन आज 300 से ज्यादा प्रबुद्ध महिलाएं इस विधा पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक आजादी ने स्त्रियों की रचनात्मकता को नया आयाम दिया। श्री कमल ने लोकार्पित संग्रह की कविता 'हिसाब' का पाठ भी किया। कवियत्री पूनम सिंह ने कहा कि स्त्री देह तक तो हर पुरूष पहुंचना चाहता है, लेकिन अंतर्मन तक बिरले ही पहुंच पाते हैं। इस संग्रह में उंस अनुभूति के दर्शन होते हैं। इस अवसर पर मशहूर साहित्यकार शिव दयाल, भावना शेखर, कुमार वरुण, निवेदिता, सुनीता गुप्ता, उपस्थिति थे। मंच संचालन लेखिका सुमेधा पाठक एवं रंजीता तिवारी ने किया।

बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने आज अपने कार्यालय कक्ष में 05:00 बजे अप. में मुख्य सचिव, बिहार श्री प्रत्यय अमृत के साथ बैठक की

नई सोच एक्सप्रेस

पटना। बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने आज अपने कार्यालय कक्ष में 05:00 बजे अप. में मुख्य सचिव, बिहार श्री प्रत्यय अमृत के साथ बैठक की। इस बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों एवं सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर उक्त प्रक्रिया को यथाशीघ्र कैशलेस करने का निदेश दिया। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों के बैठने हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में स्थान / भूखण्ड चिन्हित कर भवन निर्माण कराने अथवा पंचायत भवन में ही व्यवस्था करने का सुझाव दिया । तत्पश्चात, माननीय अध्यक्ष ने कहा कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के आधार पर वर्ष 2008-2009 से अब तक लोक लेखा समिति एवं लोक उपक्रम समिति की लगभग 2499 कंडिका (उप कंडिकाओं सहित) लंबित है एवं विभिन्न विभागों के वर्ष 1995-2025 तक वर्तमान में लगभग 23517 आश्वासन लंबित है। इन लंबित मामलों पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को समिति एवं विभाग के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर इस वित्तीय वर्ष में लंबित मामलों के निष्पादन का निदेश दिगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बिहार विधान सभा की संसदीय समितियों की विभागीय बैठकों में संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव की अनुपस्थिति पर सख्ती दिखाते हुए मुख्य सचिव को निदेश दिया की विशेष परिस्थिति को छोड़कर उक्त पदाधिकारियों की अनुपस्थिति में विशेष सचिव के ऊपर स्तर के पदाधिकारी को बैठक में सम्मिलित होने हेतु प्राधिकार पत्र के माध्यम से प्राधिकृत किया जाय । मुख्य सचिव ने माननीय अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव के साथ बैठक कर प्राप्त निदेशों का अनुपालन किया जाएगा । इस बैठक में बिहार विधान सभा की प्रभारी सचिव सहित सभा सचिवालय के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

विकसित भारत 2047 की नींव : सरकारी स्कूलों की हालत कब बदलेगी?

आरती कुमारी

भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की प्रगति, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष विज्ञान में उपलब्धियां, आधुनिक आधारभूत ढांचे का विस्तार और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव निश्चित रूप से गर्व का विषय हैं। लेकिन विकसित भारत की इस महत्वाकांक्षी यात्रा के बीच एक बुनियादी सवाल लगातार खड़ा होता है—क्या मजबूत शिक्षा व्यवस्था के बिना विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के सरकारी स्कूलों की स्थिति आज भी कई जगह गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। एक तरफ हम विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल संस्थानों और अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर देश के हजारों सरकारी विद्यालयों में बच्चे पर्याप्त शिक्षकों, सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली, पंखे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस शिक्षा व्यवस्था को 2047 के भारत की मानव पूंजी तैयार करनी है, यदि उसकी बुनियाद कमजोर रही तो विकसित भारत की इमारत कितनी मजबूत होगी, यह गंभीर चिंतन का विषय है। यूडीआईएसई प्लस 2024-25 के आंकड़े इस चिंता को स्पष्ट करते हैं। देश में 1,04,125 ऐसे स्कूल हैं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत है। इन विद्यालयों में लगभग 33.77 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक को एक साथ कई कक्षाओं, अलग-अलग विषयों और बच्चों की विभिन्न शैक्षणिक जरूरतों को संभालना पड़ रहा है। इसके अलावा विद्यालय से जुड़े प्रशासनिक कार्य भी उसी शिक्षक के जिम्मे होते हैं। ऐसी स्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा करना आसान नहीं है। यह केवल सरकारी आंकड़ा नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। देश के ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकारी स्कूल आज भी शिक्षा का सबसे सुलभ और कई बार एकमात्र माध्यम हैं। यदि वहां शिक्षक नहीं होंगे, भवन सुरक्षित नहीं होगा और पढ़ाई का वातावरण बेहतर नहीं होगा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को ही उठाना पड़ेगा। विडंबना यह है कि जिस समय देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शिक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और आधुनिक तकनीक की नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी कर रहा है, उसी समय कहीं-कहीं बच्चे टूटी छत और जर्जर कमरों के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। कहीं एक शिक्षक पांच कक्षाओं को संभाल रहा है तो कहीं विद्यालय में पेयजल की सुविधा नहीं है। कई जगह शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी अपेक्षित स्तर पर नहीं हैं। हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से विद्यार्थियों द्वारा बेहतर शैक्षणिक और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन की खबरें सामने आईं। फतेहपुर में करीब एक हजार विद्यार्थियों ने जर्जर कक्षाओं, रिसती छतों और सुरक्षित पेयजल जैसी सुविधाओं की मांग को लेकर आवाज उठाई। यह घटना केवल एक विद्यालय या एक जिले की समस्या नहीं मानी जानी चाहिए। यह उस व्यापक चुनौती की ओर संकेत करती है, जिसका सामना देश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था के कई हिस्से कर रहे हैं। हालांकि तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। यूडीआईएसई प्लस के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में कुल 14.71 लाख स्कूल, करीब 24.69 करोड़ विद्यार्थी और एक करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या लगभग 10.13 लाख है, जबकि निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या करीब 3.40 लाख है। एकल-शिक्षक विद्यालयों की संख्या 2023-24 के 1,10,971 से घटकर 2024-25 में 1,04,125 हुई है। इसी अवधि में कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 64.7 प्रतिशत हुआ है। इन आंकड़ों को सुधार के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन सुधार की दिशा में कुछ कदम बढ़ जाना मंजिल तक पहुंचने का प्रमाण नहीं हो सकता। शिक्षा की वास्तविक कसौटी यह नहीं है कि कितने स्कूलों में कंप्यूटर पहुंच गया या कितने विद्यालयों में भवन बन गए। असली सवाल यह है कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कितना सीख रहा है, उसकी भाषा और गणित की समझ कितनी विकसित हो रही है और क्या वह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था के सामने मौजूद चुनौती को रेखांकित करती है। वर्ष 2014-15 में देश में 11.07 लाख सरकारी स्कूल थे, जो 2024-25 में घटकर लगभग 10.13 लाख रह गए। दूसरी ओर निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर करीब 3.39 लाख हो गई। स्कूलों की संख्या में यह बदलाव अपने आप में निर्णायक प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे अभिभावकों की बदलती पसंद और सरकारी शिक्षा व्यवस्था में घटते भरोसे के संकेत के रूप में गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। आखिर अभिभावक निजी स्कूलों की ओर क्यों जा रहे हैं? केवल इसलिए नहीं कि निजी स्कूल बेहतर दिखते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे नियमित कक्षाएं, अनुशासन, अंग्रेजी शिक्षा, तकनीकी सुविधाएं, अभिभावकों के साथ संवाद और बच्चों की निगरानी जैसी व्यवस्थाओं पर अधिक जोर देते हैं। सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें उन सकारात्मक व्यवस्थाओं से सीखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए जिनसे बच्चों की सीखने की क्षमता बेहतर होती है। एसीईआर के आंकड़े भी सीखने के स्तर में अंतर की ओर संकेत करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कक्षा तीन के बच्चों में कक्षा दो स्तर का पाठ पढ़ पाने वाले बच्चों का अनुपात सरकारी स्कूलों में 23.4 प्रतिशत था, जबकि निजी स्कूलों में यह 35.5 प्रतिशत था। कक्षा पांच में सरकारी स्कूलों का आंकड़ा 44.8 प्रतिशत और निजी स्कूलों का 59.3 प्रतिशत रहा। इसका अर्थ साफ है कि चुनौती केवल स्कूल भवनों की नहीं, बल्कि कक्षा के भीतर होने वाली वास्तविक पढ़ाई की भी है। शिक्षा की समस्या प्राथमिक स्तर से शुरू होकर उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं तक पहुंचती है। पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितता, भर्ती में देरी और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर युवाओं में असंतोष की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। वर्ष 2026 में परीक्षा संबंधी विवादों ने भी विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के बीच चिंता बढ़ाई। यदि प्राथमिक शिक्षा में बच्चे की नींव कमजोर है, माध्यमिक शिक्षा में सीखने की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है और उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को समग्र दृष्टि से देखने की जरूरत है। सरकारी स्कूल केवल शिक्षण संस्थान नहीं हैं। वे भारत में सामाजिक समानता के सबसे महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक हैं। ग्रामीण परिवारों, मजदूरों, किसानों, निम्न आय वर्ग और वंचित समुदायों के लाखों बच्चे इन्हीं स्कूलों पर निर्भर हैं। इसलिए सरकारी स्कूलों की बदहाली को केवल शिक्षा विभाग की समस्या मानना उचित नहीं होगा। यह सामाजिक न्याय और अवसर की समानता से जुड़ा सवाल भी है। इसी संदर्भ में एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण विचार पर बहस होनी चाहिए—क्या जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने अथवा ऐसी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की कोई व्यावहारिक व्यवस्था बनाई जा सकती है? इस विचार पर कानूनी, सामाजिक और व्यावहारिक स्तर पर व्यापक चर्चा आवश्यक है। यदि नीति बनाने वाले और प्रशासन चलाने वाले लोग स्वयं सरकारी स्कूलों की वास्तविकताओं से सीधे जुड़े हों, तो संभव है कि शिक्षक की कमी, जर्जर भवन, बंद शौचालय, खराब पेयजल या भोजन की गुणवत्ता जैसे मुद्दे केवल सरकारी फाइलों का हिस्सा न रहकर प्राथमिकता बन जाएं। सरकार को अब एक व्यापक 'राष्ट्रीय सरकारी स्कूल कायाकल्प मिशन' जैसे पहल पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हर सरकारी विद्यालय के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के स्पष्ट मानक तय होने चाहिए। प्रत्येक स्कूल में आवश्यकतानुसार शिक्षक उपलब्ध हों। भवन सुरक्षित हों। पीने का पानी, बिजली, शौचालय, पंखे, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल सुविधाएं और डिजिटल संसाधन उपलब्ध हों। लेकिन इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण मानक बच्चों के सीखने के परिणामों को बनाया जाना चाहिए। हर विद्यालय का एक सार्वजनिक डिजिटल डैशबोर्ड बनाया जा सकता है, जिसमें शिक्षक उपलब्धता, विद्यार्थियों की संख्या, बुनियादी सुविधाओं, उपस्थिति और सीखने के परिणामों की जानकारी उपलब्ध हो। इससे अभिभावक और स्थानीय समुदाय भी विद्यालय की स्थिति पर नजर रख सकेंगे। स्कूल प्रबंधन समितियों को केवल कागजी संस्था बनाकर नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें वास्तविक अधिकार और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण में पारदर्शिता आवश्यक है। राजनीतिक हस्तक्षेप पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना चाहिए। शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में अनावश्यक रूप से लगाने की प्रवृत्ति कम होनी चाहिए। उन्हें प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधन और सम्मानजनक कार्य वातावरण दिया जाना चाहिए। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का केंद्र भवन या कंप्यूटर नहीं, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए केवल अधिक बजट खर्च करना पर्याप्त नहीं होगा। खर्च की गुणवत्ता, निगरानी और परिणामों की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। जिला स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिस विद्यालय में लगातार शिक्षक की कमी है, जहां बच्चों की सीखने की क्षमता में सुधार नहीं हो रहा या जहां वर्षों से बुनियादी सुविधाएं अधूरी हैं, वहां जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठाना होगा। सरकार और विपक्ष दोनों को यह समझना चाहिए कि सरकारी स्कूल किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि देश के भविष्य की प्रयोगशाला हैं। यदि विपक्ष किसी स्कूल की बदहाली पर सवाल उठाता है तो सरकार को इसे केवल राजनीतिक हमला नहीं मानना चाहिए। और यदि सरकार सुधार करती है तो विपक्ष को उसका राजनीतिक विरोध करने के बजाय उसे बेहतर बनाने के सुझाव देने चाहिए। बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति से बड़ा होना चाहिए। भारत 2047 में कैसा होगा, इसका फैसला केवल जीडीपी, सड़कों, एक्सप्रेस-वे, अंतरिक्ष अभियानों या डिजिटल सेवाओं से नहीं होगा। असली विकसित भारत वह होगा जहां किसी बच्चे को इसलिए पीछे न रहना पड़े क्योंकि उसके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकल्प नहीं था। वह भारत तब बनेगा जब गांव का बच्चा भी शहर के बच्चे की तरह सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर पाएगा। विकसित भारत की असली नींव स्कूल की कक्षा में रखी जाएगी। आज का विद्यार्थी ही 2047 का डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, उद्यमी, सैनिक, प्रशासक और जनप्रतिनिधि बनेगा। यदि उसकी नींव मजबूत होगी तो भारत की इमारत भी मजबूत होगी। इसलिए अब समय केवल बड़े लक्ष्य घोषित करने का नहीं, बल्कि उन छोटे-छोटे स्कूलों को मजबूत करने का है जहां भारत का भविष्य रोज बैठता है। 2047 का सपना केवल आर्थिक समृद्धि का सपना नहीं होना चाहिए। यह समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक न्याय और सक्षम नागरिकों का सपना भी होना चाहिए। यदि भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनना है तो सरकारी स्कूलों की दीवारों को मजबूत करना ही पर्याप्त नहीं होगा—उन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के सपनों को मजबूत करना होगा। यही विकसित भारत की सबसे जरूरी शर्त है।

छात्रों की आवाज लोकतंत्र की ताकत है - तिरंगा आंदोलन की ढाल नहीं

जितेन्द्र कुमार सिन्हा

पटना: लोकतंत्र केवल चुनाव, सरकार और विपक्ष का नाम नहीं है। लोकतंत्र की असली ताकत उस आवाज में होती है, जो सत्ता के सामने अपनी बात कहने का साहस रखती है। इस दृष्टि से छात्र आंदोलनों का भारतीय लोकतंत्र में अपना विशेष महत्व रहा है। छात्र समाज का वह वर्ग है, जो देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, फीस, छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालयों की व्यवस्था और भविष्य की अनिश्चितता जैसे मुद्दे जब छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करते हैं, तो उनकी आवाज को सुना जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

छात्रों की आवाज को राजनीतिक समर्थन मिलना अपने आप में लोकतंत्र की कमजोरी नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। राजनीतिक दल जनसमस्याओं को उठाते हैं, आंदोलनों के साथ खड़े होते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब वास्तविक छात्र मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और आंदोलन किसी राजनीतिक दल के शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन जाता है। यहीं से प्रशन उठता है कि छात्र आंदोलन को समर्थन देना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्या छात्रों की आवाज का राजनीतिक अपहरण भी लोकतांत्रिक अधिकार माना जा सकता है? भारत के इतिहास में छात्र आंदोलनों की लंबी परंपरा रही है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक आंदोलनों तक विद्यार्थियों ने अपनी भूमिका निभाई है। कई बड़े जनआंदोलनों में छात्रों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर व्यवस्था को चुनौती दी और सामाजिक बदलाव की दिशा तैयार की। इसलिए आज यदि छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करते हैं, तो उसे केवल राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं होगा। उनकी समस्याओं की वास्तविकता को समझना आवश्यक है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की भूमिका को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनभावनाओं को राजनीतिक विमर्श में बदलते हैं। वे आंदोलनकारियों की आवाज संसद और विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं। वे सरकार को जवाबदेह बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। खतरा तब पैदा होता है जब छात्र आंदोलन का नेतृत्व, एजेंडा और दृश्य पूरी तरह राजनीतिक दलों के हाथ में चला जाए। तब आंदोलन छात्र समस्या से अधिक पार्टी कार्यक्रम दिखाई देने लगता है। आंदोलन की आत्मा छात्र हो और राजनीतिक दल उसका समर्थन करें, यह लोकतंत्र है। लेकिन आंदोलन की आत्मा राजनीतिक दल बन जाए और छात्र केवल चेहरा रह जाएं तो यह लोकतंत्र की गंभीर कमजोरी है। हाल के दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में छात्र और युवा आंदोलनों ने राजनीतिक बहस को प्रभावित किया है। दिल्ली हो, रांची हो या पटना। जहां भी युवा या छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, वहां राजनीतिक दलों की सक्रियता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। राजनीतिक दलों के लिए युवा वर्ग स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। युवा मतदाता भविष्य की राजनीति की दिशा तय करता है। इसलिए युवाओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है। लेकिन यहां लोकतंत्र के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। क्या राजनीतिक समर्थन छात्र आंदोलन की ताकत बढ़ा रहा है या धीरे-धीरे आंदोलन की स्वतंत्र पहचान को खत्म कर रहा है? यह प्रशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आंदोलन केवल सड़क पर नहीं होता है। कैमरा, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया आंदोलन की तस्वीर को कुछ ही मिनटों में पूरे देश तक पहुंचा देते हैं। आंदोलन में कौन-सा झंडा है, कौन-सा नारा है, कौन आगे चल रहा है और पुलिस की कार्रवाई कैसी है, ये सभी दृश्य राजनीतिक संदेश में बदल जाते हैं। ऐसे में प्रतीकों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय ध्वज भारत की संप्रभुता, एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। तिरंगे का अर्थ किसी राजनीतिक दल की विचारधारा, सरकार के समर्थन या विरोध से कहीं बड़ा है। राजनीतिक दल आते-जाते हैं। सरकारें बदलती हैं। विपक्ष सत्ता में आता है और सत्ता विपक्ष में जाती है। चुनाव परिणाम राजनीतिक समीकरण बदल देते हैं। लेकिन तिरंगा इन सभी राजनीतिक बदलावों से ऊपर राष्ट्र की पहचान का प्रतीक बना रहता है। इसलिए किसी राजनीतिक आंदोलन में राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल को लेकर विशेष संवेदनशीलता आवश्यक है। बुधवार को पटना में लोकभवन मार्च के दौरान पुलिस की पानी की बौछार के बीच प्रदर्शनकारियों के साथ राष्ट्रीय ध्वज के भीगते और गिरते हुए दृश्य ने इसी प्रश्न को सामने ला दिया है। यह केवल एक राजनीतिक घटना का दृश्य नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक की गरिमा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करने वाला प्रसंग भी था। यहां उद्देश्य किसी दल या प्रदर्शनकारी की नीयत पर अंतिम फैसला सुनाना नहीं होना चाहिए। असली सवाल यह है कि क्या राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में तिरंगे को ऐसे हालात में ले जाना उचित है, जहां उसके गिरने, घसीटने या अपमानजनक स्थिति में पहुंचने की आशंका हो? यदि उत्तर नहीं है, तो राजनीतिक दलों और आंदोलनों को इस विषय में अधिक जिम्मेदार होना ही होगा। राजनीतिक दलों के अपने झंडे और प्रतीक होते हैं। वे अपने संगठन, विचारधारा और राजनीतिक पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। यह अंतर केवल रंगों और डिजाइन का अंतर नहीं है। यह संवैधानिक और भावनात्मक अंतर है। राजनीतिक विरोध करना है तो पार्टी का झंडा उठाइए। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है तो पार्टी का बैनर लगाइए। अपनी विचारधारा का प्रचार करना है तो अपने राजनीतिक प्रतीकों का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को राजनीतिक आवरण बना देना उचित नहीं हो सकता है। आज यदि किसी राजनीतिक दल को विरोध प्रदर्शन में तिरंगे के इस्तेमाल से अतिरिक्त भावनात्मक और दृश्यात्मक लाभ मिलता है, तो कल दूसरा दल भी यही करेगा। फिर धीरे-धीरे राष्ट्रीय ध्वज राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन सकता है। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए शुभ नहीं होगी।

भारत में अक्सर राजनीतिक बहस इतनी तीखी हो जाती है कि राष्ट्र और सरकार के बीच का अंतर धुंधला पड़ जाता है। सरकार की आलोचना को राष्ट्र की आलोचना मानना गलत है। उसी तरह सरकार के विरोध को राष्ट्र-विरोध मानना भी लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित नहीं है। सरकार बदलेगी, नीतियां बदलेगी, राजनीतिक दल बदलेंगे, लेकिन राष्ट्र बना रहेगा। इसी प्रकार तिरंगा किसी सरकार का झंडा नहीं है। वह भारत गणराज्य का राष्ट्रीय ध्वज है। इसलिए उसे न तो सत्ता पक्ष की संपत्ति समझा जा सकता है और न विपक्ष के विरोध का औजार बनाया जा सकता है। यह सरल-सा सिद्धांत राजनीतिक दलों, आंदोलनों और नागरिकों और सभी को समझना होगा। राजनीति से पूरी तरह मुक्त छात्र आंदोलन की कल्पना शायद व्यावहारिक नहीं है। छात्र स्वयं लोकतांत्रिक समाज का हिस्सा हैं। उनमें राजनीतिक चेतना होना स्वाभाविक है। राजनीतिक दल भी छात्रों की समस्याओं को उठाएं, यह लोकतंत्र में स्वीकार्य है। लेकिन राजनीति का केंद्र छात्र समस्या होनी चाहिए, राजनीतिक लाभ नहीं। यदि परीक्षा व्यवस्था में खामी है, तो उस पर चर्चा हो। यदि रोजगार का संकट है, तो सरकार से सवाल पूछा जाए। यदि छात्रवृत्ति में देरी है, तो उसका समाधान मांगा जाए। यदि विश्वविद्यालयों में अव्यवस्था है, तो प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए। लेकिन यदि वास्तविक मुद्दा पीछे चला जाए और मंच पर केवल पार्टी के नेता, पार्टी का झंडा और राजनीतिक नारे रह जाएं, तो आंदोलन की विश्वसनीयता कमजोर होती है। छात्रों को भी यह समझना होगा कि उनकी ऊर्जा किसी राजनीतिक दल की रणनीति का ईंधन न बने। वे अपने मुद्दों पर स्पष्ट रहें और किसी भी दल से समर्थन लेते समय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। लोकतंत्र में प्रदर्शनकारियों की जिम्मेदारी है कि वे कानून और सार्वजनिक व्यवस्था का सम्मान करें। लेकिन राज्य की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। पुलिस को प्रदर्शन रोकने का अधिकार कानून के दायरे में है, लेकिन बल प्रयोग की हर कार्रवाई संतुलित, आवश्यक और अनुपातिक होनी चाहिए। खासकर जब प्रदर्शन में राष्ट्रीय ध्वज मौजूद हो, तब पुलिस और प्रशासन को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। पानी की बौछार, बैरिकेडिंग या अन्य उपायों के दौरान यदि राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर गिरता है, तो उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाना प्रशासन की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। लोकतंत्र में केवल प्रदर्शनकारियों से मर्यादा की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। सत्ता और सड़क, दोनों को लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करना होगा। आज आंदोलन की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग सड़क पर उतरे। एक तस्वीर, एक वीडियो या कुछ सेकंड का दृश्य पूरे राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर सकता है। पानी की बौछार में गिरता व्यक्ति, पुलिस से भिड़ते प्रदर्शनकारी, हाथ में तिरंगा लिए युवा या सड़क पर पड़ा राष्ट्रीय ध्वज, ऐसे दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से फैलते हैं। इन दृश्यों का भावनात्मक प्रभाव किसी लंबे भाषण से अधिक हो सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों को समझना होगा कि कैमरे के सामने किया गया हर कार्य इतिहास का हिस्सा बन सकता है। तिरंगा हाथ में लेना केवल फोटो खिंचवाने का विषय नहीं है। उसके साथ राष्ट्रीय सम्मान की जिम्मेदारी भी जुड़ी है।

लगता है कि अब समय आ गया है कि राजनीतिक दल स्वयं इस विषय में आचार-संहिता बनाएं। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल कब होगा, कैसे होगा और किन परिस्थितियों में नहीं होगा, इस पर स्पष्ट नियम होने चाहिए। इसी तरह छात्र संगठनों को भी अपने आंदोलन के लिए आचार-संहिता तैयार करनी चाहिए। आंदोलन शांतिपूर्ण हो। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हो। पुलिस के साथ टकराव को लक्ष्य न बनाया जाए और वास्तविक छात्र मुद्दे केंद्र में रहे। ऐसी मर्यादा आंदोलन को कमजोर नहीं करती है, बल्कि उसकी नैतिक शक्ति बढ़ाती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। युवा केवल वोटर नहीं हैं, वे देश के भविष्य के निर्माता हैं। इसलिए युवाओं की आवाज को राजनीतिक दलों द्वारा सुना जाना चाहिए, लेकिन उन्हें राजनीतिक मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। युवा यदि बेरोजगारी पर सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब चाहिए। यदि परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हैं तो सुधार चाहिए। यदि शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल करते हैं तो नीति में बदलाव चाहिए।

दोहे - नंदिता की कलम से..

नदिता माजी शर्मा

औरों की सुनकर कभी, लोगों को मत तोल।
हर पहलू को जाँच ले, तब जाकर कुछ बोल।।१।।
सच्ची मैत्री बोलती, सुख-दुख मिलकर बांट।
सही कर्म पर साथ दे, गलत कर्म पर डांट।।२।।
देखे हैं संसार ने, कितने नाना रोग।
सबसे दुष्कर आज भी, क्या बोलेंगे लोग।।३।।
क्षणभंगुर हैं आप, मैं, क्षणभंगुर सब लोग।
क्षणभंगुर हर कामना, क्षणभंगुर सब भोग।।४।।
खोजो अपने आप में, जीवन का अभिप्रेत।
दिन-प्रतिदिन जीवन सदा, फिसले बनकर रेत।।५।।
अहंकार से है भरा, जिनके मन का कोष।
औरों पर वे थोपते, निज करनी के दोष।।६।।
मन में हो सद्भावना, बसे मनन में बुद्ध।
प्रथम चयन बस शांति हो, अंतिम विकल्प युद्ध।।७।।
गगरी भरती पाप की, संचित हों जब पाप।
चरम बिन्दु को जब छुए, फूटे अपने आप।।८।।
घातक दुनिया रील की, बाँध रही निज खूँट।
सही रहे तो है सुधा, गलत विषैले घूँट।।९।।

चीनी के दामों की अचानक बढ़ोतरी: सरकार और पीएमओ की निगरानी व्यवस्था पर भी उठने चाहिए सवाल

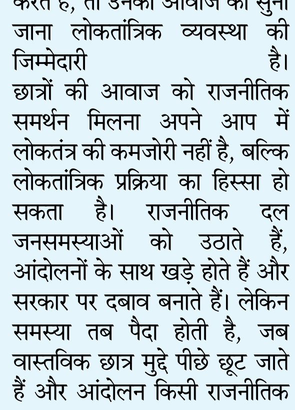

आचार्य अशोक चौधरी प्रियदर्शी

कटिहार, बिहार चीनी के दामों में अचानक आई तेजी ने एक बार फिर देश के मध्यमवर्गीय और निम्न-मध्यमवर्गीय परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। घरेलू बजट पहले से ही खाद्य पदार्थों की कीमतों के दबाव में है और ऐसे समय में चीनी, लहसुन, प्याज तथा चावल जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के दाम में वृद्धि सामान्य परिवार के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन जाती है। सवाल केवल यह नहीं है कि चीनी महंगी क्यों हुई, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अचानक होने वाली ऐसी तेजी को समय रहते नियंत्रित करने के लिए हमारी निगरानी और आपूर्ति व्यवस्था कितनी प्रभावी है? चीनी कोई विलासिता की वस्तु नहीं है। भारत के करोड़ों परिवारों की दैनिक जरूरतों में इसका स्थान है। चाय से लेकर मिठाई तक और घरेलू उपयोग से लेकर छोटे कारोबार तक चीनी की मांग बनी रहती है। इसलिए इसके मूल्य में मामूली वृद्धि भी व्यापक स्तर पर असर डालती है। यदि बाजार में चीनी की कीमत अचानक बढ़ती है तो इसका असर केवल रसोई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि चाय, मिठाई, बिस्कुट, पेय पदार्थ, होटल-रेस्तरां और अनेक खाद्य उत्पादों की लागत पर भी पड़ता है। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति को केवल बाजार की सामान्य गतिविधि कहकर छोड़ देना उचित नहीं होगा। सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि कीमतों में तेजी के पीछे वास्तविक कारण क्या हैं। क्या उत्पादन में कमी है? क्या गन्ने की उपलब्धता प्रभावित हुई है? क्या मिलों के पास पर्याप्त स्टॉक है? क्या निर्यात अथवा घरेलू आपूर्ति के बीच कोई असंतुलन पैदा हुआ है? क्या थोक और खुदरा बाजार के बीच असामान्य मूल्य-अंतर है? या फिर कहीं जमाखोरी और कृत्रिम कमी पैदा करने का प्रयास तो नहीं हो रहा? यही वह बिंदु है जहां सरकार और विशेष रूप से नीति-निर्माण एवं निगरानी तंत्र की सक्रियता महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी सरकार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह बाजार में हर वस्तु का मूल्य स्वयं निर्धारित करे। भारत एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है और मांग तथा आपूर्ति के आधार पर कीमतों में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है। लेकिन आवश्यक वस्तुओं के मामले में सरकार का दायित्व केवल कीमत बढ़ जाने के बाद प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि संभावित संकट के संकेतों को पहले पहचानना भी है। चीनी के संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि भारत विश्व के प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में है। इसके बावजूद यदि घरेलू बाजार में अचानक कीमतों में तेज उछाल आता है तो उत्पादन, स्टॉक, मिलों की बिक्री, निर्यात, थोक व्यापार और खुदरा बाजार की पूरी श्रृंखला की समीक्षा आवश्यक हो जाती है। सरकार के पास कृषि, खाद्य आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और वाणिज्य से जुड़े अनेक संस्थागत तंत्र हैं। इन सभी के बीच बेहतर समन्वय ही ऐसी परिस्थितियों में प्रभावी समाधान दे सकता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हर मूल्यवृद्धि को किसी एक व्यक्ति, उद्योग या सरकार की साजिश मान लेना भी उचित नहीं होगा। बाजार की वास्तविक परिस्थितियों का वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक है। यदि उत्पादन लागत बढ़ी है तो उसका कारण समझना होगा। यदि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य देना है तो उसका असर चीनी की लागत पर पड़ेगा। यदि मिलों की लागत बढ़ी है तो उसकी भी गणना करनी होगी। लेकिन यदि लागत में मामूली वृद्धि के बावजूद खुदरा कीमत असामान्य रूप से बढ़ रही है तो बीच की आपूर्ति श्रृंखला में कहीं न कहीं समस्या की संभावना अवश्य जांची जानी चाहिए। मध्यमवर्ग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसकी आय और खर्च के बीच संतुलन लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। गरीब परिवारों के लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं सुरक्षा कवच का काम करती हैं, जबकि उच्च आय वर्ग पर खाद्य वस्तुओं की कीमतों का प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम पड़ता है। लेकिन मध्यमवर्ग ऐसा वर्ग है जो अपनी अधिकांश आवश्यकताओं का खर्च स्वयं वहन करता है। उसकी आय सीमित होती है, बचत की क्षमता सीमित होती है और अचानक बढ़ने वाली खाद्य कीमतें उसके पूरे घरेलू बजट को प्रभावित करती हैं।

इसीलिए चीनी की कीमत में वृद्धि को केवल एक वस्तु की महंगाई के रूप में देखना सही नहीं होगा। यह उस व्यापक आर्थिक दबाव का हिस्सा है जिसमें परिवारों को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन और अन्य आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यदि लहसुन 200 रुपये किलो तक पहुंचता है, प्याज 65 रुपये किलो होता है और चावल के 10 किलो पैकेट की कीमत में लगभग 200 रुपये की वृद्धि की शिकायत सामने आती है, तो सरकार के लिए इन अलग-अलग घटनाओं को अलग-अलग देखने के बजाय समग्र खाद्य-मुद्रास्फीति की तस्वीर पर नजर रखना जरूरी हो जाता है।

यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि अलग-अलग राज्यों और शहरों में कीमतें अलग हो सकती हैं। स्थानीय परिवहन लागत, मंडी व्यवस्था, मौसम, उत्पादन क्षेत्र से दूरी और स्थानीय मांग के कारण कीमतों में अंतर स्वाभाविक है। इसलिए सोशल मीडिया या स्थानीय बाजार की किसी एक कीमत को पूरे देश की स्थिति का प्रतिनिधि मान लेना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि कई क्षेत्रों में एक जैसी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है तो निश्चित रूप से गंभीर जांच की आवश्यकता है। मोदी सरकार के संदर्भ में इस विषय को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित करना भी समस्या का समाधान नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा, महंगाई नियंत्रण, डिजिटल निगरानी, आपूर्ति श्रृंखला और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के क्षेत्र में कई संस्थागत व्यवस्थाएं विकसित की हैं। ऐसे में अपेक्षा यह होनी चाहिए कि उन्हीं व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। सरकार की आलोचना का उद्देश्य सरकार को कमजोर करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाना होना चाहिए। प्रश्न प्रधानमंत्री कार्यालय से भी है—आखिर इतनी बड़ी आबादी वाले देश में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाले अचानक बदलाव की वास्तविक समय में निगरानी किस स्तर तक हो रही है? यदि किसी वस्तु का थोक मूल्य तेजी से बढ़ता है तो उसकी सूचना संबंधित मंत्रालयों तक कितनी जल्दी पहुंचती है? यदि किसी जिले में किसी आवश्यक वस्तु का खुदरा मूल्य सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है तो क्या कोई स्वतः सक्रिय होने वाली निगरानी व्यवस्था है? यदि नहीं है तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जानी चाहिए? सरकार को केवल मूल्य नियंत्रण के पारंपरिक उपायों पर निर्भर रहने के बजाय आधुनिक डेटा आधारित निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए। देश के विभिन्न राज्यों की मंडियों, थोक बाजारों और खुदरा बाजारों से प्राप्त आंकड़ों का वास्तविक समय में विश्लेषण किया जा सकता है।

संक्षिप्त समाचार

नई बीएमडब्ल्यू एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस लॉन्च

रांची। नई बीएमडब्ल्यू एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस को लॉन्च किया गया। बीएमडब्ल्यू एक्स1 देश की सबसे सफल लग्जरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल है और अब इसका नया अवतार लॉन्ग व्हीलबेस पेश किया गया है, जिसमें मिलती है बेहतर प्रदर्शन के साथ कई डिजिटल अपग्रेड्स।नई बीएमडब्ल्यू एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस का पेट्रोल वेरिएंट बीएमडब्ल्यू ग्रुप प्लांट चेन्नई में स्थानीय रूप से उत्पादित किया जाता है और आज से बीएमडब्ल्यू डीलरशिप पर इसकी बुकिंग की जा सकती है। हरदीप सिंह बरार, प्रेसिडेंट और बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने कहा, बीएमडब्ल्यू एक्स1 भारत में एक शानदार सफलता की कहानी रही है और लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में अपनी बढ़त बनाए हुए है। नई बीएमडब्ल्यू एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस एक दमदार नई पेशकश के साथ इस बढ़त को और आगे बढ़ाती है। ज्यादा जगह, ज्यादा आराम, ज्यादा टेक्नोलॉजी और ज्यादा शानदार मौजूदगी। अपने सेगमेंट की सबसे लंबी, सबसे ऊंची और सबसे चौड़ी कार होने के नाते, यह ऐसी जगह और पिछली सीट पर ऐसा आराम देती है जो वाकई बेमिसाल है, साथ ही यह बीएमडब्ल्यू की पहचान बनी फुर्ती, परफॉर्मेंस और ड्राइविंग के मजे को भी बरकरार रखती है। इस लॉन्च के साथ, हम न केवल इस मॉडल की आकर्षक पहचान को बढ़ा रहे हैं, बल्कि हम उस उम्मीद को भी एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं जो ग्राहक इस क्लास की लग्जरी एसयूवी से करते हैं।

क्रॉम्पटन ने पेश किया क्रॉम्पटन रायन

रांची। भारत की अग्रणी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनियों में शामिल क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपनी नई मास्टर ब्रांड आइडेंटिटी का अनावरण किया। यह क्रॉम्पटन 2.0 के तहत कंपनी के अगले चरण की शुरुआत को दर्शाता है, जिसमें कंपनी खुद को एक इनोवेशन-लेड और कंज्यूमर-सेंट्रिक बिजनेस के रूप में आगे बढ़ा रही है। पिछले एक दशक में क्रॉम्पटन ने टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट इनोवेशन में लगातार निवेश करते हुए अपनी पारंपरिक प्रमुख श्रेणियों से आगे विस्तार किया है। इस अवसर पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ, प्रोमीत घोष ने कहा कि क्रॉम्पटन रायन का लॉन्च हमारी प्रीमियमाइजेशन जर्नी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और सुपर-प्रीमियम सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की हमारी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। हमारे डेडिकेटेड सुपर-प्रीमियम ब्रांड के रूप में क्रॉम्पटन रायन सोच-समझकर किए गए डिजाइन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और उपभोक्ताओं की बदलती आकांक्षाओं के अनुरूप सॉल्यूशंस के जरिए बेहतर अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

आजसू पार्टी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक 27 अगस्त को, सुदेश महतो करेंगे अध्यक्षता

रांची। आजसू पार्टी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक 27 अगस्त, गुरुवार को सुबह 10 बजे केंद्रीय कार्यालय, हरमू में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो करेंगे। आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत ने बताया कि बैठक में पार्टी के सभी प्रमंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक, विधानसभा क्षेत्रों के BLA-1, नवनियुक्त युवा आजसू प्रभारी तथा विभिन्न जिलों के नामित पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में राज्य के सभी जिलों से पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इस दौरान संगठन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के साथ गांव, पंचायत और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। डॉ. भगत ने कहा कि यह बैठक महज संगठनात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि पार्टी की राजनीतिक दिशा, वैचारिक प्रतिबद्धता और आगामी संघर्ष की कार्ययोजना को जमीन पर उतारने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन, स्थानीय अधिकार, रोजगार, शिक्षा, युवाओं का भविष्य और झारखंड के संसाधनों पर राज्य के लोगों के अधिकार जैसे मुद्दे पार्टी के राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में रहेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में झारखंड के सवालों पर स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण के साथ मजबूत जमीनी संगठन भी जरूरी है। कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा और उन्हें राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बनाना होगा। बैठक में BLA-1 की भूमिका, सदस्यता विस्तार, युवा संगठन की सक्रियता, बूथ स्तर की तैयारी, जनसरोकार से जुड़े मुद्दों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। डॉ. भगत ने कहा, "आजसू पार्टी के लिए संगठन पदों का ढांचा नहीं, बल्कि संघर्ष का आधार है। जिस दिन हमारा संगठन गांव के अंतिम व्यक्ति के सवाल के साथ मजबूती से खड़ा होगा, उसी दिन झारखंड के अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई निर्णायक ताकत हासिल करेगी।" उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होकर संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

थाना क्षेत्र में चोरों का बढ़ा आतंक घर के पास खड़ा ट्रेक्टर ट्राली हुई चोरी

मयूरहंड (चतरा)। थाना क्षेत्र के सिंदुवारी निवासी रमाकांत पाण्डेय पिता कैलेश्वर पाण्डेय की ट्रेक्टर ट्राली चोरों ने सोमवार रात को चुरा लिया।पीड़ित द्वारा बताया गया कि महेंद्रा कंपनी की 475 मॉडल ट्रेक्टर जिसका नंबर JH02 BP 2446 नित्य दिन की भांति रात्रि में भी अपने घर के बगल में खड़ा किया हुआ था।जो रात्रि लगभग 11 बजे तक थी पर सुबह उठने पर देखा तो ट्रेक्टर ट्राली नहीं था। जिसके बाद पीड़ित द्वारा अपने स्तर से काफी खोजबीन की गई पर कहीं पता नहीं चला। जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मयूरहंड थाना में आवेदन दिया। पुलिस अपने स्तर से चोरी हुई ट्रेक्टर की खोजबीन शुरू कर दिया है। पुलिस द्वारा संभावित मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच में जुटी है।

सिख समाज की समस्याओं पर मंथन, ज्योति सिंह माथारू को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाने की मांग

नई सोच एक्सप्रेस

रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय कार्यालय में मंगलवार को राज्यभर के सिख समाज के प्रतिनिधियों, गुरुद्वारा प्रबंधकों एवं पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह माथारू ने की। इसमें सिख समाज की विभिन्न समस्याओं, अधिकारों और सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय मौजूद रहे। आयोजक ज्योति सिंह माथारू ने अतिथियों का बुके एवं माला पहनाकर स्वागत किया। **बच्चों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर दें जोर : केशव महतो कमलेश** प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने ज्योति सिंह माथारू के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे अल्पसंख्यक समाज, विशेषकर सिख समाज की समस्याओं को लेकर लगातार गंभीरता से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और राहत का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सिख समाज से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सिख समाज अपने पुरुषार्थ और मेहनत के बल पर अपनी अलग पहचान रखता है। समाज की समस्याओं और मांगों को राज्य सरकार के समक्ष मजबूती से रखने का उन्होंने भरोसा दिलाया। कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं माथारू : सुबोध कांत सहाय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि ज्योति सिंह माथारू लगातार राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर अल्पसंख्यक समाज की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने माथारू को कांग्रेस का पुराना, निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए उनके जनसेवा कार्यों की सराहना की। **हर स्तर पर संघर्ष के लिए तैयार : ज्योति सिंह माथारू** ज्योति सिंह माथारू ने सभी अतिथियों और प्रतिनिधियों का आभार जताते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज के हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए वे हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों की सेवा के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। माथारू को आयोग का अध्यक्ष बनाने की उठी मांग बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से आए सिख समाज के प्रतिनिधियों एवं गुरुद्वारा प्रबंधकों ने सर्वसम्मति से ज्योति सिंह माथारू को झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई। प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज की समस्याओं को मजबूती से उठाया जा रहा है और समाज के लोगों में विश्वास बढ़ा है। बैठक में तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के पूर्व महासचिव शैलेंद्र सिंह, साकची गुरुद्वारा के प्रधान निशांत सिंह, गुरमुख सिंह मुखी, राजेंद्र सिंह चहल, अकाली दल के प्रधान रविंद्र सिंह, आनंद सलूजा, डी.एस. नरुला, हरपाल सिंह हीरे, सतपाल सिंह, हरचरण सिंह सिद्धू, बेरमो से गुरमीत सिंह, परमजीत सिंह सेठी, परमजीत सिंह, ट्विंडर सिंह, हरजीत सिंह, परमजीत सिंह चन्ना, रिंकू सिंह, तारा सिंह, हरमीत सिंह, हरभजन सिंह, जसपाल सिंह पधरी, प्रताप सिंह, कुशल सलूजा, रोमन सिंह, संदीप सिंह, राजवंत सिंह मारवाह सहित विभिन्न जिलों के गुरुद्वारा प्रबंध समितियों के अध्यक्ष, सचिव एवं बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग उपस्थित रहे।

छात्रों पर एकतरफा कार्रवाई के विरोध में सीओ कार्यालय पहुंचे बाबूलाल मरांडी, JMM कार्यकर्ताओं पर FIR की मांग

नई सोच एक्सप्रेस

रांची। जेपीएससी एवं जेएससी-सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मंगलवार को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रांची सदर अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार और मारपीट करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार की कठपुतली बनने के बजाय कानून और विधि सम्मत तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान दंडाधिकारी ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए छात्रों पर मुकदमा दर्ज कराया, जबकि छात्रों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने और कार्यक्रम में विघ्न डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि छात्र पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन कर रहे थे। इस दौरान जिन लोगों ने कार्यक्रम में बाधा डाली और छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। मरांडी ने कहा कि घटना से संबंधित कई वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिनसे पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि यदि संबंधित दंडाधिकारी द्वारा दोषी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो भाजपा कार्यकर्ता उनके कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। मरांडी ने झारखंड में प्रशासनिक तंत्र पर राजनीतिक दबाव का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों को कानून के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को दबाने के बजाय उनकी शिकायतों और मांगों पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए। गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी ने 24 अगस्त को ही चेतावनी दी थी कि यदि कथित रूप से JMM कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो 25 अगस्त को संबंधित मजिस्ट्रेट के कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, योगेंद्र प्रताप सिंह, वरुण साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मनुस्मृति के बचाव से भाजपा की महिला-विरोधी सोच उजागर : विजय शंकर नायक

नई सोच एक्सप्रेस

रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने मनुस्मृति को लेकर भाजपा नेताओं की कथित पैरवी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि वह डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान के साथ खड़ी है या मनुस्मृति की असमानतावादी सामाजिक सोच के साथ। नायक ने कहा कि महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के सवाल पर दूसरे धर्मों की कुरीतियों का हवाला देना मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। सामाजिक बुराई चाहे किसी भी परंपरा में हो, उसका विरोध होना चाहिए। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया था, तब उनसे दूसरे धर्मों की कुरीतियों का हिसाब नहीं मांगा गया था। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के विभिन्न श्लोकों की व्याख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आधुनिक भारत के संवैधानिक मूल्यों से ऊपर किसी भी ऐसी सामाजिक अवधारणा को नहीं रखा जा सकता, जो महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को सीमित करती हो। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, समान अवसर, महिलाओं की भागीदारी तथा वंचित वर्गों की सत्ता और संसाधनों में हिस्सेदारी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में नागरिकों के अधिकार जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि संविधान से सुनिश्चित होते हैं और सभी नागरिक बराबर हैं। विजय शंकर नायक ने भाजपा से सवाल किया कि क्या वह महिलाओं को स्वतंत्र नागरिक के रूप में समान अधिकार देने के पक्ष में है? क्या जाति और जन्म के आधार पर असमानता स्वीकार्य है? और क्या भाजपा डॉ. आंबेडकर के संविधान को सर्वोच्च मानती है? उन्होंने कहा कि महिला सम्मान केवल नारों से नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक स्वतंत्रता और समान अधिकारों से सुनिश्चित होगा। कांग्रेस संविधान, सामाजिक न्याय और महिला समानता के सवाल पर पीछे नहीं हटेगी। मनुवादी सोच को लोकतंत्र और संविधान से ऊपर रखने की किसी भी कोशिश का राजनीतिक विरोध किया जाएगा।

हेमंत कैबिनेट के बड़े फैसलेः 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ेंगी

नई सोच एक्सप्रेस

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुलिस, आपदा प्रबंधन और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में 100 नए विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। वहीं सरकारी स्कूलों की कक्षा छह से 12 तक की छात्राओं को हर माह अधिकतम 10 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 124.38 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली। **मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी एमबीबीएस और पीजी सीटेंः** कैबिनेट ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर के उन्नयन के लिए 393.91 करोड़ रुपये तथा शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के लिए 495.03 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी। इन योजनाओं के तहत एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने और पीजी सीटें बढ़ाने का प्रावधान है। इसके अलावा धनबाद में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के उन्नयन के लिए 275.18 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई। **100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयः** आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 721 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। **छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिनः** सरकारी विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक अध्ययनरत छात्राओं के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक छात्रा को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना पर 124 करोड़ 37 लाख 96 हजार 150 रुपये खर्च होंगे। **606 थानों में लगेंगे 9006 सीसीटीवी कैमरेः** राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी व्यवस्था मजबूत करने के लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके तहत राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9006 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। **स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की संविदा नियुक्तिः** सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई। हालांकि, गैर-शैक्षणिक चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का भी निर्णय लिया गया। **पांच नए प्रखंडों में बालिका आवासीय विद्यालयः** राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। भवन निर्माण समेत इसके लिए 49.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। **सड़कों और पुलों के लिए करोड़ों की मंजूरीः** कैबिनेट ने विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण की कई योजनाओं को स्वीकृति दी। मनोहरपुर क्षेत्र में पिंडी से गीरू-गुदड़ी मार्ग के लिए 114.01 करोड़ रुपये, रामगढ़ में बरलंगा-गोला-मुरी मार्ग के लिए 56.85 करोड़ रुपये, गिरिडीह में बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ मार्ग के लिए 30.46 करोड़ रुपये, चाईबासा में असुरा- कुमारडुंगी मार्ग के लिए 29.87 करोड़ रुपये तथा चतरा में हजारीबाग-कटकमसाण्डी-चतरा मार्ग के सुधार के लिए 25.53 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। **तोपचांची झील का होगा सौंदर्यीकरणः** धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए PPP मॉडल पर 184.29 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। परियोजना Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) मॉडल पर विकसित की जाएगी। **रोजगार और छात्र हित से जुड़े फैसलेः** कैबिनेट ने झारखंड में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना को मंजूरी दी। साथ ही झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति-2026 तथा झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन को स्वीकृति दी गई। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन का फैसला भी लिया गया। **अन्य महत्वपूर्ण निर्णयः** मंत्रिपरिषद ने वज्रपात और ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने, झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक-2026 के प्रारूप को मंजूरी देने, निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित जमा राशि वापस करने, ग्रामीण पुलों के रख-रखाव के लिए झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 लागू करने तथा पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के बाद वनभूमि को राजस्व भूमि में बदलने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट ने पांच केंद्रीय कारागारों में Open/Semi Open Barrack की स्थापना, आवासीय विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों की सेवा अवधि विस्तार तथा 12 पूर्व संविदा आधारित कनीय अभियंताओं के सेवा नियमितीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की।

MMDR बिल झारखंड की आर्थिक और संघीय स्वायत्तता पर सीधा हमला : सुबोध कांत सहाय

नई सोच एक्सप्रेस

» पूर्व केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार से पूछे 10 सवाल, कहा—झारखंड के खनिज और जमीन पर पहला अधिकार झारखंड की जनता का

रांची। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने मंगलवार को कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में MMDR संशोधन विधेयक को झारखंड के आर्थिक हितों, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों और संघीय ढांचे पर गंभीर हमला बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से 10 सवाल पूछते हुए कहा कि झारखंड की जमीन और खनिज संपदा से होने वाले राजस्व पर राज्य का उचित अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि झारखंड देश को कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट समेत बहुमूल्य खनिज संसाधन देता है, लेकिन खनिज संपदा से होने वाले राजस्व के मामले में राज्य के अधिकार सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के 2026-27 के बजट में मिनिरल बियरिंग लैंड सेस से करीब 14,000 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान है। ऐसे में इस संभावित राजस्व पर रोक या सीमा लगाने की स्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा, केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस राज्य की जमीन से खनिज निकलता है और जिसका पर्यावरणीय एवं सामाजिक बोझ भी राज्य की जनता उठाती है, वहां राजस्व संबंधी निर्णयों में राज्य की भूमिका सीमित क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल खनन कानून का विषय नहीं, बल्कि झारखंड की आर्थिक और संघीय स्वायत्तता का सवाल है। सहाय ने कहा कि खनन प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास और रोजगार के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होती है। यदि राज्य के राजस्व स्रोत कमजोर होंगे तो इसका सबसे अधिक असर इन्हीं क्षेत्रों पर पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि पुराने बकाये को समाप्त करने का प्रावधान क्यों लाया गया है और राज्यों के वित्तीय अधिकारों को सीमित करने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने झारखंड के भाजपा सांसदों से भी स्पष्ट रुख अपनाने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें जनता को बताना चाहिए कि वे झारखंड के संभावित 14 हजार करोड़ रुपये के राजस्व और राज्य के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संसद में आवाज उठाएंगे या नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खनिज संपदा झारखंड की धरती से निकलती है, इसलिए उसके लाभ में सबसे पहला और न्यायसंगत हिस्सा झारखंड की जनता का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड देश को खनिज दे सकता है, लेकिन बदले में बेरोजगारी, विस्थापन, प्रदूषण और पिछड़ेपन का बोझ नहीं उठाना चाहिए। सुबोध कांत सहाय ने झारखंड के सभी राजनीतिक दलों और विशेषकर राज्य के भाजपा सांसदों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के आर्थिक हित और संघीय अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने केंद्र सरकार से मंदिर संशोधन में झारखंड के हितों को स्पष्ट रूप से सुरक्षित करने तथा संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई की ठोस गारंटी देने की मांग की। प्रेस वार्ता में राकेश सिन्हा, सोनल शांति, कमल ठाकुर और उज्जल तिवारी उपस्थित थे।

MMDR संशोधन पर कांग्रेस के विरोध को लेकर भाजपा का पलटवार

नई सोच एक्सप्रेस

रांची। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाईक ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय द्वारा MMDR संशोधन अधिनियम को लेकर लगाए गए आरोपों पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों में तथ्यों से अधिक राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश दिखाई देती है। अशोक बड़ाईक ने कहा कि MMDR संशोधन किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के खनिज क्षेत्र को पारदर्शी, व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्यों के वैधानिक अधिकार और खनिज राजस्व सुरक्षित हैं, तो कांग्रेस जनता के बीच भ्रम क्यों फैला रही है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा बार-बार 14 हजार करोड़ रुपये के संभावित राजस्व का उल्लेख किए जाने पर कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह आंकड़ा किस आधार पर है और इसका MMDR संशोधन से वास्तविक कानूनी संबंध क्या है। उन्होंने कहा कि केवल बड़ी संख्या का उल्लेख कर देने से वह सुनिश्चित या संवैधानिक राजस्व नहीं बन जाती। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि खनिज क्षेत्र से प्राप्त राजस्व का बड़ा हिस्सा राज्यों को प्राप्त होता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा झारखंड का पूरा खनिज राजस्व छीन लिए जाने का प्रचार भ्रामक है। उन्होंने कांग्रेस से खनन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास और रोजगार की स्थिति का भी हिसाब देने को कहा। अशोक बड़ाईक ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले का हवाला देकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए कानून में आवश्यक स्पष्टता और समान व्यवस्था सुनिश्चित करना संघीय ढांचे पर हमला नहीं, बल्कि कानूनी एवं प्रशासनिक स्पष्टता की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को झारखंड की खनिज संपदा की इतनी चिंता है तो उसे धनबाद, चतरा, हजारीबाग समेत अन्य खनन क्षेत्रों में अवैध खनन और कोयला कारोबार के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध खनन, सिंडिकेट और खनिज माफिया के खिलाफ सख्ती होने से कांग्रेस और झामुमो में बेचैनी है। उन्होंने राज्य में कोयले पर बढ़े सेस और विभिन्न उपकरों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे उद्योग और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का भी राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को नारे नहीं, बल्कि दस्तावेज और स्पष्ट हिसाब चाहिए। अशोक बड़ाईक ने कांग्रेस के भाजपा सांसदों से जुड़े सवालों पर कहा कि भाजपा के सांसद झारखंड के साथ भी हैं और देश के साथ भी। भाजपा की राजनीति राष्ट्रहित और राज्यहित के संतुलन पर आधारित है। उन्होंने जेपीएससी-जेएससी भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा ने छात्रों के हित में शुरू से स्वतंत्र जांच की मांग की, जबकि कांग्रेस और झामुमो ने छात्र आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर चुप रहने वाले लोगों को आज झारखंड के आर्थिक अधिकारों का सबसे बड़ा प्रहरी बनने का नैतिक अधिकार नहीं है। अशोक बड़ाईक ने कहा कि कांग्रेस यदि वास्तव में MMDR संशोधन को झारखंड के हितों के खिलाफ मानती है तो उसे कानून की एक-एक धारा पर तथ्यात्मक बहस करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के बीच जाकर MMDR कानून, राज्य के राजस्व, खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की वास्तविकता रखेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा झारखंड की जनता की है और भाजपा चाहती है कि इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और झामुमो खनिज के नाम पर भ्रम और आरोपों की राजनीति कर रहे हैं। बड़ाईक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का लक्ष्य खनिज क्षेत्र को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। यदि कांग्रेस को इससे परेशानी है तो उसे जनता को बताना चाहिए कि उसकी परेशानी कानून से है या उन रास्तों के बंद होने से, जिनसे भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता रहा है।

संक्षिप्त समाचार

करमा पंचायत सचिवालय में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जागरूकता

मयूरहंड। प्रखंड क्षेत्र के करमा पंचायत सचिवालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों को मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता एवं अन्य विवरणों की जांच करने तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आवश्यक सुधार कराने की जानकारी दी गई। बीडीओ मनीष कुमार ने पात्र मतदाताओं से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें। उन्होंने कहा कि सूची में किसी तरह की गलती होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज कराकर उसका सुधार कराया जा सकता है। अधिकारियों ने सभी पात्र नागरिकों से पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की।

सनराइज पब्लिक स्कूल में मनाया गया रक्षा बंधन उत्सव

टाटीझरिया(हजारीबाग)। प्रखंड क्षेत्र के खंभवा में अवस्थित सनराइज पब्लिक स्कूल में मंगलवार को विद्यालय परिवार में रक्षा बंधन उत्सव मनाया गया। उच्च कक्षा के लड़कियों ने राखी बनाकर अपने हस्तकला की निपुणता को दर्शाया वहीं निम्न कक्षा के छात्राओं ने भी उत्साह पूर्वक राखी खरीदकर लाई और सबों ने मिलकर अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी। इस अवसर पर बच्चों के बीच मिठाइयां भी बांटी गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनुज साव ने विद्यार्थियों को रक्षा बंधन के त्योहार के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि यह त्यौहार शुद्ध और पवित्र त्यौहार है। बहनों द्वारा भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। भाइयों ने बहनों को रक्षा करने का संकल्प दोहराया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार का ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर सोनी देवी,संजू देवी,पूजा कुमारी, गांगी कुमारी ,अदिति कुमारी,श्रुति रानी,आयुष गुप्ता,शौर्य उपाध्याय,श्लोक आरुष,रिया कुमारी,रौशनी कुमारी ,खुशबू कुमारी समेत अन्य उपस्थित थे।

पदमा में उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शनः 3 अवैध शराब भट्ठियां ध्वस्त, 3400 kg जावा-महुआ नष्ट

हजारीबाग। जिले में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला उपायुक्त हेमंत सती के निर्देश पर सोमवार को उत्पाद विभाग की टीम ने बरही अंचल अंतर्गत पदमा थाना क्षेत्र में बड़ी छापेमारी की। इस दौरान टीम ने तीन अवैध चुलाई शराब भट्ठियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग के नेतृत्व में चलाई गई इस मुहिम के तहत पदमा थाना क्षेत्र के दरजीचक जुड़, कुटीपिसी और पिंडारपुर में सघन छापेमारी की गई। मौके पर संचालित हो रहीं 3 अवैध चुलाई शराब भट्ठियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। बरामदगी और विनष्टीकरणः टीम ने 40 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त की। इसके साथ ही शराब बनाने के लिए तैयार करीब 3,400 किलोग्राम किण्वित (फर्मेंटेड) जावा-महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया। अवैध भट्ठियों के संचालन में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा इसमें संलिप्त आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बंशी यादव हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

चलकुसा (हजारीबाग)। चलकुसा थाना क्षेत्र के घोरबन्दा पंचायत, सलैयडीह से जुड़े बहुचर्चित बंशी यादव हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान घोरबन्दा निवासी उमेश यादव (39 वर्ष), पिता तेजो यादव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच के दौरान उमेश यादव को गिरफ्तार किया गया। इस हत्याकांड की तफ्तीश के दौरान चलकुसा पुलिस के दो जवानों की भी वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। वहीं, मृतक के परिजनों का कहना है कि मामले में नामजद बताए जा रहे कई अन्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। परिजनों के अनुसार प्रभु यादव, सुनील यादव, अर्जुन यादव, राजेन्द्र यादव, रामबोल यादव, नारायण यादव, सितेश्वर यादव, अनिल यादव, सुमित्रा देवी, चिंता देवी, रामसहाय यादव सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। बंशी यादव के परिजन लंबे समय से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। परिजनों ने पुलिस से मामले में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी कर जल्द न्याय दिलाने की मांग की है।

जनजातीय गौरव उत्सव में रक्तदान के क्षेत्र में निर्मल जैन सम्मानित

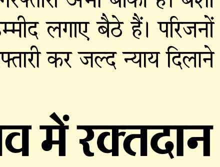

हजारीबाग। ठाकुरबाड़ी परिसर में 17 से 24 अगस्त तक आयोजित जनजातीय गौरव उत्सव के समापन समारोह में रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु ब्लड मैन निर्मल जैन को सम्मानित किया गया। यह उत्सव बिरसा मुंडा जन कल्याण योजना प्रचार अभियान के सौजन्य से महादेव स्मारक खादी ग्रामोद्योग मंडल द्वारा आयोजित किया गया था। समिति के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राज किशोर सामंत ने स्मृति चिन्ह देकर निर्मल जैन का सम्मान किया।कार्यक्रम में महिला एवं जनजातीय उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों के सुंदर स्टॉल लगाए गए थे, जिससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। समारोह के दौरान प्रतिदिन आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। कलाकारों में काफी उत्साह देखा गया और दर्शकों ने कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लिया।कार्यक्रम का संचालन समिति के मीडिया प्रभारी ने किया। उत्सव को सफल बनाने में कल्चरल ट्रस्ट के सचिव सुबोध कुमार सहित समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ सहयोग दिया।

नेत्रदान को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान, 41वें नेत्रदान पखवाड़े का शुभारंभ

नई सोच एक्सप्रेस

रांची। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को सदर अस्पताल रांची के 8वें फ्लोर स्थित ऑडिटोरियम में 41वें नेत्रदान पखवाड़ा-2026 का शुभारंभ किया गया। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य नेत्रदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, भ्रांतियों को दूर करना और अधिक से अधिक लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड शशि प्रकाश झा ने प्रतिभागियों को नेत्रदान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि नेत्रदान केवल दान नहीं, बल्कि मानवता का अनुपम उपहार है। मृत्यु के बाद भी किसी जरूरतमंद के जीवन में रोशनी लाई जा सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नेत्रदान का संकल्प लें और अपनी इच्छा के बारे में परिवार के सदस्यों को पहले से जानकारी दें। उन्होंने कहा कि अभियान को केवल विभागीय कार्यक्रम तक सीमित न रखकर जनभागीदारी का व्यापक अभियान बनाया जाएगा। विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, स्वास्थ्य संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, युवा संगठनों और सामाजिक संस्थाओं को इससे जोड़ा जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी नेत्रदान से संबंधित तथ्यपरक एवं सकारात्मक संदेश लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सिद्धार्थ सान्याल ने कहा कि नेत्रदान किसी के अंधकारमय जीवन में प्रकाश देने का संकल्प है। राज्य अंधापन नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. पंकज कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टि दोष नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कॉर्नियल अंधत्व सहित विभिन्न नेत्र रोगों की रोकथाम एवं उपचार के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए दान किए गए कॉर्निया की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद ने बताया कि व्यक्ति जीवनकाल में नेत्रदान की इच्छा व्यक्त कर सकता है, लेकिन नेत्र प्राप्ति की प्रक्रिया मृत्यु के बाद निर्धारित चिकित्सकीय एवं कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है। इसलिए परिवार को पहले से अपनी इच्छा की जानकारी देना जरूरी है। कार्यक्रम में डॉ. प्रभात कुमार, डॉ. विमलेश सिंह, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. आरके सिंह, डॉ. प्रतिश प्रणय, डॉ. सरिता लकड़ा समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। धन्यवाद ज्ञापन डीपीएम रांची प्रवीण कुमार ने किया, जबकि मंच संचालन डीपीसी रांची प्रीति चौधरी ने किया।

चार साल पुराने पित्त नली के स्टेंट और 70-80 पथरी का बिना चीर-फाड़ सफल इलाज

नई सोच एक्सप्रेस

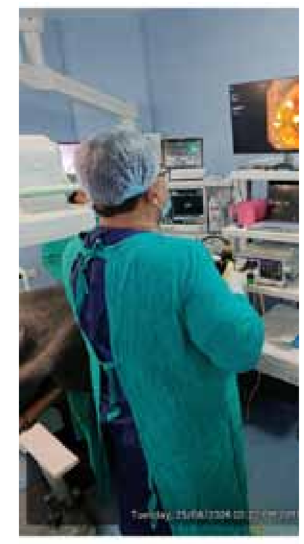

रांची। सदर अस्पताल रांची में गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. जयंत कुमार घोष ने पित्त की नली में चार वर्ष से फंसे स्टेंट, करीब 70-80 पथरी और कीचड़ से ग्रसित गंभीर मरीज का सफल इलाज किया। चिकित्सकों के अनुसार, मरीज को चार वर्ष पूर्व पित्त की नली में पथरी की समस्या थी। ईआरसीपी विधि से पथरी का उपचार कर स्टेंट लगाया गया था, जिसे एक-दो महीने के भीतर निकालना था, लेकिन निजी कारणों से मरीज समय पर स्टेंट नहीं निकलवा सका। हाल में तेज पेट दर्द और अत्यधिक पीलिया की शिकायत के बाद मरीज ने सदर अस्पताल में डॉ. जयंत कुमार घोष से संपर्क किया। जांच में चार वर्ष पुराना स्टेंट पित्त नली में ही पाया गया। इसके साथ बड़ी संख्या में पथरी और कीचड़ भी मौजूद था। डॉ. घोष और उनकी टीम ने बिना किसी चीर-फाड़ के ईआरसीपी एवं दूरबीन विधि से स्टेंट और पथरी को निकालकर मरीज का सफल उपचार किया। टीम में डॉ. वसुधा, डॉ. नीरज, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन शेषनाथ यादव, सिस्टर श्वेता, सिस्टर सरिता, ओटी टेक्नीशियन मोहित एवं सुरेश शामिल रहे। यह इलाज ओटी इंचार्ज डॉ. अखिलेश झा, उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश सिंह एवं सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद के सहयोग से संभव हुआ। चिकित्सकों ने बताया कि समय पर स्टेंट नहीं निकलवाने से गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।

देवेंद्र नाथ महतो का गिद्धौर में भव्य स्वागत,नौकरी बेचने के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी

नई सोच एक्सप्रेस

गिद्धौर। प्रखंड मुख्यालय ब्लॉक मोड में मंगलवार को गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय के ब्लॉक मोड़ पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का आगमन हुआ। उनके पहुंचते ही प्रखंड के युवाओं और स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया। लोगों ने फूल-माला पहनाकर और नारेबाजी कर उनका भव्य स्वागत किया।स्वागत के बाद ब्लॉक मोड़ के पास ही एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में बड़ी संख्या में छात्र, बेरोजगार युवा और ग्रामीण उपस्थित थे। सभी के हाथों में 'झारखंड में नौकरी बेचना बंद करो',छात्र एकता जिंदाबाद' और 'झारखंड राज्य जिंदाबाद' लिखे बैनर और पोस्टर थे।सभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज झारखंड में मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।नौकरियां बेची और खरीदी जा रही हैं।पेपर लीक हो रहे हैं,और योग्य छात्र दर-दर भटक रहे हैं।उन्होंने कहा,यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह पूरे झारखंड के छात्र और युवा की लड़ाई है। अगर हम आज एकजुट नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी।महतो ने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे जाति-धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएं।उन्होंने कहा कि छात्र संघ लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है,लेकिन सरकार इस पर कोई लगाम नहीं लगा रही है।चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाती और नौकरी की खरीद-बिक्री पर रोक नहीं लगाती है, तो पूरे झारखंड में छात्र संघ द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।कार्यक्रम के अंत में सभी ने एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। मौके पर गिद्धौर प्रखंड के दर्जनों युवा, छात्र और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।

सनातन संस्कृति सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने की कांवरिया सेवा

नई सोच एक्सप्रेस

गिद्धौर। सावन माह में शिवभक्तों की सेवा को लेकर गिद्धौर की सनातन संस्कृति सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत कुमरसार गांव में कांवरिया सेवा शिविर आयोजित कर डाक बम एवं अन्य कांवरियों की सेवा की। इस दौरान समिति के कार्यकर्ताओं ने शिवभक्तों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हुए सेवा कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई। कुमरसार गांव कांवरिया पथ का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यहां से प्रसिद्ध कुमरसार नदी भी होकर गुजरती है, जिसके कारण सावन के दौरान इस मार्ग से बड़ी संख्या में कांवरियों एवं डाक बमों का आवागमन होता है। गंगा जल लेकर विभिन्न शिवालयों की ओर बढ़ रहे श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सनातन संस्कृति सेवा समिति के कार्यकर्ता दिनभर तत्पर रहे। सेवा शिविर में थके-मांदे कांवरियों को शरबत, चाय और फल उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा पैदल यात्रा के दौरान होने वाली शारीरिक थकान और पैरों की तकलीफ को देखते हुए ठंडा तेल एवं दर्दनिवारक स्प्रे आदि की भी व्यवस्था की गई। कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सेवा को प्राथमिकता देते हुए लगातार उनकी सहायता की। कांवरिया सेवा में सनातन संस्कृति सेवा समिति के बिट्टू कुमार रावत, रॉकी कुमार, राकेश कुमार, ठाकुर अंकित, अंजेश कुमार, नीतीश कुमार गट्टू, संतोष पंडित, राजा रजक, पवन पंडित सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सावन माह में कांवरियों और डाक बमों की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य एवं सामाजिक-धार्मिक दायित्व का विषय है। शिवभक्तों की सेवा के माध्यम से समिति ने धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सेवा का संदेश भी दिया। कांवरिया पथ पर समिति के कार्यकर्ताओं की इस सेवा पहल की स्थानीय लोगों एवं श्रद्धालुओं ने सराहना की।

» शरबत, चाय, फल और दर्दनिवारक सामग्री से डाक बम व शिवभक्तों की हुई सेवा

अमेरिका में किसान पुत्र लखेंद्र दांगी ने रचा इतिहास, मयूरहंड का नाम किया रोशन

नई सोच एक्सप्रेस

चतरा। झारखंड के चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड अंतर्गत मधनिया गांव निवासी किसान पुत्र लखेंद्र दांगी ने अमेरिका की धरती पर अपनी प्रतिभा और मेहनत का परचम लहराते हुए गांव, प्रखंड और जिले का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। न्यूयॉर्क में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फ्लैगपोल (ध्वज स्तंभ) स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली टीम में लखेंद्र दांगी भी महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में शामिल रहे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद टीम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। **किसान परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय पहचानः** लखेंद्र दांगी एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। ग्रामीण परिवेश से निकलकर अमेरिका में अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा बनना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उनकी इस उपलब्धि ने यह साबित किया है कि प्रतिभा और मेहनत के सामने गांव और शहर की सीमाएं मायने नहीं रखतीं। **भारत की शान से जुड़ा ऐतिहासिक आयोजनः** न्यूयॉर्क में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय से जुड़े प्रमुख लोग एवं पदाधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम से संबंधित सूची में श्रीकांत अक्कापल्ली — FIA अध्यक्ष, अंकुर वैद्य — चेयरमैन, सृजल पारिख — संयुक्त सचिव, डॉ. अविनाश गुप्ता — बोर्ड सदस्य (रांची), अलोक कुमार — बोर्ड सदस्य (बिहार) तथा FIA के सौरिन पारिख — Immediate Past President (पूर्व अध्यक्ष) के नाम शामिल हैं। इसके अलावा पंकज प्रवीण और राघवेंद्र कुमार रॉय भी बिहार से जुड़े प्रतिनिधियों के रूप में सूची में दर्ज हैं। इस आयोजन में भारतीय समुदाय की भागीदारी ने विदेश की धरती पर भारतीय संस्कृति, एकता और राष्ट्रीय गौरव को भी प्रदर्शित किया। विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली टीम में झारखंड के चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड के लखेंद्र दांगी की मौजूदगी क्षेत्र के लिए विशेष उपलब्धि मानी जा रही है। **मयूरहंड के युवाओं के लिए बने प्रेरणास्त्रोतः** लखेंद्र दांगी की सफलता मयूरहंड प्रखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा का संदेश है। किसान परिवार और ग्रामीण परिवेश से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना इस बात का उदाहरण है कि मेहनत, लगन, प्रतिभा और सही अवसर के बल पर गांव का युवा भी दुनिया के मंच पर अपनी पहचान बना सकता है। उनकी इस उपलब्धि की खबर से मधनिया गांव सहित पूरे मयूरहंड प्रखंड और चतरा जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लखेंद्र दांगी ने अमेरिका की धरती पर उपलब्धि हासिल कर न केवल अपने परिवार का मान बढ़ाया, बल्कि मयूरहंड प्रखंड और चतरा जिले का नाम भी देश-दुनिया में रोशन किया है। लखेंद्र दांगी की यह उपलब्धि सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि एक किसान परिवार, मधनिया गांव, मयूरहंड प्रखंड और पूरे चतरा जिले के लिए गौरव का विषय है। विदेश की धरती पर भारत का मान बढ़ाने वाले मयूरहंड के इस लाल को क्षेत्रवासियों का सलाम।

» न्यूयॉर्क में फ्लैगपोल स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली टीम का रहे हिस्सा, मिला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र

कौलेश्वरी पहाड़ पर दर्दनाक हादसाः तालाब में डूबने से 22 वर्षीय युवक की मौत

नई सोच एक्सप्रेस

हंटरगंज/चतरा। कौलेश्वरी पहाड़ पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 22 वर्षीय युवक सम्राट सिंह की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना भगवान शिव मंदिर के समीप स्थित तालाब की है। मृतक पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के सिडिलिया गांव का निवासी बताया गया है। जानकारी के अनुसार, सम्राट सिंह भगवान भोलेनाथ और माता कौलेश्वरी के दर्शन-पूजन के लिए कौलेश्वरी पहाड़ पहुंचे थे। इसी दौरान शिव मंदिर के समीप स्थित तालाब में नहाने के क्रम में वह अचानक गहरे पानी में चले गए और डूब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। **सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालः** हादसे के बाद कौलेश्वरी धाम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं, वहां तालाब के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी बोर्ड और प्रशिक्षित बचाव दल की मौजूदगी क्यों नहीं थी? यदि तालाब का पानी गहरा और खतरनाक है, तो संवेदनशील हिस्से की घेराबंदी क्यों नहीं की गई? श्रद्धालुओं को खतरे से आगाह करने के लिए स्पष्ट सूचना बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? इन सवालों को लेकर अब प्रशासन और कौलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति की भूमिका पर चर्चा शुरू हो गई है। **समिति और प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवालः** कौलेश्वरी पहाड़ आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ-साथ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम जरूरी हैं। हादसे के बाद सवाल उठ रहा है कि भीड़भाड़ वाले दिनों में सुरक्षा कर्मियों और जिम्मेदार पदाधिकारियों की तैनाती क्यों नहीं रहती। साथ ही, तालाब जैसे संवेदनशील स्थानों पर स्थायी सुरक्षा व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई। **परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था सम्राटः** सम्राट सिंह की मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया गया कि वह परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उसके निधन से परिवार के सामने भावनात्मक संकट के साथ आर्थिक परेशानी भी खड़ी हो गई है। मृतक के पिता रामू सिंह सहित छोटे भाई प्रीतम और बहनें रिंकी व रिकू इस घटना से गहरे सदमे में हैं। जिस बेटे के सहारे परिवार की उम्मीदें टिकी थीं, उसकी अचानक मौत से पूरा परिवार मातम में डूब गया है। **हादसे के बाद अब जिम्मेदारी तय करने की मांगः** इस घटना ने एक बार फिर कौलेश्वरी धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर तालाब में खतरा था तो चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? यदि पानी गहरा था तो संवेदनशील हिस्से की घेराबंदी क्यों नहीं की गई? और अगर यहां लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है तो सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त तैनाती क्यों नहीं की गई? अब लोगों की नजर प्रशासन और कौलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति की अगली कार्रवाई पर है। जरूरत है कि घटना से सबक लेते हुए कौलेश्वरी धाम में तालाब सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर ठोस सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी दूसरे परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े।

» शिव मंदिर के समीप तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया सम्राट सिंह, परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था मृतक

विष्णुगढ़ एसडीपीओ कार्यालय का एसपी ने किया औचक निरीक्षण, दिए कड़े निर्देश

नई सोच एक्सप्रेस

विष्णुगढ़। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) कार्यालय, विष्णुगढ़ का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने कार्यालय की विभिन्न संचिकाओं, पंजियों और लंबित मामलों की गहराई से समीक्षा की तथा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपस्थित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीपीओ फौजान अहमद, चुरचू अंचल की पुलिस निरीक्षक विद्यावती ओहदार, विष्णुगढ़ थाना प्रभारी सुभाष सिंह, चरही थाना प्रभारी अजीत कुमार, टाटीझरिया थाना प्रभारी इंद्रजीत कुमार, आंगो थाना प्रभारी जानू कुमार और चुरचू थाना प्रभारी अश्वनी कुमार उपाध्याय मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एसपी ने कार्यालय की अपराध नियंत्रण संचिकाओं का जायजा लिया और थाना प्रभारियों को लंबित कांडों, वारंट और कुर्की-जब्ती के मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। विष्णुगढ़ अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों और अभियुक्तों की तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा गया। अवैध नशीले पदार्थों से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए एसपी ने संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने और क्षेत्र में नशे के खिलाफ व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया। क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को आम जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की हिदायत दी गई।

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 अगस्त को खेरागढ़ में होगा महादंगल

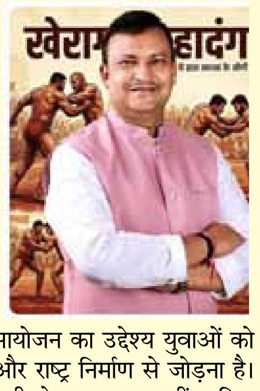

आगरा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को सुबह 10 बजे मंडी ग्राउंड, खेरागढ़ में दंगल-2026 का आयोजन किया जाएगा। महादंगल में देश-प्रदेश के पहलवान अपने दमखम, तकनीक और कुश्ती कौशल का प्रदर्शन करेंगे। नगर पंचायत खेरागढ़ के चेयरमैन सुधीर गर्ग 'गुड्डू' ने युवाओं से दंगल में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आयोजन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर कर खेल, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास, धैर्य, नेतृत्व और संघर्षशीलता जैसे गुण विकसित करने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि "युवा नशे से नहीं, खेल से जुड़ें और बुरी आदतों से नहीं, अपनी प्रतिभा से पहचान बनाएं।" आयोजन समिति ने क्षेत्रवासियों और खेलप्रेमियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है।

इंजीनियर रशीद ने बखियाकर स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए हाइड्रोलिक रोलर उपलब्ध कराया

हंदवाड़ा। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने अपनी पहल के तहत बखियाकर स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए एक हाइड्रोलिक रोलर उपलब्ध कराया है, जिसका औपचारिक उद्घाटन लंगेट के विधायक शेख खुर्शीद ने किया। इस उद्घाटन समारोह में स्थानीय खिलाड़ी, ग्राउंड कमेटी के सदस्य, युवा और अवामी इत्तेहाद पार्टी के समर्थक शामिल हुए। इस मौके पर खिलाड़ियों और ग्राउंड कमेटी के सदस्यों ने उपकरण उपलब्ध कराने के लिए इंजीनियर रशीद का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस पहल से मैदान पर खेल की स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। युवाओं ने कहा कि यह सुविधा स्थानीय खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, "जो काम किसी विधायक या मंत्री ने हमारे लिए नहीं किया, वह आज सांसद इंजीनियर रशीद ने कर दिखाया है। इस अवसर पर एडवोकेट माजिद बांदे, सांसद के पीआरओ लोन सज्जाद और एआईपी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

तुलसीदास भारतीय संस्कृति के संवाहक कवि : शशि भूषण

पटना। टी.पी.एस. कॉलेज, पटना में हिंदी विभाग के तत्वावधान में आयोजित तुलसीदास जयंती समारोह में मुख्य वक्ता डॉ. शशि भूषण चौधरी ने रामचरितमानस के प्रमुख पात्रों के चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं जीवन-मूल्यों की रक्षा और प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण कार्य किया। रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि परिवार और समाज को जोड़ने तथा मानवीय मूल्यों को स्थापित करने की प्रेरणा देने वाला महान ग्रंथ है। उन्होंने तुलसीदास को भारतीय संस्कृति का संवाहक कवि बताया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रो. तपन कुमार शाण्डिल्य ने अपने संबोधन में रामचरितमानस के प्रमुख पात्र हनुमान के चरित्र पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हनुमान निष्काम भक्ति, समर्पण, सेवा और कर्तव्यनिष्ठा के आदर्श हैं। उनके चरित्र में भक्ति के साथ साहस, विवेक, विनम्रता और कर्तव्यपरायणता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने राम और सुग्रीव की मित्रता स्थापित कराने में हनुमान की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि हनुमान का व्यक्तित्व आदर्श मित्रता, सेवा और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम का मंच संचालन हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. अश्विनी कुमार ने किया। उन्होंने कार्यक्रम के विभिन्न चरणों का प्रभावी संचालन करते हुए तुलसीदास और रामचरितमानस के सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व को रेखांकित किया। समारोह के अंत में डॉ. ओंकार पासवान ने धन्यवाद ज्ञापन किया तथा मुख्य वक्ता, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं उपस्थित छात्र-छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त किया। संगोष्ठी में महाविद्यालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. प्रशांत कुमार, डॉ. शशि शेखर कुमार सिंह, डॉ. चंद्रशेखर ठाकुर, डॉ. हंस कुमार सिंह, डॉ. सोनू कुमार, डॉ. नूतन कुमारी, डॉ. ऊषा किरण, डॉ. सुनीता कुमारी, डॉ. चांदनी कुमारी, डॉ. तरन्नुम नसरीन, डॉ. सुशोभन पलाधि सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की।

रक्षाबंधन पर बिहार में 300 करोड़ रुपये के कारोबार की संभावना : अशोक

पटना। रक्षाबंधन के अवसर पर इस वर्ष बिहार में लगभग 300 करोड़ रुपये के कारोबार होने की संभावना है। इसमें राखी, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिक सामान, मिठाई सहित विभिन्न उत्पादों का व्यापार शामिल है। यह जानकारी कैट बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने दी। अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन बिहार के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इस अवसर पर बाजार में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। विशेष रूप से राखी, मिठाई, आभूषण और उपहार सामग्री की मांग बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रधानमंत्री जी के ह्लोकल फॉर वोकलह्व और ह्ववोकल फॉर ग्लोबलह्व के आह्वान का असर बाजार में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिहार के बाजारों में स्वदेशी राखियों की मांग और उपलब्धता अधिक है, जबकि चीन सहित अन्य देशों से आने वाली राखियों की जगह स्थानीय कारीगरों और घरेलू उत्पादकों द्वारा तैयार राखियों को प्राथमिकता दी जा रही है। कैट बिहार अध्यक्ष ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने से न केवल स्थानीय व्यापार को मजबूती मिलती है, बल्कि छोटे कारीगरों, महिलाओं, लघु उद्यमियों और घरेलू उत्पादकों को भी रोजगार एवं आय के अवसर मिलते हैं। उन्होंने बिहार के लोगों से अपील की कि वे रक्षाबंधन के अवसर पर अधिक से अधिक स्वदेशी राखी एवं स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करें, ताकि त्योहार की खुशियों के साथ-साथ बिहार की अर्थव्यवस्था और स्थानीय व्यापार को भी मजबूती मिल सके।

महंत राजू नाथ चंदेल ने शिवेश कुमार राम को अंग वस्त्र भेंट कर अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी

नई सोच एक्सप्रेस

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा दिल्ली प्रदेश के मीडिया शह प्रभारी महंत राजू नाथ चंदेल ने राष्ट्रीय कार्यालय में जाकर नवनियुक्त सांसद श्री शिवेश कुमार राम जी को अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर शुभकामनाएं दी महंत राजू नाथ चंदेल ने कहा कि हमारे अनुसूचित जाति समाज के लिए देशभर में हमारे सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवेश कुमार राम ने बड़े ही उल्लेखनीय कार्य करें हैं और बिहार में समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अनेकों अनेक कार्य किए हैं आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर अनुसूचित जाति समाज में खुशी की लहर है और इसके लिए देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को कोटि-कोटि धन्यवाद व्यक्त करते हैं आज देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना सम्मान अनुसूचित जाति समाज के लोगों को मिला है उतना 80 सालों में आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया है उन्होंने कहा कि हमारे नवनियुक्त अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवेश कुमार राम जी अनुसूचित जाति समाज के तमाम वर्गों को लेकर समान रूप से कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी

» शिवेश कुमार राम ने अनुसूचित जाति समाज के लिए देशभर में उल्लेखनीय कार्य किया

को और अत्यधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी अनिल सूद, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुजीत विश्वास, सहित गणमानिया व्यक्ति उपस्थित थे

दिव्य रुद्राभिषेक में संतोषानंद बोले- समाज को फर्जी धर्मगुरुओं से खतरा

नई सोच एक्सप्रेस

नई दिल्ली। श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के अवसर पर तालकटोरा स्टेडियम एवं तिरुपति बालाजी मंदिर में दिव्य रुद्राभिषेक समारोह का आयोजन किया गया। परमाध्यक्ष स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु एवं श्री पंचमुखी महादेव पीठाधीश्वर स्वामी संतोषानंद जी महाराज ने कहा कि भगवान शिव का परिवार सामाजिक समरसता, प्रेम, सौहार्द और आपसी सम्मान का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि समाज को आपसी भेदभाव और शत्रुता छोड़कर समन्वय एवं सम्मान की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म को विश्व की प्राचीन एवं श्रेष्ठ परंपरा बताते हुए कहा कि समाज को स्वयंभू और फर्जी धर्मगुरुओं से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने संत रविदास के संदेश "मन चंगा तो कठौती में गंगा" का उल्लेख करते हुए लोगों से मन को पवित्र रखने और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान का भाव अपनाने की अपील की। समारोह में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कपिल खन्ना, वरिष्ठ प्रचारक रौशन सिंह, जीवकांत झा सहित संत-महात्मा एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया।

वाराणसी में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में कर्मचारियों के उत्पीड़न पर जताई गई नाराजगी

नई सोच एक्सप्रेस

» सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के सम्मान और संगठन विस्तार का निर्णय

» कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं होगा बर्दाश्त,जरूरत पड़ी तो अधिकारियों का होगा घेराव - शशिकांत श्रीवास्तव

वाराणसी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा वाराणसी की कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को कोषागार कार्यालय स्थित सभागार में सम्पन्न हुई | बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शशिकान्त श्रीवास्तव व संचालन हरेंद्र यादव,उपाध्यक्ष ने किया | बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विगत वर्षों में जो कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी सेवानिवृत हो चुके हैं उनका सम्मान किया जाए और साथ ही संगठन का विस्तार कर नए पदाधिकारी कार्यकारिणी में सम्मिलित कर दायित्व दिया जाए | जिलाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव ने अध्यक्षीय सम्बोधन में कहा कि जनपद में कुछ विभागों के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है वह क्षम्य नहीं है क्योंकि कर्मचारियों की कमी के बावजूद भी किस तरह से कार्यरत कर्मचारियों मानसिक दबाव में रहकर कार्य कर रहा है उत्पीड़न से कार्य पर प्रभाव पड़ता है इसलिए उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए लामबंद होकर उस विभाग के अधिकारी का घेराव किया जाएगा घेराव किया जाएगा | बैठक में के अंत में जिला मंत्री श्याम राज यादव ने सभी का स्वागत एवं आभार प्रकट किया | बैठक मे दिवाकर द्विवेदी मण्डल अध्यक्ष,रामचन्द्र गुप्ता जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ,दिनेश सिंह अध्यक्ष विकास भवन कर्मचारी संघ, अशोक कुमार सिंह सलाहकार एवं मार्गदर्शक मण्डल,प्रमोद श्रीवास्तव,महेश श्रीवास्तव,श्रीप्रकाश लाल,राज्य कर विभाग,कुमारी सुषमा भास्कर गीता उपाध्याय (स्वास्थ्य विभाग) वेद प्रकाश सिंह (पशुपालन विभाग) हेमलता भारती, प्रियंका गुप्ता (कृषि विभाग) गया यादव, सुनील कुमार सिंह,राजेश कुमार सिंह नंदलाल गुप्ता,नीरज श्रीवास्तव (कुष्ठ विभाग) देवेंद्र राय,कमलेश सिंह (कोषागार),अरविन्द दूबे,अवधेश पाण्डेय (सिंचाई विभाग),मनीष चौबे सहित इत्यादि पदाधिकारियों ने भाग लिया ||

करंट से युवक की मौत और गंगा में व्यक्ति के बहने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने जताई चिंता

नई सोच एक्सप्रेस

देसरी/सहदेई बुजुर्ग। चांदपुरा थाना क्षेत्र के आजमपुर पंचायत के खड़गपुर गांव में बिजली पोल से करंट की चपेट में आने से युवक गुलशन ठाकुर की मौत तथा देसरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में 58 वर्षीय उमेश पंडित के गंगा की तेज धारा में बह जाने की घटना को लेकर क्षेत्र में चिंता का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने पर वैशाली जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रंजीत पंडित ने दोनों गांवों का दौरा कर घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जर्जर पोल एवं तारों की तत्काल जांच और मरम्मत कराने की मांग की। सुल्तानपुर में उमेश पंडित के परिजनों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को खोज अभियान तेज करना चाहिए। उन्होंने विद्युत विभाग के पदाधिकारियों, अंचलाधिकारी और एडीएम आपदा से दूरभाष पर बात कर दोनों मामलों में त्वरित कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों को नियमानुसार सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। मौके पर कांग्रेस नेता अभिषेक कुमार, सुबोध पासवान, राकेश सिंह, राजद नेता श्यामनंदन राय और प्रजापति समन्वय समिति के प्रखंड अध्यक्ष वीरेंद्र पंडित सहित अन्य लोग मौजूद थे।

राष्ट्रीय सनातन संघ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नागेश्वर सिंह का वाराणसी में जोरदार स्वागत,जय श्रीराम के जयघोष से गूंजा परिसर

नई सोच एक्सप्रेस

वाराणसी। राष्ट्रीय सनातन संघ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नागेश्वर सिंह के मनोनीत होने के बाद प्रथम बार वाराणसी आगमन पर राष्ट्रीय नेतृत्व कन्हैया पांडेय के मार्गदर्शन पर जनपद इकाई द्वारा जोरदार स्वागत किया गया | वाराणसी मे चोलापुर स्थित कान्हा रेस्टोरेंट टी स्टॉल पर जिला इकाई की तरफ से माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया गया इस दौरान जय श्री राम के जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठा | स्वागत कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय प्रभारी देवेंद्र पांडे जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश चतुर्वेदी,जिला प्रभारी शिवपूजन सिंह,जिला सलाहकार विवेक राय,जिला उपाध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह,जिला कार्यकारिणी सदस्य अंगद यादव सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे | प्रदेश अध्यक्ष नागेश्वर सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं हिंदू समाज को संगठित करने के लिए निरंतर कार्य करेगा | उन्होंने वाराणसी इकाई द्वारा किए गए स्वागत के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया ||

» प्रदेश अध्यक्ष नागेश्वर सिंह ने सनातन संस्कृति के संरक्षण और हिंदू समाज को संगठित करने का लिया संकल्प

सभी शिक्षकों को टीईटी से मुक्ति का प्रावधान लागू करे सरकार- सनत कुमार सिंह

नई सोच एक्सप्रेस

» उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ वाराणसी के वरिष्ठ शिक्षक नेता सनत कुमार सिंह ने शिक्षक दिवस से पहले शिक्षकों को टेट से मुक्ति की उठाई मांग- सनत कुमार सिंह

वाराणसी। शिक्षक दिवस से पूर्व सरकार को सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से स्थायी छूट देने का प्रावधान लागू करना चाहिए। यह मांग सनत कुमार सिंह ने उठाई है उन्होंने कहा कि लंबे समय से शिक्षण कार्य कर रहे अनुभवी और वरिष्ठ शिक्षकों की सेवा, सम्मान और नौकरी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार को संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए | सनत कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने बुजुर्ग और अनुभवी शिक्षकों के कल्याण, स्वास्थ्य सुरक्षा और सम्मान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं | उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना के माध्यम से शिक्षकों और उनके परिवारों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित है | उन्होंने कहा कि आठवें वेतन आयोग से जुड़े प्रस्तावों में स्कूली शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किए जाने और पुरानी पेंशन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा जारी है उनके अनुसार,तमिलनाडु जैसे राज्यों में 2010 से पहले नियुक्त अनुभवी एवं वरिष्ठ सरकारी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से स्थायी छूट देने का प्रस्ताव पारित किया गया है ताकि उनकी लंबी सेवा और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके | सनत कुमार सिंह ने कहा कि कई राज्यों में योग्य एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानद अथवा स्वयंसेवक शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है | इससे अनुभवी शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं और उनका अनुभव नई पीढ़ी के विद्यार्थियों के काम आ सकता है | उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस से पहले सरकार को सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से स्थायी छूट यानी 'टीईटी से मुक्ति' का प्रावधान लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को समय -समय पर शिक्षकों की समस्याओं और उनकी मांगों के प्रति सचेत रहना चाहिए | यदि शिक्षक अपनी समस्याएं लेकर सरकार के पास नहीं जा पाएंगे तो वे अपनी आपबीती आखिर किसे सुनाएंगे ||

महिला थाना प्रभारी फिरदौस नाज के विरुद्ध पहले भी कई बार कार्रवाई की अनुशंसा, फिर भी महत्वपूर्ण पद पर तैनाती

नई सोच एक्सप्रेस

» ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोपों को लेकर अलग-अलग तिथियों में थाने में दर्ज हुआ सनहा, विभागीय कार्रवाई की अनुशंसाओं के बावजूद पद पर बने रहने से उठ रहे सवाल

चतरा। चतरा महिला थाना की प्रभारी फिरदौस नाज की कार्यशैली और उनके विरुद्ध पूर्व में की गई विभागीय कार्रवाई की अनुशंसाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, महिला थाना प्रभारी के विरुद्ध पूर्व में भी कई बार विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जा चुकी है। इसके बावजूद उनका महत्वपूर्ण पद पर बने रहना पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कई अनसुलझे सवाल पैदा कर रहा है। बताया जाता है कि फिरदौस नाज के विरुद्ध अलग-अलग समय में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने समेत कई शिकायतें सामने आती रही हैं। ड्यूटी से लगातार गायब रहने के आरोपों को लेकर अलग-अलग तिथियों में थाने में सनहा दर्ज किए जाने की भी बात सामने आ रही है। यदि किसी पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध लगातार अनुपस्थित रहने जैसी गंभीर शिकायतें सामने आती हैं और इस संबंध में थाने के अभिलेखों में सनहा भी दर्ज होता है, तो स्वाभाविक रूप से विभागीय स्तर पर इसकी जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजिमी है। **कार्रवाई की अनुशंसा के बावजूद पद पर क्यों** ?सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि महिला थाना प्रभारी के विरुद्ध पूर्व में कई बार विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी, तो इसके बाद भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले पद पर बनाए रखने का आधार क्या है? क्या पूर्व की अनुशंसाओं पर विभागीय स्तर पर कोई अंतिम निर्णय लिया गया या फिर मामले लंबित हैं? इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना अभी बाकी है। महिला थाना महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मामलों की सुनवाई और कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे थाने की जिम्मेदारी संभालने वाले पदाधिकारी से नियमित उपस्थिति, शिकायतकर्ताओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा रहती है। ऐसे में थाना प्रभारी के विरुद्ध लगातार शिकायतें और कार्रवाई की अनुशंसाओं की चर्चा सामने आने से विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। **अभिलेखों की जांच से सामने आ सकती है सच्चाई**:मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए तो यह स्पष्ट हो सकता है कि महिला थाना प्रभारी के विरुद्ध पूर्व में कितनी बार शिकायतें की गईं, किन मामलों में विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा हुई, ड्यूटी से अनुपस्थिति को लेकर कितनी बार सनहा दर्ज हुआ और उन सभी मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई। साथ ही यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित शिकायतों पर विभागीय स्तर से क्या निर्णय लिया गया। फिलहाल इन तमाम सवालों के बीच महिला थाना प्रभारी फिरदौस नाज का महत्वपूर्ण पद पर बने रहना चर्चा का विषय बना हुआ है।

महात्मा गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में 470वें युगऋषि वाङ्मय की स्थापना

नई सोच एक्सप्रेस

लखनऊ। गायत्री ज्ञान मंदिर, इंदिरा नगर के विचार क्रांति ज्ञान यज्ञ अभियान के तहत महात्मा गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, खसरवारा-जुनाबगंज के केंद्रीय पुस्तकालय में 470वें युगऋषि वाङ्मय की स्थापना की गई। इस अवसर पर गायत्री परिवार के संस्थापक युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित सम्पूर्ण 79 खंडों का साहित्य पुस्तकालय को भेंट किया गया। साहित्य भेंट करने वाली श्रीमती सावित्री शर्मा ने इसे अपनी पुत्री सुश्री पार्वती शर्मा के स्वस्थ जीवन एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए ज्ञानदान बताया। इस अवसर पर संस्थान के शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं छात्र-छात्राओं को अखंड ज्योति पत्रिका तथा चेयरमैन एवं प्रधानाचार्य को अमृतवाणी कैलेंडर भी भेंट किया गया। वाङ्मय स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि ऋषि का सद्साहित्य व्यक्ति को स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की दिशा प्रदान करता है। संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ. राजीव कुमार पाण्डेय ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में गायत्री ज्ञान मंदिर के प्रतिनिधि उमानंद शर्मा, देवेंद्र सिंह, सावित्री शर्मा, शशि गंगवार सहित संस्थान के चेयरमैन, चिकित्सक, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

हर खबर पर पैनी नजर
नई सोच एक्सप्रेस
(बिहार और झारखंड से प्रकाशित हिन्दी दैनिक)

संक्षिप्त समाचार

पवन सिंह लफुआ है ,शराब पीकर आया हैं, जांच होगी तो धरा जाएगा : तेजप्रताप

पटना। भोजपुरी बवाल का मंच इन दिनों सिर्फ मनोरंजन का अड्डा नहीं, बल्कि तंज, ठिठोली और सियासी चुटकियों का अखाड़ा भी बनता दिखाई दे रहा है। ताजा मामला भोजपुरी स्टार और बीजेपी टछउ पवन सिंह को लेकर है, जिन पर तेज प्रताप यादव ने मंच से तीखा हमला बोला। पटना के ज्ञान भवन में शो की शूटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत में तेज प्रताप ने कलाकारों के शराब से दूर रहने की बात कही और इसी बहाने पवन सिंह पर निशाना साध दिया। तेजप्रताप ने कहा कि वह खुद कृष्ण भगवान के भक्त हैं, वृंदावन आते-जाते हैं और तुलसी की माला धारण करते हैं। उन्होंने दावा किया कि वह शराब से दूर रहते हैं। इसके बाद उनका निशाना कुछ कलाकारों की ओर मुड़ गया।तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि कुछ कलाकार शराब पीकर मंच पर ठुमके लगाते हैं। इसी क्रम में उन्होंने पवन सिंह का नाम लेते हुए कहा कि वह टछउ हो गए हैं और शराब पी रहे हैं। तेज प्रताप ने आगे दावा किया कि अगर केस होगा तो पकड़े जाएंगे। बात यहीं नहीं रुकी। तेज प्रताप ने पवन सिंह को लेकर और भी तीखी टिप्पणी कर दी। उन्होंने उन्हें बड़ा लफुआ कह दिया। यानी जिस शो का नाम ही भोजपुरी बवाल है, वहां मंच से निकला यह बयान खुद एक नया बवाल बन गया। दिलचस्प बात यह है कि भोजपुरी बवाल में भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आ रहे हैं। पवन सिंह, दिनेश लाल यादव ह्यनिरहुआह्ल, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव जैसे नाम इस शो से जुड़े हैं। यानी मंच पर कैमरा मनोरंजन कैद कर रहा है, लेकिन कैमरे के बाहर बयानबाजी अलग ही पटकथा लिख रही है। एक तरफ कलाकारों की हंसी-मजाक और परफॉर्मेंस है, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप के बयान ने सोशल मीडिया और भोजपुरी गलियारे में चर्चा को गरमा दिया है।अब देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह इस तंज का जवाब देते हैं या फिर ह्यभोजपुरी बवालह्ल की यह चिंगारी अगले एपिसोड तक सिर्फ चर्चा बनकर रह जाती है। फिलहाल इतना तय है कि शो के मंच पर मनोरंजन चल रहा है और बाहर बयानों की सियासत अपना अलग रंग दिखा रही है

मुख्यमंत्री ने आवासीय मकानों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर जारी नोटिस के समाधान के लिए समिति का किया गठन

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना नगर निगम द्वारा आवासीय मकानों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर जारी नोटिस के समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में समिति गठित की है। इस समिति में नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश कुमार मिश्र तथा सदस्य के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव एवं विधान पार्षद संजय कुमार सिंह होंगे।समिति संबंधित विषय का अध्ययन कर व्यावहारिक एवं जनहितकारी समाधान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।पटना नगर निगम द्वारा जारी किये गये नोटिस के समाधान हेतु मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में विधायक संजीव चौरसिया, विधायक रत्नेश कुशवाहा, विधायक श्याम रजक एवं विधायक संजय गुप्ता शामिल थे।

आंदोलनकारी छात्र-युवाओं पर दंडनात्मक कार्रवाई निंदनीयः भाकपा

पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर हुए पानी के बौछार, पुलिस लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा की है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भारी पुलिस बल का इस्तेमाल करना, भाजपा सरकार की लोकतंत्र के प्रति घोर अवमानना को उजागर करता है। लोकतंत्र संवाद से कायम रहता है, दमन से नहीं। भाजपा सरकार जन आंदोलन को लाठी के बल पर दबाना चाहती है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा छात्रों पर की गई टिप्पणी की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी निंदा करती है और उन पर कठोर कार्रवाई की मांग करती है। सरकार गिरफ्तार एआईएसएफ राज्य अध्यक्ष सुधीर कुमार सहित सभी छात्र नेताओं को बिना शर्त रिहा करें। भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि छात्र बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से जुड़े भ्रष्टाचार और बार-बार सामने आए घोटालों के चलते छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय, सरकार बिहार लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली का बचाव कर रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में भी बदलाव कर दिया है जिससे भी छात्र नाराज है। भाजपा सरकार में देश की शिक्षा व्यवस्था संकट में डूब गई है। छात्रों पर हो रहा यह निरंकुश हमला बंद होना चाहिए। देश जवाबदेही का हकदार है, न कि लीपापोती का। भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास घेराव करने निकले थे। पहले पुलिस लाठी के बल पर छात्रों को गांधी मैदान में रोकने की कोशिश की।

जेडी वीमेंस कॉलेज में सावन महोत्सव आयोजित

पटना। जानकी देवी महिला महाविद्यालय, पटना के न्यू आर्ट्स ब्लॉक स्थित सेमिनार हॉल में आज, 25 अगस्त 2026 को सावन के पावन महीने के अवसर पर सावन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. मीरा कुमारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सावन महोत्सव में महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़-चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में ठरर की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. मंजरी नाथ एवं डॉ. हीना रानी के साथ-साथ अन्य शिक्षिकाओं एवं शिक्षकों ने भी सक्रिय सहभागिता की। महोत्सव को मनोरंजक एवं आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के खेल, नृत्य एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए पूरे कार्यक्रम में उत्साह और उमंग का माहौल बनाए रखा। महोत्सव का प्रमुख आकर्षण सावन क्वीन प्रतियोगिता रही, जिसमें तीन छात्राओं का चयन किया गया। प्रतियोगिता में मौली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रियंका ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता ने सभी प्रतिभागियों और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।पूरे कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय परिसर में सावन की खुशियों, उमंग और उत्साह का वातावरण बना रहा। छात्राओं एवं शिक्षिकाओं ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर सावन के पावन महीने का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम का आयोजन सभी के लिए आनंददायक एवं यादगार रहा।

बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस की बर्बरता शर्मनाक : राजेश

पटना। पटना में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बर कार्रवाई बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों का खुला उल्लंघन है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचकर पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों का हालचाल जाना। उन्होंने घायल छात्रों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में अपने अधिकारों और भविष्य के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों के साथ सरकार का यह रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों की समस्याओं का समाधान संवाद और संवेदनशीलता से होना चाहिए, न कि लाठी और दमन से। उन्होंने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थी अपने भविष्य और रोजगार से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। उनकी आवाज सुनने के बजाय उन पर पुलिस की कार्रवाई करना सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। छात्र सवाल पूछें तो लाठी, हक मांगें तो दमन—क्या यही सम्राट का सुशासन है? उन्होंने सरकार से मांग की कि घायल छात्रों का समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए, पुलिस की बर्बर कार्रवाई की निष्पक्ष जांच हो तथा शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों पर तत्काल संवाद स्थापित कर उचित समाधान निकाला जाए।

अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन 20000 छात्राओं को देगा स्कॉलरशिप

नई सोच एक्सप्रेस

पटना।अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन ने दिल्ली (एनसीटी) के लिए अज़ीम प्रेमजी स्कॉलरशिप शुरू करने का ऐलान किया है। इस साल दिल्ली में 20000 तक छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए इस स्कॉलरशिप से मदद मिलेगी। स्कॉलरशिप के लिए चुनी गई हर छात्रा को हर साल 30000 रुपये दिए जाएँगे। यह राशि कॉलेज के पहले साल से लेकर छात्राओं की स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पूरा होने तक दी जाएगी। अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ अनुराग बेहर ने कहा कि हमारे देश और समाज के भविष्य और उसकी खुशहाली को हासिल करने और बनाए रखने में लड़कियों की भूमिका किसी भी दूसरे सामाजिक समूह से कहीं ज़्यादा होगी। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में बराबर मौके मिलें। उच्च शिक्षा ऐसे ही सबसे अहम क्षेत्रों में से एक है। यह जिंदगी भर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। उच्च शिक्षा हासिल करने में लड़कियों को आज भी जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हमारी स्कॉलरशिप उनमें से कुछ मुश्किलों को सीधे तौर पर दूर करने की कोशिश करती है।

महिला सम्मान पर भाषण नहीं, पहले आचरण से उदाहरण पेश करें राहुल गांधी : संतोष

नई सोच एक्सप्रेस

पटना।हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं के महिला सम्मान, बराबरी और सामाजिक न्याय संबंधी बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला सशक्तीकरण केवल भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के आचरण और नेतृत्व में दिखाई देना चाहिए।डॉ. सुमन ने कहा कि यदि राहुल गांधी महिलाओं के सम्मान, बराबरी और पुरुष वर्चस्व के खिलाफ इतने गंभीर हैं, तो इसकी

> » नई पीढ़ी भाषण नहीं, नेताओं का आचरण और राजनीतिक इतिहास देखती

शुरूआत अपनी पार्टी से करें और कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंपकर उदाहरण प्रस्तुत करें। इसी तरह तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय और बराबरी की बात करते हैं तो क्या वे राजद की कमान मीसा भारती को सौंपने का साहस दिखाएंगे? उन्होंने कहा कि स्टालिन और अखिलेश यादव सहित जो नेता महिलाओं को बराबरी देने की बात करते हैं, उन्हें अपने संगठन और सत्ता में महिलाओं को वास्तविक नेतृत्व का अवसर देना चाहिए।उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के खिलाफ बोलने से पहले राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक आचरण और इतिहास को भी देखना चाहिए। जब देश ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया, तब उनके खिलाफ खड़े होने वालों को पहले अपने राजनीतिक रुख पर देश को जवाब देना चाहिए। महिला सशक्तीकरण की बात करने वालों को यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेस ने कितने राज्यों में महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक नेतृत्व दिया, कितनी महिला प्रदेश अध्यक्ष बनीं और आज कितने राज्यों में कांग्रेस की महिला मुख्यमंत्री हैं।

दादी प्रकाशमणि की पुण्यतिथि पर रक्तदान महाअभियान

नई सोच एक्सप्रेस

सिमराही बाजार।प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी की 19वीं पुण्यतिथि पर स्थानीय ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र में रक्तदान महाअभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने कैंडल लाइटिंग एवं फीता काटकर किया। इस दौरान दादी प्रकाशमणि जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके त्याग, सेवा, सादगी और मानव कल्याण के कार्यों को याद किया गया। राघोपुर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. दीप नारायण राम, प्रो. वैद्यनाथ प्रसाद भगत और सेवानिवृत्त डीआईजी प्रणव जयसवाल ने रक्तदान को महान मानवीय सेवा बताते हुए लोगों से नियमित रक्तदान की अपील की। आयोजकों के अनुसार महाअभियान में 60 यूनिट रक्त संकलन का लक्ष्य रखा गया। इसमें विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी बबीता दीदी समेत ब्रह्माकुमारी परिवार के सदस्य एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

महिला कॉलेज खगौल में सावन महोत्सव का आयोजन

नई सोच एक्सप्रेस

खगौल।महिला कॉलेज, खगौल में सावन महोत्सव हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। महाविद्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जहां सावन की हरियाली के साथ भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिली। प्राचार्या डॉ. उषा विद्यार्थी ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन छात्राओं को अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़ने के साथ उनके व्यक्तित्व विकास में भी सहायक होते हैं। कार्यक्रम का नेतृत्व डॉ. आराधना सिंह ने किया, जबकि मंच संचालन फरहीन तबस्सुम ने किया। छात्राओं और शिक्षिकाओं ने सावन के पारंपरिक गीत, नृत्य एवं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में डॉ. बुलबुली कानू, डॉ. खुशबू फातिमा, डॉ. सीमा, डॉ. मधुश्री, डॉ. राखी, डॉ. वीणा, डॉ. रीना, डॉ. कविता जैन, डॉ. किरण, डॉ. अजीता प्रियदर्शिनी, डॉ. चंदा सिंह, डॉ. जूली एवं डॉ. सुमन सहित अन्य शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।

किसानों के आंदोलन के बीच जदयू नेता उत्तम सिंह ने जताया सरकार पर भरोसा

नई सोच एक्सप्रेस

पटना। किसानों के द्वारा आज पटना में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। इस दौरान पुनपुन के किसानों ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी समस्याओं पर अपेक्षित सुनवाई नहीं हो रही है। मौके पर पहुंचे जदयू पटना महानगर अध्यक्ष उत्तम सिंह ने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है और जल्द ही किसानों के हित में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उत्तम सिंह ने कहा कि मुझे अपने नेता विकास पुरुष नीतीश कुमार पर पूरा विश्वास है। पुनपुन मेरा पैतृक गांव भी है, इसलिए एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में किसानों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया हूं और हमेशा किसानों के हित में खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और उन्हें विश्वास है कि जल्द ही उचित पहल होगी।

अतिथि शिक्षकों के सेवा समायोजन की दिशा में पहल, मुख्यमंत्री के आश्वासन से खुशी

नई सोच एक्सप्रेस

पटना।राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के सेवा समायोजन को लेकर सकारात्मक पहल सामने आई है। 22 दिनों से धरना स्थल पर आमरण अनशन कर रहे अतिथि शिक्षकों के मामले में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के स्तर पर पहल के बाद शिक्षकों में उम्मीद और खुशी का माहौल है। दरभंगा ग्रामीण के विधायक एवं जदयू जिलाध्यक्ष राजेश मंडल उर्फ ईश्वर मंडल ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अतिथि शिक्षकों को 65 वर्ष तक सेवा सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग रखी थी। विधायक ने कहा कि वर्ष 2019 में नियुक्त अतिथि शिक्षकों को अध्यापन कार्य के अलावा अन्य रोजगार नहीं करने का निर्देश दिया गया था। शिक्षक इस निर्देश का पालन करते हुए वर्षों से विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में नियमित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से पहले अतिथि शिक्षकों के सेवा समायोजन पर निर्णय नहीं हुआ तो हजारों शिक्षकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने बताया कि बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति भी सेवा समायोजन की अनुशंसा कर चुकी है। उन्होंने सरकार और राजभवन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद आंदोलनरत शिक्षकों ने विधायक ईश्वर मंडल के प्रति आभार जताया। मौके पर डॉ. बच्चा कुमार रजक, डॉ. कन्हैया शाह, डॉ. अशोक कुमार, डॉ. सुमन कुमार पोद्दार सहित कई अतिथि शिक्षक मौजूद रहे।

दूरगामी सोच के साथ विकास के पथ पर बढ़ रही बिहार सरकार : सीता सिन्हा

नई सोच एक्सप्रेस

पटना।पूर्व मंत्री एवं भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सीता सिन्हा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार के विकास कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नई सरकार उद्योग, रोजगार, पर्यटन, सड़क, सेतु और शहरी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में दूरगामी सोच के साथ काम कर रही है। सीता सिन्हा ने कहा कि बिहार में उद्योगों के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य तय कर कार्ययोजना पर काम शुरू किया गया है। सरकार उद्योगों को राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख इंजन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की पहल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गंगा पथ के विस्तार, रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, अर्बन ग्रोथ कॉरिडोर, पटना में मेट्रो एवं एलिवेटेड बाईपास, चीनी मिलों के पुनरुद्धार तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन जैसी योजनाएं बिहार के विकास को नई गति देंगी। भाजपा नेत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार युवा, महिला, किसान और रोजगार के मुद्दों पर भी काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार की विकास योजनाएं आने वाले समय में बिहार की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को मजबूत करेंगी।

अनुसूचित जाति टोलों में श्री संत रविदास विकास शिविर लगाकर परिवारों को दिया जाएगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ- श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

नई सोच एक्सप्रेस

> » 27 अगस्त से हर गुरुवार लगेंगे श्री संत रविदास विकास शिविर, अनुसूचित जाति टोलों में योजनाओं की होगी मैपिंग

पटना।संत श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर शुरू किए गए संत श्री गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान का अगला चरण 27 अगस्त से शुरू होगा। इस दिन से राज्य के अनुसूचित जाति आबादी वाले टोलों और क्लस्टरों के समीप प्रत्येक गुरुवार को श्री संत रविदास विकास शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पात्र परिवारों तक पहुंचाने के साथ उनकी वास्तविक जरूरतों की पहचान और समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत विकास शिविरों का आयोजन 27 अगस्त 2026 से 15 फरवरी 2027 तक किया जाएगा। अभियान के शुरुआती चरण में 18 से 20 अगस्त तक आयोजित तीन दिवसीय कलश यात्रा के माध्यम से लोगों को सामाजिक समरसता, सरकारी योजनाओं और अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। अब जागरूकता के बाद योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में प्रशासनिक गतिविधियां तेज की जाएंगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री लखेंद्र कुमार रौशन ने कहा कि संत श्री गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल टोलों में रहने वाले प्रत्येक पात्र परिवार तक सरकार की योजनाओं और सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। विकास शिविरों के माध्यम से केवल योजनाओं की जानकारी नहीं दी जाएगी, बल्कि परिवारवार जरूरतों की पहचान कर उन्हें संबंधित योजनाओं से जोड़ने की ठोस कार्रवाई की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि कोई भी पात्र परिवार जानकारी, दस्तावेज या प्रक्रिया के अभाव में कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। **टोलेवार होगी जरूरतों की पहचान**:विकास शिविरों से पहले चिह्नित अनुसूचित जाति टोलों की मैपिंग कर वहां रहने वाले परिवारों की योजनावार स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि कौन-से परिवार पहले से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और किन पात्र परिवारों को अभी भी योजनाओं या बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाना बाकी है। परिवारवार स्तर पर आवास, राशन, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी जरूरतों की पहचान की जाएगी। साथ ही आयुष्मान कार्ड, आवास योजना, कौशल प्रशिक्षण, पेंशन सहित अन्य योजनाओं से वंचित पात्र लाभुकों को चिह्नित किया जाएगा। **एक ही स्थान पर मिलेंगी कई सेवाएं**: श्री संत रविदास विकास शिविरों की खासियत यह होगी कि ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। सरकारी भवनों अथवा मैदानों में लगाए जाने वाले इन शिविरों में संबंधित विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की तैयारी है। पात्रता के अनुसार आवेदन, दस्तावेजों की प्रक्रिया और योजनाओं से जोड़ने की कार्रवाई मौके पर ही किए जाने पर जोर रहेगा। **22 योजनाओं को बनाया गया अभियान का आधार**: शिविरों में 22 प्रमुख योजनाओं एवं सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, शिक्षा में दाखिला, आंगनबाड़ी सेवाएं, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, ई-श्रम/श्रमिक कार्ड, आयुष्मान भारत/स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, वास-भूमि बंदोबस्ती और सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं। इसके अलावा हर घर नल-जल, पक्की गली-नाली, मनरेगा जॉब कार्ड, जन-धन खाता, जीवन ज्योति एवं सुरक्षा बीमा, बिजली कनेक्शन, जीविका समूह और लोहिया स्वच्छता अभियान से पात्र परिवारों को जोड़ने की भी कार्रवाई की जाएगी। **शत-प्रतिशत संतुष्टि पर फोकस**: अभियान का उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी देना नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति आबादी वाले टोलों में पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाकर शत-प्रतिशत संतुष्टि सुनिश्चित करना है। टोलेवार और परिवारवार मैपिंग से प्रशासन को स्थानीय जरूरतों की स्पष्ट तस्वीर मिलेगी और उसी के आधार पर योजनाओं की पहुंच बढ़ाई जा सकेगी।

पेट्स का खाना बदलते समय जल्दबाजी से बचें, धीरे-धीरे करें बदलाव

नई सोच एक्सप्रेस

पटना।पालतू जानवरों का खाना बदलते समय अचानक डाइट बदलना उनके स्वास्थ्य के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। गोदरेज पेट केयर के हैड (आरएंडडी) डॉ. अशोक पटनायक के अनुसार, अचानक भोजन बदलने से पाचन तंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे उल्टी, दस्त या खाना छोड़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर नए भोजन को 7 से 10 दिनों में धीरे-धीरे पुरानी डाइट में शामिल करना सुरक्षित रहता है। शुरुआत में नए खाने की 10 से 25 प्रतिशत मात्रा पुराने खाने में मिलाकर दें और हर दो-तीन दिन में इसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। बिल्लियों को नई डाइट अपनाने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है। घर के बने भोजन से पैकेज्ड या सूखे भोजन पर जाने में विशेष सावधानी जरूरी है। सूखे भोजन को जरूरत पड़ने पर थोड़े गुनगुने पानी या शोरबे से नरम किया जा सकता है। डाइट चुनते समय केवल ब्रांड या मार्केटिंग पर निर्भर रहने के बजाय पैकेट पर दिए गए इंग्रीडिएंट्स और प्रोटीन स्रोत की जानकारी भी देखनी चाहिए। यदि भोजन बदलने के दौरान लगातार दस्त, उल्टी या 24 घंटे से अधिक समय तक खाना छोड़ने जैसी समस्या हो तो डाइट परिवर्तन की गति धीमी करनी चाहिए। लक्षण 48 घंटे से अधिक बने रहने पर पशु चिकित्सक से सलाह लेने की जरूरत है। डॉ. पटनायक ने कहा कि धैर्यपूर्वक और धीरे-धीरे किया गया डाइट परिवर्तन ही पालतू जानवरों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है।

आम्रपाली दुबे के फॉलोअर्स की संख्या 60 लाख पर पहुंची

सो सोशल मीडिया पर भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के फॉलोअर्स की संख्या 60 लाख पहुंच गई है। इस उपलब्धि के लिए अपने प्रशंसकों का आभार जताते हुए अभिनेत्री ने एक वीडियो साझा किया। पोस्ट किए गए वीडियो में आम्रपाली दुबे 'तितली शहर' गाने पर शानदार अंदाज में लिपसिंक और एक्सप्रेशन देती नजर आईं। उन्होंने अपने प्रशंसकों के प्यार और लगातार मिल रहे समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद कहा। आम्रपाली दुबे फिल्मों के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं। उनके वीडियो और तस्वीरें अक्सर प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बनते हैं। हालांकि, इन दिनों वह अपनी सोशल मीडिया गतिविधियों के अलावा जियो हॉटस्टार के शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर भी सुर्खियों में हैं। शो के दौरान उन्होंने निजी जिंदगी से जुड़े कुछ मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि वह बिना शादी किए मां बनना चाहती हैं। आम्रपाली के मुताबिक, शुरुआत में उनके परिवार ने इस विचार पर आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में उनकी मां ने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। 'भोजपुरी बवाल' में आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' से जुड़े कई सवाल भी सामने आए हैं। दोनों कलाकार लंबे समय से भोजपुरी सिनेमा की चर्चित जोड़ियों में शामिल हैं। उनकी जोड़ी ने 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' से साथ काम करना शुरू किया था। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया और लगभग 35 फिल्मों में पति-पत्नी की भूमिका निभाई है। पर्दे पर बार-बार पति-पत्नी की भूमिका निभाने के कारण दोनों के बीच प्रेम संबंध और गुप्त शादी की अफवाहें भी लंबे समय से सामने आती रही हैं। हालांकि, आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव दोनों ही इन चर्चाओं को कई बार खारिज कर चुके हैं। आम्रपाली ने अलग-अलग मौकों पर स्पष्ट किया है कि निरहुआ का परिवार उनके लिए अपने परिवार जैसा है। वह उनके बच्चों के साथ भी करीबी और आत्मीय रिश्ता रखती हैं। लेकिन उनके और निरहुआ के बीच पेशेवर संबंध से आगे कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है।

दोनों कलाकार एक-दूसरे के प्रति सम्मान और दोस्ती का भाव रखते हैं। हाल ही में अभिनेत्री काजल राघवानी ने भी 'भोजपुरी बवाल' में आम्रपाली और निरहुआ के रिश्ते को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने आम्रपाली से पूछा कि क्या वह दिनेश लाल यादव को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं और क्या उनकी वजह से निरहुआ उनके साथ फिल्में नहीं करते। इन सवालों ने दोनों कलाकारों के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं को फिर हवा दे दी। आम्रपाली ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अफवाहों से अलग वास्तविकता पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर 60 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करना आम्रपाली दुबे की लोकप्रियता का एक और बड़ा प्रमाण माना जा रहा है।

प्यार और रिश्तों की परिपक्वता दिखाता शहजान पद्मसी का डेब्यू लव सॉन्ग 'रात कालिया'

द दक्षिण भारतीय अभिनेत्री शहजान पद्मसी ने गाना रात कालिया से गायिकी में डेब्यू किया है। अभिनेत्री ने बताया कि गायन को लेकर वे पहले से पैशनेट थीं, लेकिन एक्टिंग के लिए फिल्मों के ऑफर आने लगे, जिससे ये सपना पीछे रह गया। अभिनेत्री ने बताया, एक्टिंग का सफर अचानक से शुरू हुआ और मुझे काम करते वक्त काफी मजा भी आ रहा था। फिर, एक के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं लहर पर सर्फिंग कर रही हूं। शहजान पद्मसी कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 2 में पारुल नाम के किरदार में नजर आई थी। अभिनेत्री का मानना है कि इस फिल्म में काम करने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें थोड़ी क्रिएटिविटी की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे अंदर एक दूसरा पहलू भी था, जिसे मैं देखना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि चलो उस रास्ते पर चलते हैं। मेरी मां, शेरोन प्रभाकर, इंडिया की पहली पॉप स्टार्स में से एक हैं। तो मैंने मॉम के साथ म्यूजिक में आगे बढ़ने का फैसला किया। हम दोनों घंटों तक साथ में रियाज करते थे। अभिनेत्री ने अपनी मां का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि वे उनकी वजह से शहजान पद्मसी को बाहर क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा, मां की शिक्षिका बनना मुझे काफी अच्छा लगा। क्योंकि बेशक हम सब दिल से ही काम करते हैं, लेकिन मैंने सच में समय लिया और खुद से कहा कि अगर मुझे इस प्रोफेशन को सीरियसली लेना है, तो अपने हुनर पर काम करना होगा। पहले अपना हुनर पक्का करना होगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और मुझे प्रैक्टिस की इस पूरी प्रोसेस से प्यार हो गया। अभिनेत्री ने आगे गाना रात कालिया के बार में भी बताया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यह एक लव सॉन्ग है, जो प्यार के नजरिए को दिखाता है। जैसे किसी भी रिश्ते के शुरुआत में इंसान एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, कुछ वैसा ही। इसमें मेरे बहुत सारे ख्याल हैं, जिसमें मैं घंटों बात कर सकती हूं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं अपने दोस्तों से इस बारे में बात करती हूं, तो वो भी कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसा ही महसूस किया है। वो कहते हैं, हां, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं पहले बहुत डिपेंडेंट थी। मैं एक इंसान पर झुक जाती थी और अब मैं बहुत बदल गई हूं, तो ये प्यार का एक बदला हुआ, परिपक्व सफर है।

एक्टिंग के बाद अब सुरों का जादू चलाएंगी शहजान पद्मसी

फिल्म 'हाउसफुल 2' में अपनी मासूमियत से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री शहजान पद्मसी ने अपनी नई कलात्मक पारी की शुरुआत की है। लंबे समय से अभिनय की दुनिया में सक्रिय शहजान ने अब संगीत क्षेत्र में कदम रखते हुए अपना पहला डेब्यू सिंगल 'रात कालिया' लॉन्च कर दिया है। अपने इस नए सफर पर बात करते हुए शहजान ने साझा किया कि संगीत हमेशा से उनका पहला प्यार रहा है। हालांकि, करियर की शुरुआत में ही एक के बाद एक कई फ़िल्मी प्रोजेक्ट्स मिलने के कारण उनका गायिकी का सपना कुछ समय के लिए थम गया था। लेकिन अब उन्होंने अपने भीतर की इस रचनात्मक लालसा को पूरा करने का मन बनाया है। शहजान के संगीत के इस सफर में उनकी मां और भारत की मशहूर पॉप स्टार शेरोन प्रभाकर की अहम भूमिका रही है। बिना किसी बाहरी कोचिंग के, शहजान ने अपनी मां के मार्गदर्शन में ही घंटों रियाज कर अपनी आवाज़ को निखारा है। उनका डेब्यू ट्रैक 'रात कालिया' एक रोमांटिक गाना है। शहजान के मुताबिक, यह गाना प्यार में मिलने वाले जुड़ाव, शुरुआती निर्भरता और समय के साथ रिश्ते में आने वाली परिपक्वता को गहराई से बयान करता है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म वन की बदली रिलीज तारीख, अब 25 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी

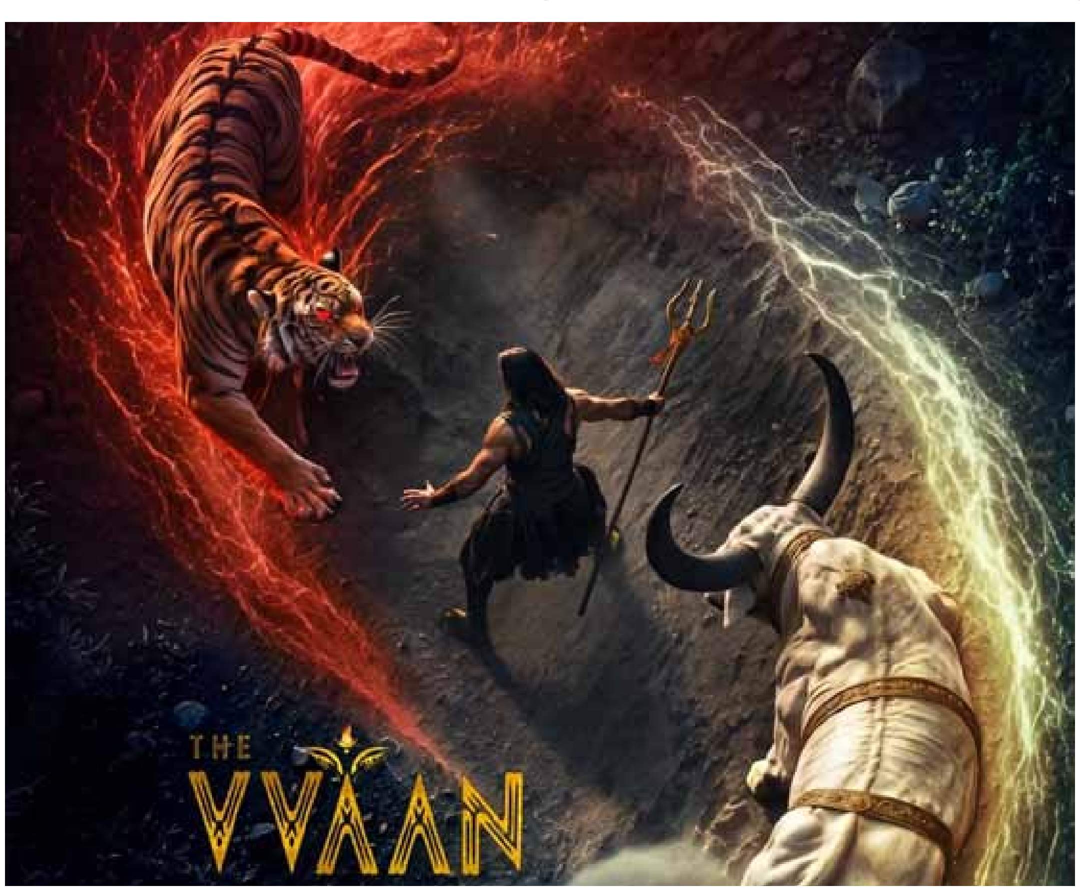

सि सिद्धार्थ मल्होत्रा की बहुप्रतीक्षित फिल्म वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट अब 28 अगस्त को नहीं आएगी। निर्माता बालाजी मोशन पिक्चर्स ने एक मोशन पोस्टर जारी करते हुए इसकी नई रिलीज तारीख का ऐलान किया है। दीपक मिश्रा और अरुणभ कुमार द्वारा निर्देशित यह फिल्म पहले रक्षाबंधन के अवसर पर सिनेमाघरों में आनी थी। चूकि उसी हफ्ते में श्रद्धा कपूर की ईथा और यश की टॉक्सिक रिलीज हो रही हैं। इस टकराव से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। निर्माता एकता कपूर ने वन का एनिमेटेड मोशन पोस्टर जारी किया है, जिसमें त्रिशूल लिए एक व्यक्ति खूंखार बाघ और नंदी से घिरा हुआ है। उसके चारो ओर बिजली की कड़क दिखाई गई है। पोस्ट के साथ कैप्शन दिया गया, बाघ की दहाड़ है नंदी उसकी शक्ति है। और वन उसकी कहानी। फिल्म में सिद्धार्थ के साथ तमन्ना भाटिया मुख्य किरदार में हैं। यह अब 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। इसके बाद अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी। मध्य भारत के घने जंगलों में फिल्माई गई फिल्म वन को रोमांच, गुप्त मंदिरों और पुरानी कहानियों का मिश्रण बताया गया है। इसकी शूटिंग वास्तविक वन क्षेत्रों में की गई है। एकता कपूर इसकी प्रोड्सर हैं और फिल्म की निर्माण बालाजी मोशन पिक्चर्स और द वायरल फीवर के सहयोग से हुआ है। दीपक मिश्रा और अरुणभ कुमार इसके डायरेक्टर हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा को आखिरी बार फिल्म परम सुंदरी में देखा गया था। इस मूवी में उनके अपोजिट जाह्नवी कपूर नजर आई थीं। दिनेश विजन के मैडॉक बैनर तले इसका निर्माण हुआ था और तुषार जलोटा इसके डायरेक्टर हैं।

कभी पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते थे शान

हा हाल ही में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर शान ने बताया कि उन्हें कभी भरोसा नहीं था कि वह संगीत की दुनिया में अपनी अलग जगह बना पाएंगे। यहां तक कि वह अपने परिवार में खुद को संगीत के मामले में सबसे कमजोर कड़ी मानते थे। यही वजह थी कि शुरुआत में उन्होंने गायकी को करियर के रूप में अपनाने के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। शान ने एक पॉडकास्ट में अपने संगीत सफर से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उनके पिता एक कुशल संगीतकार और शानदार गायक थे। उनके दादा, मां और बहन भी बहुत अच्छा गाते थे। ऐसे परिवार में पले-बढ़े शान को हमेशा लगता था कि उनकी गायकी बाकी सदस्यों के मुकाबले कमजोर है। शान ने स्वीकार किया कि परिवार में संगीत की मजबूत पृष्ठभूमि होने के बावजूद वह खुद को सबसे कम प्रतिभाशाली मानते थे। शान ने अपने बचपन और युवावस्था की विद्रोही सोच का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस समय वह पत्रकारिता और विज्ञापन जैसे क्षेत्रों में अपना भविष्य तलाशना चाहते थे। गायकी उनके लिए किसी सुनियोजित करियर का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। उनके मुताबिक, गायकी उनके जीवन में धीरे-धीरे और स्वाभाविक रूप से आती चली गई। शान ने इस धारणा से भी असहमति जताई कि गायकी की प्रतिभा परिवार से आनुवंशिक रूप से मिलती है। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति की प्रतिभा को उसके आसपास का माहौल ज्यादा प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि जिस वातावरण में बच्चा बड़ा होता है, उसका उसकी रुचियों और क्षमताओं पर गहरा असर पड़ता है। उनके घर में बचपन से ही संगीत का माहौल था, इसलिए गायकी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनती चली गई। शान ने बताया कि मुंबई में रहने और उनके माता-पिता के संगीत से जुड़े होने के कारण उन्हें बहुत कम उम्र में ही गाने के अवसर मिलने लगे थे। उनकी मां कोरस सिंगर थीं, जबकि उनके पिता की संगीत जगत में अच्छी पहचान थी। जब लोगों को पता चला कि शान और उनकी बहन भी गा सकते हैं, तो उन्हें विज्ञापनों के लिए गाने के मौके मिलने लगे। शुरुआत में शान ने कई अवसर ठुकरा दिए, क्योंकि वह इसे अपना करियर नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन लगातार मिलते अवसरों ने उनका नजरिया बदला और आखिरकार उन्होंने गायकी को पेशे के रूप में अपना लिया। आज शान भारतीय संगीत जगत के सम्मानित और बहुमुखी गायकों में शामिल हैं। मालूम हो कि भारतीय संगीत जगत के लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर शान ने अपनी सुरीली आवाज और अलग-अलग अंदाज के गीतों से खास पहचान बनाई है। हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर आत्मविश्वास की कमी से शुरू हुआ था।

खांसी से छुटकारा पाना चाहते हैं ? आज ही आजमाएं ये 5 घरेलू उपाय

खां खांसी एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। यह समस्या कई कारणों से होती है, जैसे ठंड, धूल-मिट्टी और धूम्रपान आदि। खांसी होने पर गले में खुजली, खराश और बलगम जैसी समस्याएं होती हैं, जिससे आराम मिलना मुश्किल हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप आसानी से खांसी से छुटकारा पा सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं।

अदरक का रस पीएं : अदरक का रस खांसी के लिए एक असरदार घरेलू उपाय है। इसमें मौजूद खास गुण गले की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए एक छोटे टुकड़े अदरक को कद्दूकस करके उसका रस निकालें और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर पीएं। यह मिश्रण गले की खराश को भी दूर करता है और खांसी को कम करता है। अदरक का रस पीने से आपको ताजगी और आराम महसूस होगा।

तुलसी की चाय बनाकर पीएंः तुलसी की चाय खांसी के लिए एक अच्छा उपाय हो सकती है। तुलसी में मौजूद गुण आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं और खांसी को दूर करते हैं। इसके लिए कुछ तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालें और उसमें थोड़ा-सा गुड़ डालें, फिर इसे छानकर पीएं। यह चाय न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि आपके गले को भी राहत देती है और खांसी को कम करने में मदद करती है।

नमक वाले गर्म पानी से गरारे करें

नमक वाले गर्म पानी से गरारे करना गले की सूजन कम करने का एक अच्छा तरीका है। नमक में मौजूद गुण बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और दर्द निवारक का काम करते हैं। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर गरारे करें। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी। इन उपायों को अपनाकर आप आसानी से खांसी से छुटकारा पा सकते हैं।

शहद और नींबू का मिश्रण लेंः शहद और नींबू का मिश्रण खांसी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और शहद की मिठास गले को सुकून देती है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पीएं। यह मिश्रण खांसी को कम करने के साथ-साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है और आपको जल्दी आराम मिलता है।

लहसुन की कली चबाएंः लहसुन की कली चबाना खांसी के लिए एक पुराना और असरदार तरीका है। लहसुन में मौजूद गुण संक्रमण को दूर करते हैं और खांसी को कम करते हैं। इसके लिए एक लहसुन की कली को चबाकर उसका रस निकालें या उसे थोड़ा कच्चा खा लें। इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी। लहसुन का सेवन करने से गले की सूजन भी कम होती है।

महिला डीपीएलः साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने सेंट्रल दिल्ली क्वींस को 11 रन से हराया

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 के महिला वर्ग में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल दिल्ली क्वींस को 11 रन से हरा दिया। बारिश के कारण आठ ओवरों तक सीमित रहे इस मुकाबले में साउथ दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 68 रन बनाए, जिसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली की टीम 5 विकेट पर 57 रन ही बना सकी। अरुण जेटली स्टेडियम में साउथ दिल्ली की कप्तान श्वेता सहरावत ने 21 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 26 रन बनाकर टीम की पारी को संभाला। तनिषा सिंह ने भी 13 गेंदों पर 19 रन का उपयोगी योगदान दिया। इससे पहले प्रिया पुनिया ने तेज शुरुआत करते हुए चार गेंदों में नौ रन बनाए। सेंट्रल दिल्ली की ओर से सुमिति सोनी और मेधावी बिधूड़ी ने दो-दो विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। 69 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट्रल दिल्ली क्वींस की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने पहली ही गेंद पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद दीक्षा शर्मा ने 16 गेंदों में चार चौकों की मदद से 22 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन छठे ओवर में उनके रन आउट होने के बाद टीम की मुश्किलें बढ़ गईं। अरुषि गोयल ने 14 और मोनिका ने नौ रन बनाए, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह पर्याप्त नहीं रहा। साउथ दिल्ली की ओर से रूपाली विश्व मोहन, दिशा नागर और एकता भदाना ने एक-एक विकेट लिया। अनुशासित गेंदबाजी और चुस्त क्षेत्ररक्षण के दम पर साउथ दिल्ली ने मुकाबला 11 रन से अपने नाम कर लिया।

दलीप ट्रॉफी : शाहबाज और सुदीप के शतक से ईस्ट जोन ने दर्ज की पारी और 210 रनों से बड़ी जीत

एजेंसी, बेंगलुरु

शाहबाज अहमद के करियर के सर्वश्रेष्ठ 167 रन और सुदीप कुमार घरामी के 146 रन की शानदार पारियों के बाद अनुकूल रॉय और अभिजीत सरकार की पांच-पांच विकेट की घातक गेंदबाजी के दम पर ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ ईस्ट जोन को पारी और 210 रन से करारी शिकस्त दी। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-2 में खेले गए मुकाबले में ईस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 467 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। शाहबाज ने 167 रनों की करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली, जबकि सुदीप कुमार घरामी ने 146 रन बनाए। दोनों ने शानदार शतकीय पारियों से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

इसके जवाब में नॉर्थ ईस्ट जोन की पहली पारी महज 111 रन पर सिमट गई। अभिजीत सरकार ने 20 रन देकर पांच विकेट झटके, जबकि शाहबाज अहमद ने तीन विकेट अपने नाम किए। नॉर्थ ईस्ट जोन की ओर से अर्पित भटेवार ने सर्वाधिक 32 रन बनाए। फॉलोऑन खेलने उतरी नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम दूसरी पारी में भी ईस्ट के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। अनुकूल रॉय ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 37 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। शाहबाज और वैभव सूर्यवंशी ने भी अहम विकेट चटकाए। नॉर्थ ईस्ट जोन की ओर से पीहेरोइजाम जोतिन ने 39 रन बनाकर कुछ प्रतिरोध किया। नौवें विकेट के लिए आकाश चौधरी और जोतिन ने 39 रन की साझेदारी कर हार को कुछ देर टाला लेकिन अनुकूल रॉय ने चौधरी को बोल्ड करने के बाद जोतिन को भी आउट कर ईस्ट जोन की जीत पक्की कर दी। इस जीत के साथ ईस्ट जोन ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका सामना पिछले सत्र की चैंपियन सेंट्रल जोन से होगा। दोनों टीमों के बीच सेमीफाइनल मुकाबला 30 अगस्त से खेला जाएगा।

डीपीएलः साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने नई दिल्ली टाइगर्स को पांच विकेट से हराया

एजेंसी, नई दिल्ली

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सोमवार रात नई दिल्ली टाइगर्स को पांच विकेट से हरा दिया। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने 169 रन के लक्ष्य को 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नई दिल्ली टाइगर्स ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 168 रन बनाए। लक्ष्य थरेजा ने 47 गेंदों पर 62 रन की शानदार पारी खेलकर टीम की पारी को संभाला। आखिरी ओवरों में नमन तिवारी ने दो गेंदों पर 10 रन और रेवान रक्यान ने छह गेंदों पर 17 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज की ओर से अंकित डबास ने चार ओवर में 16 रन देकर दो विकेट लिए। वहीं दिवांश रावत ने दो ओवर में 25 रन खर्च करने के बावजूद चार विकेट झटककर प्रभावी प्रदर्शन किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने अच्छी शुरुआत की। अनमोल शर्मा ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए एक और अर्धशतक लगाया और टीम को मजबूत आधार दिया। वह 16वें ओवर में आउट हुए, लेकिन दूसरे छोर पर एकांश डोबाल ने पारी को संभाले रखा। इसके बाद अंकित ने 18वें ओवर में पार्थ की गेंदों पर लगातार तीन छक्के लगाकर मुकाबले का रुख पूरी तरह साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के पक्ष में कर दिया। वह पांच गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए।

ओडिशा टी20 लीग 18 सितंबर से, 27 को बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल

एजेंसी, कटक । ओडिशा टी20 लीग 2026 का आयोजन 18 से 27 सितंबर तक कटक के ऐतिहासिक बाराबती स्टेडियम में किया जाएगा। टूर्नामेंट में राज्य के युवा और प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को अपनी क्षमता दिखाने का महत्वपूर्ण मौका मिलेगा। इस सत्र में कटक, भुवनेश्वर, केंदुझर, पुरी, राउरकेला और संबलपुर की टीमें हिस्सा लेंगी। अलग-अलग जिलों के खिलाड़ियों के एक साथ आने से लीग में क्षेत्रीय क्रिकेट को बढ़ावा मिलने के साथ युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा का अनुभव भी मिलेगा। ओडिशा क्रिकेट संघ के सचिव संजय बेहरा ने कहा कि 18 सितंबर से लीग के शुरू होने को लेकर संघ उत्साहित है। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के दौरान बाराबती स्टेडियम में रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा। बेहरा ने कहा कि ओडिशा टी20 लीग राज्य के क्रिकेटरों के लिए महत्वपूर्ण मंच है। इससे खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने, अनुभव हासिल करने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट कई खिलाड़ियों को अपने करियर में अगला कदम बढ़ाने में मदद करेगा। लीग के जरिए क्षेत्रीय प्रतिभा, युवा खिलाड़ियों और प्रतिस्पर्धी टी20 क्रिकेट को एक मंच मिलने की उम्मीद है।

आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभात जयसूर्या को फटकार

एजेंसी, कोलंबो

भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज प्रभात जयसूर्या को आधिकारिक फटकार लगाई गई है। इसके साथ ही उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है। जयसूर्या को आईसीसी आचार संहिता के लेवल-1 के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। यह नियम अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण, कपड़े, मैदान से जुड़े उपकरण या अन्य सुविधाओं के अनुचित इस्तेमाल अथवा नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। यह घटना दूसरे दिन (सोमवार) की आखिरी गेंद पर जयसूर्या के आउट होने के बाद हुई। पवेलियन लौटते समय उन्होंने अपने बल्ले से मैदान की सीमा पर लगे बोर्ड को मारा था। जयसूर्या ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और आईसीसी के एलीट पैनल के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित सजा को भी स्वीकार कर लिया। इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। मैदानी अंपायर अहसान रजा और शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, तीसरे अंपायर रॉड टकर तथा चौथे अंपायर प्रगीथ रंबुकवेला ने जयसूर्या के खिलाफ आरोप लगाए थे। पिछले 24 महीनों में जयसूर्या का यह पहला अपराध है। लेवल-1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार, जबकि अधिकतम सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक है।

बिजनेस

सुमैक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ लॉन्च, पहले घंटे में ही हुआ फुली सब्सक्राइब

एजेंसी, नई दिल्ली

ऑटो रिफिनिश मार्केट के लिए ऑटोमोटिव ऑरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सुमैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का 53.40 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 28 अगस्त तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 31 अगस्त को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि एक सितंबर को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर दो सितंबर को एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। लॉन्चिंग के बाद जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने के कारण पहले घंटे में ही ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया था। दोपहर 2:45 बजे तक इस आईपीओ को 2.10 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका था। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 95 रुपये से लेकर 101 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1,200 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 2,400 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,42,400 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 52,87,200 शेयर जारी हो रहे हैं। इनमें लगभग 44 करोड़ रुपये के लगभग 42,91,200 नए शेयर बेचे जा रहे हैं, जबकि लगभग 10 करोड़ रुपये के 9,96,000 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये जारी हो रहे हैं। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 49.90 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 35.04 प्रतिशत हिस्सा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 15.06 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्से में ही मार्केट मेकर के लिए रिजर्व 5.04 प्रतिशत हिस्सा शामिल रखा गया है। इस इश्यू के लिए जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मार्केट मेकर हैं। सुमैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 7.43 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 9.98 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 12.76 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 131.54 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 147.18 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 148.34 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज के बोझ में भी बढ़ोतरी हुई।

सर्राफा बाजार में महंगा हुआ सोना, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

एजेंसी, नई दिल्ली । सर्राफा बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना आज 820 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 900 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है।

कीमत में हुए इस बदलाव के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,63,980 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,64,130 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,50,310 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,50,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज भी 2,59,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,64,130 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,50,460 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला अन्नू प्रोजेक्ट्स का आईपीओ, 2 सितंबर को हो सकती है लिस्टिंग

एजेंसी, नई दिल्ली

टेलीकॉम, सीवरेज और गैस पाइपलाइन जैसे क्षेत्रों में ओवरहेड और अंडरग्राउंड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सेवाएं देने वाली कंपनी अन्नू प्रोजेक्ट्स का 175.06 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 28 अगस्त तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 31 अगस्त को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 01 सितंबर को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 02 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। लॉन्चिंग के बाद दोपहर 2:45 बजे तक इस आईपीओ को 18 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला था।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 94 रुपये से लेकर 99 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 151 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम एक लॉट यानी 151 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 14,949 रुपये का निवेश करना होगा। इसी तरह रिटेल इनवेस्टर 1,94,337 रुपये के निवेश से अधिकतम 13 लॉट में 1,963 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं।

इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 1,76,83,000 नए शेयर जारी किए जा रहे हैं। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 10 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 50 प्रतिशत हिस्सा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 40 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इस इश्यू के लिए मेफकॉम कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। अन्नू प्रोजेक्ट्स की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत बनी रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 17.39 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 21.10 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध लाभ उछल कर 33.03 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 155.42 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 182.35 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 244.59 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ता गया। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी पर 19.69 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 22.27 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस वित्त वर्ष के दौरान कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ छलांग लगा कर 52.54 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

वाणिज्य मंत्री गोयल ने जापान से अधिक संस्थागत पूंजी निवेश का किया आह्वान

एजेंसी, नई दिल्ली/टोक्यो

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को जापान के प्रमुख वित्तीय एवं निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह एवं निवेश साझेदारी मजबूत करने और भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की। गोयल ने एक्स पर जारी पोस्ट में लिखा, टोक्यो में दूसरे दिन की शुरुआत प्रमुख विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के प्रतिनिधियों के साथ नाश्ते पर गोलमेज बैठक से हुई। इस दौरान भारत में निवेश के बदलते माहौल, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार में आसानी) में हुई प्रगति और अलग-अलग सेक्टर में उभर रहे व्यापक अवसरों पर चर्चा की गई। साथ ही, ग्लोबल निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने और साझा विकास के लिए मज़बूत व लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप बनाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। बैठक में मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप (एमयूएफजी), डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान (डीबीजे), मिज़ुहो, मॉर्गन स्टेनली, नोमुरा और निप्पॉन लाइफ के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। गोयल ने बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया।

ईएसडीएस सॉफ्टवेयर का आईपीओ 28 अगस्त को खुलेगा, प्राइस बैंड 408-429 रुपये प्रति शेयर

एजेंसी, मुंबई । ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 28 अगस्त को खुलेगा। इसमें निवेश के लिए निवेशक एक सितंबर 2026 तक बोली लगा सकते हैं। इसके लिए मूल्य दायरा 408- 429 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने मंगलवार को यहां आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड का आईपीओ 28 अगस्त को खुलेगा और एक सितंबर, 2026 को बंद होगा। इसमें निवेश के लिए एंकर निवेशक 27 अगस्त को बोली लगा सकते हैं। कंपनी ने इसके लिए मूल्य का दायरा 408-429 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड ने बताया कि उसका आईपीओ पूरी तरह नए शेयर के निर्गम पर आधारित है। इसमें बिक्री पेशकश (ओएफएस) का कोई घटक शामिल नहीं है। कंपनी की योजना इस इश्यू से 720 करोड़ रुपये जुटाने की है। कंपनी ने सार्वजनिक घोषणा में कहा कि एक रुपये की फेस वैल्यू वाले इस आईपीओ के लिए निवेशक न्यूनतम 34 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 34 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं।

सरकार सभी पायलटों के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट पर कर रही विचार : राममोहन नायडू

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि सरकार सभी पायलटों के लिए हर साल रैंडम ड्रग टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। यह कदम एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली उड़ान की जांच के बीच उठाया गया है, जिसमें अचानक 300 फुट की ऊंचाई कम होने से 24 लोग घायल हो गए थे। नायडू ने दिल्ली में फेडरल एक्सप्रेस कॉर्पोरेशन (फ़ेडेक्स) के इंटीग्रेटेड एयर कार्गो हब के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। नायडू ने कहा कि यह प्रस्ताव एयर इंडिया के दो पायलटों के उड़ान के बाद शुरुआती ड्रग टेस्ट में "नॉन-नेगेटिव" पाए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। इसके बाद एयर इंडिया ने अपने सभी पायलटों की जांच शुरू कर दी है। नायडू ने बताया कि एयर इंडिया के अलावा दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी टेस्ट करा रही हैं। उन्होंने अपने संबोधन में फुकेत-दिल्ली फ़्लाइट से जुड़ी "गंभीर घटना" का ज़िक्र किया और कहा कि विमान दुर्घटना जांच बोर्ड इस मामले की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), स्टेकहोल्डर्स से इस बारे में सलाह-मशविरा कर रहा है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आरती कुमारी द्वारा अभिषेक प्रिंटिंग प्रेस, नया टोला, काजीपुर, पटना- 800004, से मुद्रित एवं मुसल्लहपुर हाट, रामपुर लेन, पटना 800006 से प्रकाशित। संपादक- अविनाश। संपादकीय कार्यालय : 8 वां तल्ला, रश्मि कॉम्प्लेक्स, पीएनटी कॉलोनी, किदवईपुरी, पटना- 800001, RNI: BIHHIN\2019/77032, फोनः 0612-2524441, 2951617, 9472072441, 9472244606, समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेवार।